

संपादक

अभिजीत कुमार, 9431006107

समाचार संपादक

अखिलेश कुमार, 9431089053

सहायक संपादक

मुकेश कुमार सिंह / कोमल सुल्तानिया

राजनीतिक संपादक

प्रो. नीरज कुमार सिंह, 9431049337

संपादकीय सलाहकार

राजीव कुमार सिंह 9431210181

कॉन्सेप्ट एडिटर

अनूप कुमार शर्मा, 7004821433

राजनीतिक ब्यूरो

अमरेन्द्र शर्मा 9899260011

प्रभाकर कुमार राय

प्रबंधक

अविनाश कुमार 8287266244

विधि सलाहकार

वीणा कुमारी जयसवाल, पटना हाई कोर्ट
बिहार ब्यूरो

अनूप नारायण सिंह 9546224277

क्राइम ब्यूरो

एसएन श्याम

मुख्य संवाददाता

सोनू सिंह, 9431006189

आशीष कुमार

जिला ब्यूरो

बेगूसराय : विरेश कुमार सिंह, 9430415316

अमित सिंह, 9430595995

भागलपुर प्रमंडल : राजेश पंजिकार,
(ब्यूरो चौफ), 9334114515

समस्तीपुर : राजेश कुमार

चांदन : अमोद कुमार दूबे : 8578934993

मुंगेर : सिद्धांत

कटोरिया : दीपक चौधरी, विशेष संवाददाता
9973077043

सुईया : चन्द्रशेखर मिश्र (संवाददाता)

बिहार-झारखण्ड : अभिनव कुमार 7903292877

दिल्ली : नवल वत्स, 9818901841

स्वाति, रंजीत कुमार

ग्रेटर नोएडा : गौरीशंकर, 8920215318

प्रधान कार्यालय

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर,
काली मंदिर रोड नं.- 7, पटना - 800 020 (बिहार)

मो.- 9431006107, 9939815347

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक : अभिजीत कुमार

गिरिराज सदन, हनुमान नगर, संजय गांधी नगर, काली
मंदिर रोड नं.- 7 पटना - 800 020 (बिहार) से
प्रकाशित व एस.एम. ऑफसेट पंडुईकोठी लंगर ठोली,
डीएन दास लेन, पटना-800 004, से मुद्रित।पत्रिका में प्रकाशित किसी भी रचना के विवाद के लिए
लेखक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके लिए संपादक से
सहमति जरूरी नहीं। पत्रिका से संबंधित सभी विवादों
का निबटारा पटना उच्च न्यायालय से होगा।

संरक्षक



डॉ. संजय मयूरक्षी

राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी
माजपा

जय जयराम सिंह

JJRS CONSTRUCTION
PVT. LTD.

चर्चित बिहार

वर्ष : 8, अंक : 6, फरवरी 2021, मूल्य : 25/- राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका



10

बिहार के शिक्षा विभाग में नहीं मिल रहा है 700 करोड़ रुपए...



पहली बार किसी प्रधानमंत्री... 21

संस्थान के संस्थापक-निदेशक ... 17



बुजुर्गों का झ्याल रखना हमारा ... 31

वृद्धजनों विधवाओं एवं दिव्यांग... 25



ज्याय तंत्र की मुखीष्टते

राष्ट्रीय औसत के मुताबिक हाईकोर्टों में जजों के 38 फीसदी पद खाली पड़े हैं। पुलिस की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। एक लाख की आबादी पर 156 पुलिसकर्मी का अनुपात बैठता है। जनवरी 2020 की हालत रिपोर्ट में यह बताई गई कि राष्ट्रीय स्तर पर हर तीन जरूरी पुलिसकर्मियों में से एक का पद खाली था। यह तो हुई संख्या की बात। पिछले दिनों आई इंडियन जस्टिस रिपोर्ट हमें मौजूदा विधि व्यवस्था से जुड़े उन बुनियादी मुद्दों से रुबरु करती है जो आम तौर पर अनदेखे ही रह जाते हैं। देश की न्याय प्रक्रिया की गड़बड़ियों और इसके नतीजों के उदाहरण हमें मिलते रहते हैं। कभी अदालतों के असंगत फैसले के रूप में तो कभी सही फैसला आने में हुए अत्यधिक विलंब के रूप में, कभी पुलिस ज्यादतियों के रूप में तो कभी जेल प्रशासन की लापरवाही के रूप में। इन सबके मूल कारणों पर बातचीत कम होती है। देश में अपराध नियंत्रण और दंड विधान से जुड़ी पूरी मशीनरी किस हाल में है और किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, इस पर नियमित सार्वजनिक चर्चा संभवतः इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा ध्यान आम तौर पर तात्कालिक महत्व की चौंकाने वाली घटनाएं ही खींचती हैं, और यह सवाल किसी तात्कालिक घटना से नहीं जुड़ा है। इसी कमी को पूरा करते हुए इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 बताती है कि कैसे हमारा यह तंत्र अपने ही बोझ से चरमरा रहा है। न्यायपालिका में लंबित मामलों की विशाल संख्या की तो बात ही छोड़िए, रिपोर्ट के मुताबिक जनरल केस विलयरेस रेट भी ऊपरी और निचली अदालतों में गिरता जा रहा है। और यह स्वाभाविक भी है। सुनवाई तो तब होगी जजों की संख्या पर्याप्त हो। लॉ कमिशन ने 1987 में ही अपनी 120वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश में 20,000 की आबादी पर एक जज का अनुपात होना चाहिए। हकीकत यह है कि आज भी 50,000 की आबादी पर एक जज का अनुपात बैठता है। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक हाईकोर्टों में जजों के 38 फीसदी पद खाली पड़े हैं। पुलिस की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। एक लाख की आबादी पर 156 पुलिसकर्मी का अनुपात बैठता है। जनवरी 2020 की हालत रिपोर्ट में यह बताई गई कि राष्ट्रीय स्तर पर हर तीन जरूरी पुलिसकर्मियों में से एक का पद खाली था। यह तो हुई संख्या की बात। गुणवत्ता पर चर्चा करें तो उसकी एक अहम कसौटी डायवर्सिटी को माना जाता है। इस लिहाज से महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मामला बहुत ही चिंताजनक है। पुलिस में महिलाओं की मौजूदगी का राष्ट्रीय औसत 10 फीसदी है। सिर्फ आठ राज्य ऐसे हैं जहां पुलिस बलों में महिलाओं का अनुपात इससे बेहतर है। अदालतों में भी हर स्तर पर महिलाओं की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। बिहार, उत्तराखण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों के हाईकोर्टों में महिलाओं का औसत शून्य है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में पुलिस और अदालतों से महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की सीमित अपेक्षा ही की जा सकती है। काम के बढ़ते बोझ और काम निपटाने वाले हाथों की लगातार कमी के बीच न्याय तंत्र के लिए ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं रह पाती। ऐसे में अगर जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से कहीं अधिक बनी हुई है और उनमें 70 फीसदी कैदी विचाराधीन हैं, जिनके बारे में यह भी पता नहीं है कि वे दोषी हैं या बेकसूर, तो आश्र्य कैसा!

अभिजीत कुमार
संपादक

9431006107

cbhindi.news@gmail.com

बजट 2021-22

कुछ सत्ता, कुछ महंगा



कोमल सुल्तानिया



वैश्विक महामारी के दौरान इस साल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को संसद में 2021-22 का बजट पेश किया.. इस बार बहिखाते के बजाय मेड इन इंडिया टैब से पढ़कर पहली बार पेपरलेस बजट यानी डिजिटल बजट पेश किया।

इस बजट से सभी वर्गों से लेकर स्वास्थ्य और ऑटो क्षेत्र तक, हर किसी को इस बजट से काफी उमीदें थीं। इस बजट में लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। हर बार की तरह इस बार भी बजट के बाद कुछ चीजें महंगी हुई और कुछ चीजें सस्ती हुई। आईए जानते हैं इस बजट में किसको वित्त मंत्री के पिटारे से सौगात मिली और कौन निराश हुआ। कौन सी चीजें हुई सस्ती और किस सामान की खरीदारी पर ढीली करनी होगी जेब। आपकी रोजमर्ज के जीवन पर इसका

क्या प्रभाव पड़ेगा। किसने सराहा, किसे नहीं आया पसंद, बजट पर किसने क्या कहा? बजट 2021 से किसी को नाराजगी है तो किसी ने तारीफ भी की है। इस बीच शेयर बाजार तो बजट के बाद झूम रहा है। वित्त मंत्री ने किसको दिया झटका और किसको मिली सौगात?

सड़कों के नेटवर्क से सत्ता की चाह लेकर इस बजट में उत्तरी वित्त मंत्री ने ऐसा 'रोडमैप' तैयार किया, जो चुनावी राज्यों से होकर ही निकला। बजट में पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु और असम से लेकर केरल तक का रास्ता तय करने के लिए सुगम 'हाइवेज' को अरबों रुपयों की सौगात दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की छह लोगों की टीम ने खास परिस्थितियों में बजट तैयार किया। इस बार टीम में दो नए चेहरे हैं।

कृष्णमूर्ति सुब्रह्मण्यन दिसंबर 2018 में मुख्य अर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे।

तरुण बजाज 1988 हरियाणा बैच के आईएएस

अधिकारी तरुण बजाज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

देवाशीष पांडा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं। टीवी सोमनाथन व्यव विभाग के सचिव हैं।

तुहीन कांत निवेश व सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव हैं। इस बार के बजट में उनके कार्यों पर भी नजर रहेगी क्योंकि एंड्रॉनिक फिलहाल विनिवेश से राजस्व जुटाने पर जोर है।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में पौने दो लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में करीब 35 हजार करोड़ रुपये कम है। इनमें रेल, मेट्रो, सड़क आदि के लिए बड़े-बड़े पैकेज दिए गए। हालांकि, बजट में उन राज्यों पर भी फोकस किया गया, जहां भाजपा की सरकार नहीं है।



कोविड 19 के कारण झटका झेल रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए बजट से सभी को खास उमीदें थीं। महामारी के बीच बजट में संकट मोचक बजट स्वास्थ्य और विनिवेश के लिए बंपर एलान किया गया। वहीं इस बजट में नौकरीपेशा के लिए कोई घोषणा नहीं की गई।

आम बजट 2021-22 में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सौगत दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले वर्ष तक देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये के बजट का एलान किया, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इजाफा किया गया वहीं, 2013-14 से की गेहूं-धान खरीदी की तुलना की गई।

जानिए इस बार किसानों के लिए क्या है खास

- किसानों को गेहूं के लिए 75060 करोड़ रुपए आवंटित।
- 2021 में धान खरीदी के लिए 1 लाख 72 हजार 752 करोड़ रुपए का आवंटन।
- 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
- ग्रामीण इन्फ्रा फंड के लिए 40 हजार करोड़ की घोषणा।
- ए-ठें के लिए 1 हजार नई मंडियां, फॉर्म क्रेडिट लक्ष्य।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- किसानों के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड का एलान।
- एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी, देश में 5 बड़े फिलिंग हब बनेंगे। ये कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआधाट जैसे शहरों में होंगे।
- बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1 हजार करोड़।
- तमिलनाडु में मल्टीपर्ज सी-विड पार्क बनेगा।

बजट 2021 से केंद्र सरकार किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही। ज्यादातर किसानों ने बजट

2021 में किसानों के लिए की गई घोषणाओं को नाकाफी बताया और कहा कि सरकार उन मूल मुद्दों को छूने में नाकाम रही जिन मुद्दों को लेकर पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है।

बजट 2021 को देखकर लगता है कि कोरोना ने पूरे देश के बजट को हेल्प बजट में तब्दील करके रख दिया। सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए स्वास्थ्य बजट में 137 प्रतिशत की बढ़ातरी कर दी। पिछले साल के 92 हजार करोड़ रुपये के स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर इस साल दो लाख 32 हजार 846 करोड़ कर दिया गया।

इस कोरोना काल में पहले से ही ये उम्मीद की जा रही थी कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट से बहुत कुछ मिलेगा और ऐसा हुआ भी। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ातरी की गई है और साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का तोहफा दिया।

इस बजट से नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। जबकि करदाता यह उम्मीद कर रहे थे कि सीतारमण कोई सौगत देंगी। ऑटोमोबाइल और कारोबार क्षेत्र के साथ स्टील उत्पादों पर सीमा शुल्क में सरकार द्वारा 7.5 फीसदी की कटौती करने से ऑटो डृप्टर (ओरिजिनल इक्यूप्रैंट मैन्यूफैक्चरर्स) (ओईएम) को फायदा होगा।

बैंक और रेलवे क्षेत्र में बैंकों को ठढ़अ से उबारने के लिए 'बैंड बैंक' बनाने का फैसला लिया गया। इस बैंड बैंक को डेवलपमेंट फाइंनेंस इंस्टिट्यूशन के नाम से जाना जाएगा। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकों को ढूबे कर्ज से बाहर निकालना है। बजट 2021 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए 15,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है तो वहीं रेलवे को 1.10 लाख करोड़ तो सड़कों पर खर्च होंगे 3 लाख करोड़ किया गया।

देश में रेलवे जगत के कायाकल्प के लिए एक लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की राष्ट्रीय रेल योजना-2030 पेश की है। इसके तहत जहां दिसंबर 2023 तक बड़ी लाइनों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा वहीं विभिन्न शहरों के बीच मेट्रो, मेट्रो लाइन परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

बजट में भारतीय रेलवे से जुड़े कई महत्वपूर्ण

एलान किए गए हैं। रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एनएचएआई के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे में लाया जाएगा।

बता दें कि, इस बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में 5 फीसदी की भारी कटौती की घोषणा की गई। मालूम हो कि वर्तमान में सोने पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है।

खेल, बीमा, राज्य और रक्षा

कोरोना महामारी का असर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए खेल बजट पर भी देखने को मिला। वित्त मंत्री द्वारा खेलों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2596.14 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल की तुलना में इस बार 230.78 करोड़ रुपये की कटौती की गई।

बीमा क्षेत्र पर सरकार का बड़ा एलान लिया गया.. ऋणकों को बढ़ाकर 74 फीसदी तक क्या गया.. पहले यहां पर सिर्फ 49 फीसदी तक की ही इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का एलान किया गया है। इसमें कई स्टार्ट अप कंपनियों के लिए एलान किया। इसके तहत करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरूआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी।

बंगाल सहित इन चुनावी राज्यों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बंपर एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के बीच देश का पहला पेपरलेस बजट हुआ जिसमें इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए करीब 4.78 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

रियल स्टेट, शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र

आम बजट में सस्ते मकानों की खरीदी के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

उच्च शिक्षा आयोग, लेह को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तोहफा, 15 हजार आदर्श स्कूल बनेंगे.. इसके साथ

ही देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे।

मोबाइल से लेकर चार्जर और सोलर लैप तक होंगे महंगे

आम बजट 2021 में सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों और चार्जर के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से मोबाइल फोन के साथ चार्जर, केबल जैसे कई गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट महंगे होंगे।

बजट भाषण में सरकार ने हर वर्ग के श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज कोड लागू करने की घोषणा की है। यह प्रवासी और असंगठित श्रमिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। अनुमान है कि इससे देश के 50 करोड़ के करीब श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा।

आम बजट-2021 से ज्यादातर लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लेकर की गई घोषणा भी उन्हें खुश नहीं कर सकेगी। बजट प्रस्ताव में उन बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने की छूट दी गई है, जिनकी आय सिर्फ पेंशन से या बैंकों में सावधि जमा यानी एफडी से होती है।

75 साल से ज्यादा उम्र वालों को राहत का मतलब क्या?

सरकार ने एलान किया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। हम आपको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है? दरअसल, अधिकतर लोग मान रहे हैं कि अब 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार के इस नियम के द्वारे में 75 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ वही लोग आएंगे, जिनकी इनकम का आधार पेंशन या एफडी समेत अन्य माध्यमों से मिलने वाला ब्याज है। ऐसे लोगों को सिर्फ आईटीआर नहीं भरना होगा। पहले की तरह बैंक में ही उनका टीडीएस कट जाएगा। अगर आय का माध्यम कुछ और है, मसलन कारोबार आदि है तो आईटीआर भी फ़ाइल करना होगा।

केंद्रीय बजट में इस बार आम करदाता को कोई राहत नहीं दी गई है। उन्हें पिछली बार जारी हुए टैक्स स्लैब के आधार पर ही कर चुकाना होगा। बता दें कि इस वक्त ढाई लाख रुपये की तक आय इनकम टैक्स के द्वारे से बाहर है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी और साढ़े सात लाख से 10 लाख रुपये पर 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी कर का प्रावधान है।

टैक्स रिअसेसमेंट में राहत

अब तक टैक्स रिअसेसमेंट छह साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। ऐसे मामलों के चक्कर में आयकरदाता को छह से 10 साल तक सभी कागजात संभालकर रखने पड़ते थे। अब टैक्स रिअसेसमेंट घटाकर 3 साल कर दिया गया

है। अगर गंभीर मामलों में एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। हालांकि, उसके लिए कमिशनर से मंजूरी लेनी होगी।

अलग से डाटा जुटाने से भी राहत

नौकरीपेशा लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। दरअसल, अब तक आईटीआर भरते वक्त नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16ए के अलावा एफडी समेत अन्य माध्यमों में निवेश से मिलने वाले ब्याज की डिटेल अलग से देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। फॉर्म 16ए में इनकी जानकारी पहले से होगी, जिससे आयकरदाता को अलग से डाटा नहीं जुटाना पड़ेगा।

डिविडेंट पेमेंट या नहीं लगेगा टीडीएस

बता दें कि अब तक होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपये की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपये की एकस्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।

अलग डाटा जुटाने से भी राहत

नौकरीपेशा लोगों को सरकार ने थोड़ी राहत दी है। दरअसल, अब तक आईटीआर भरते वक्त नौकरीपेशा लोगों को फॉर्म 16ए के अलावा एफडी समेत अन्य माध्यमों में निवेश से मिलने वाले ब्याज की डिटेल अलग से देनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा। फॉर्म 16ए में इनकी जानकारी पहले से होगी, जिससे आयकरदाता को अलग से डाटा नहीं जुटाना पड़ेगा।

एनआरआई को मिली छूट

केंद्रीय बजट में विदेश में रहने वाले भारतीयों यानी एनआरआई को राहत दी गई है। दरअसल, उन्हें डबल टैक्स से जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने उन्हें राहत देने का एलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनआरआई को टैक्स भरने में काफी दिक्कत होती थी। ऐसे में उन्हें डबल टैक्स से राहत दी जा रही है।

स्टार्टअप में टैक्स की छूट बढ़ी

स्टार्टअप के दौरान टैक्स जमा करने को लेकर सरकार ने राहत दे रखी है। अब सरकार ने इसकी समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है।

सरकार ने किए ये बड़े एलान

करदाताओं को राहत देने के मकसद से वित्त मंत्री ने फेसलेस समिति बनाने का एलान किया। 50 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य इनकम वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग इस समिति के पास जा सकते हैं। इसके लिए सुनवाई वीडियो कॉर्नर्सिंग के माध्यम से होगी। सरकार ने बताया कि टैक्स संबंधित मामले सुलझाने के लिए बैनी विवाद से विश्वास समिति का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अब छोटे कारोबारियों को भी जोड़ा जाएगा।

कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कम

सरकार ने बताया कि देश में आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी है। वहीं, भारत में कॉर्पोरेट टैक्स पूरी दुनिया में सबसे कम है।

संसद में केंद्रीय बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को

बल देने की जो कोशिशें हुई हैं, उनका जमीनी असर न केवल योजनाओं और बजट के क्रियान्वयन, बल्कि सरकार के भावी निर्णयों पर निर्भर करेगा। जो प्रयास मूलभूत ढांचे में निवेश या उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। बजट से भी जाहिर है, सरकार लोगों को मिल रही प्रत्यक्ष आर्थिक मदद के अभी तक के प्रयासों से संतुष्ट है और इसका बखान बजट में बखूबी भुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, तो कोई आश्र्य नहीं। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। अब आम बजट में सरकार ने 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करना कितना जरूरी है, यह हमने कोरोना के समय अच्छी तरह समझ लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी जारी रहेगा। बहरहाल, जब सरकारी खजाना दबाव में है, तब आयकरदाताओं को वैसे भी राहत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। 135 करोड़ लोगों के देश में करीब छह करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि करीब तीन करोड़ लोग ही आयकर चुकाते हैं। मुश्किल समय में सरकार आयकर का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती थी।

यह आयकर बढ़ाने का समय नहीं है, यह अन्य करों को बढ़ाने का भी समय नहीं है। ऐसे में, सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का अधिभार लगाया है, जबकि डीजल पर 4 रुपये। इससे पेट्रोल, डीजल की कीमतों को तीन अंकों में जाने और बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र बढ़ेगी। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन इसका लाभ तभी है, जब देशी कंपनियां स्वयं पर्याप्त उपकरण बनाने लगें, वरना आज के समय में मोबाइल फोन को महंगा करने की दिशा में कोई भी निर्णय अनुकूल नहीं है। जब भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करते हैं, तब आयात बढ़ाने के छोटे-मोटे उपाय भले किसी निजी कंपनी या उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हों, लेकिन हमें व्यापकता में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए।

सस्ते घर की सुविधा, ढूबते कर्ज का प्रबंधन, सरकारी बैंकों को पूँजी देने का प्रस्ताव, उज्ज्वला योजना का विस्तार, रेल व बस सेवा विस्तार, किसानों को फसल लागत से डेढ़ गुना मूल्य देने का इरादा इत्यादि अनेक प्रशंसनीय कार्रिशें हैं। हम समझ सकते हैं, विनिवेश से भी सरकार पैसे जुटाना चाहती है, यह पुराना एजेंडा है।

पिछले बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का अनुमान था और इस बार 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का इरादा है, लेकिन यह एक ऐसा मोर्चा है, जहां सरकार को राजनीति और अनेक अड्डों का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में सरकार के खर्च का बढ़ना तय है, अतः सरकार को इस दौर में वित्तीय घटे की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। यह ज्यादा व सुनियोजित खर्च के साथ अर्थव्यवस्था में मांग और विकास की गति बढ़ाने का समय है।

सरकार बनने के 85 दिनों के बाद हुआ बिहार मन्त्रिमण्डल का विस्तार

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह का खास विशेषण

बिहार में नीतीश सरकार का गठन 16 नवंबर, 2020 को हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत 15 विधायकों ने शपथ ली थी। लेकिन विभिन्न आरोपों से घिरे, मेवालाल चौधरी को ढाई घण्टे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद बिहार मन्त्रिमण्डल में कुल 13 चेहरे बचे थे। 13 में बीजेपी के 7, जेडीयू के 4, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और विकासशील इंसान पार्टी के 1 मंत्री शामिल थे। बिहार में 44 विभाग हैं और 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मतलब, 23 मंत्रियों की जगह खाली थी। मंगलवार को सरकार गठन के 85 दिनों के बाद बिहार मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया गया। भाजपा कोटे से 9 और जदयू कोटे से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि इस बार बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 74 सीटें हैं। वहीं, जेडीयू को 43, हम को 4 और बीआईपी को भी 4 सीटें मिली हैं। ऐसे में अगर, पिछले एनडीए सरकार के आधार पर मंत्रियों की भारीदारी देखें, तो जेडीयू के सीएम समेत 22 विधायक मंत्री थे। बीजेपी के डिटी सीएम सहित 13 विधायक मंत्री थे। पिछली बार जेडीयू के विधायकों की संख्या 71 थी जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या 54 थी। इस बार बीजेपी के 74 विधायक हैं और जेडीयू के 43 विधायक हैं।

सरकार बनने के 85 दिनों के बाद हुआ बिहार मन्त्रिमण्डल का विस्तार

लम्बी रस्साकसी और खींचतान के बाद, मंगलवार को नीतीश सरकार के बहुप्रतीक्षित मन्त्रिमण्डल का विस्तार हो गया। विस्तार के दौरान, राजभवन में मंगलवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें सबसे पहले शपथ दिलाई। पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कुल 17 नए मंत्रियों जिसमें भाजपा से नौ और जदयू से आठ मंत्री शामिल हैं, को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। नीतीश मन्त्रिमण्डल के इस विस्तार में भाजपा से सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रमोद कुमार, सप्राट चौधरी, नीरज कुमार सिंह "बबलू", सुभाष सिंह, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, डॉक्टर आलोक रंजन और जनक राम तथा जदयू से श्रवण कुमार, मदन सहनी, संजय झा, लेसी सिंह, सुमित कुमार सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज और जमा खान ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें, एक बार फिर से शाहनवाज हुसैन की चुनावी राजनीति में वापसी हो गई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद

■ कोसी क्षेत्र से कुल पाँच मंत्री हुए हैं, जो है एक रिकॉर्ड

■ मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह "ज्ञानू" ने खोला मोर्चा

■ मन्त्रिमण्डल विस्तार में सबसे अधिक चर्चा में हैं शाहनवाज हुसैन और नीरज कुमार सिंह "बबलू"



यह पहला मौका है जब वह सक्रिय राजनीति में वापस लौटे हैं। वर्ष 2014 में वह भागलपुर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे जबकि 2019 में, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वह नागरिक उद्घाटन मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार की राजनीति में शाहनवाज हुसैन की एंट्री, भाजपा की दूरदृष्टि का परिचायक है। शाहनवाज के जरिये भाजपा, बिहार में मुस्लिमों को रिजाना चाह रही है। भविष्य में शाहनवाज हुसैन को भाजपा बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बना सकती है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को जीत मिली थी। एनडीए में शामिल भाजपा को बिहार में 74 सीट, जदयू को 43 सीट और मुकेश सहनी की बीआईपी, जीतनराम मांझी की हम को चार-चार सीटों पर जीत मिली थी। गौरतलब है कि बिहार में बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत थी, वहीं एनडीए ने बहुमत से तीन सीट ज्यादा, यानि 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

मन्त्रिमण्डल विस्तार के साथ ही सीएम नीतीश के नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। भाजपा कोटे से सबसे पहले शपथ लेने वाले शाहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग मिला है।



भाजपा कोटे से बने मंत्रियों के विभाग की बात करें, तो

शाहनवाज हुसैन को उद्योग, सुधार सिंह को सहकारिता, पितिन नवीन को पथ निर्माण नारायण प्रसाद को पर्यटन विभाग नीरज कुमार सिंह "बबलू" को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग विभाग, सप्नाट चौधरी को पंचायती राज विभाग, डॉक्टर आलोक रंजन को कला-संस्कृति एवं युवा विभाग और जनक राम को खान एवं भूततःव विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। जरदू कोटे से बने मंत्रियों में लेसी सिंह को खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सुमित सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,

संजय झा को जलसंसाधन, सूचना और जनसंपर्क सहकारिता विभाग, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग, मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग,

जयंत राज को ग्रामीण कार्य विभाग, जमा खान को अलूपसंख्यक विभाग और

सुनील कुमार को मद्य निषेध उत्पाद विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।

कोसी क्षेत्र से कुल पाँच मंत्री हुए हैं, जो है एक रिकॉर्ड

कोसी क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा और सुपौल तीन जिले हैं। इस बार कोसी के सहरसा और सुपौल जिले से पाँच मंत्री बनाये गए हैं। सरकार गठन के दिन तारकेश्वर प्रसाद और बिंजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया था और मन्त्रिमण्डल विस्तार में सुपौल के रहने वाले शाहनवाज हुसैन, नीरज कुमार सिंह "बबलू" और डॉक्टर आलोक रंजन को मंत्री बनाया गया है। पाँच मंत्री होने से कोसी इलाके के लोगों में बेहद खुशी है। लोग यह उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार सहरसा में ओवर ब्रिज बनेगा, सदर अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा, उद्योग के जाल बिछेंगे, रोजगार का सुजन होगा और कोसी क्षेत्र से पलायन रुकेगा। यानि कोसी में इस बार



विकास की दरिया बहेगी।

मंत्री नहीं बनाए जाने से खफा बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह "ज्ञानू" ने खोला मोर्चा

नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह "ज्ञानू" की नाराजगी खुलकर सामने आई है। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि इस बार के मंत्रिमण्डल में साफ-सुधारी छवि वाले नेताओं को पीछे कर के, दागियों को मंत्री बनाया गया है। भाजपा विधायक ने चेताया है कि इस तरह के विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचेगा। विधायक ज्ञानू ने कहा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है कि इसमें जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। कहीं-कहीं से तीन-तीन मंत्री बनाए गए और कहीं से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। साफ-सुधारी छवि वाले नेताओं को दरकिनार कर के दागियों को मंत्री बनाया गया है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह "ज्ञानू" ने आगे कहा है कि लगता ही नहीं है कि कोई भारी-भरकम चेहरा मंत्रिमण्डल में है। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग जीतकर आए हैं।

लगभग 50 प्रतिशत उच्च जाति के लोग बीजेपी से जीतकर आए हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया जबकि दूसरों को बनाया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या आपको मंत्रिमण्डल में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए तो ये नाराजगी नहीं है। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि मुझे जगह नहीं मिली इसकी कोई चिंता नहीं है। हम मंत्री से अच्छी हैसियत में हैं। मंत्रियों की क्या हैसियत है इस सरकार में, वो सभी को पता है। चिंता यह है कि पार्टी कमजोर हो रही है। कुछ जातिवादी लोग हैं, जो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। भाजपा अब, यादव और बनिया जाति के कंट्रोल में चली गई है। इस तमाम उठापटक के बीच, विरोधी दल के नेता, जमा खान, लेसी सिंह और नीरज कुमार सिंह "बबलू" को लेकर भी कई तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं। जहाँ तक नीरज "बबलू" का सवाल है, तो उन्होंने लगातार पाँच बार विधायक बनकर, राजनीति में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। 2015 के चुनाव में जब नीतीश और लालू की जोड़ी बनी थी, तब कोसी से नीरज "बबलू" ने अकेले कमल खिलाया था।

क्षत्रिय समाज से आने वाले नीरज कुमार सिंह "बबलू" की धमक पूरे कोसी-सीमांचल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में है। इन्हें बाहुबली और दबंग विधायक के रूप में भी देखा जाता है। लक्जरी गाड़ियों के काफिले में चलना इनका शौक है। सर्वसमाज को साथ लेकर चलने वाले इस नेता की काबिलियत, इस बात से परखी जा सकती है कि जिस छातपुर से ये दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, उस विधानसभा में राजपूत मतदाताओं की संख्या महज दो से ढाई हजार है। सदन में इनकी कार्यशैली, क्षेत्र में विकास सहित जनता के अथाह प्रेम और विभिन्न मानदंडों पर खड़ा उत्तरने की बजह से सकारात्मक पत्रकारिता के एशिया के नम्बर वन हाउस फेम इंडिया-एशिया पोस्ट सर्वे में, देश के पचास सर्वश्रेष्ठ विधायकों की श्रेणी में इहें जागह दी गयी है। आगे यह देखना बेहद जरूरी है कि इन नवोदित मंत्रियों के द्वारा, अपने-अपने क्षेत्र का कितना और कैसा विकास किया जाता है।

एमलसी बना कर गुप्तेश्वर पांडेय को मंत्री बनाने के मृद में हैं नीतीश कुमार

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह

कोटे की टक्कर में बायुषिकल, एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले नीतीश कुमार के लिए, इस बार की राजनीतिक पारी बेहद कठिन मानी जा रही है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार पर बिहार भाजपा सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भारी दबाव रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार समझौतावादी और घटने टेक कर राजनीति करने के आदी नहीं रहे हैं। नीतीश अपने किश्म के अक्खड़ और जिद्दी राजनेता माने जाते हैं। इसलिए टिकाऊ सरकार के लिए भाजपा को भी संयम के साथ राजनीति करनी होगी। 14 से 15 करोड़ के बीच की आबादी वाले बिहार में अभी बेहद छोटा मन्त्रिमण्डल है। आगे मन्त्रिमण्डल का विस्तार होना बाकि है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी और जदयू कोटे से अभी कई विधायक मंत्री बनने वाले हैं। इधर जदयू कोटे से महज ढाई घण्टे के लिए शिक्षा मंत्री बनने वाल डॉक्टर मेवालाल चौधरी की वजह से जदयू की भद्र पिट चुकी है। ऐसे में जदयू के भीतरखाने से यह जानकारी मिल रही है कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को एमलसी बनाकर, मंत्री बनाये जाने को लेकर जदयू के भीतर बहस और विमर्श जारी है। गौरतलब है कि पूर्व डीजीपी ने 2009 में भी वीआरएस लेकर राजनीति में आने के लिए समर में कूद पड़े थे। उस समय भी बिहार की सत्ता के सिंहासन पर नीतीश कुमार काबिज थे। लेकिन कुछ कारणों से राजनीति में श्री पांडेय की एंट्री नहीं हो सकी। थक-हार कर गुप्तेश्वर पांडेय ने फिर से नौकरी में वापिस आने की अज्ञां लगाई। बिहार सरकार की मदद से गुप्तेश्वर पांडेय की फिर से सेवा बहाल हो गयी। नीतीश कुमार के साथ-साथ भाजपा के प्रियगांत गुप्तेश्वर पांडेय ने इस दफा, नीतीश कुमार की सहमति पर सेवानिवृति के पाँच महीने पूर्व ही नौकरी से वीआरएस लेकर जदयू ज्वाइन कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से श्री पांडेय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। गुप्तेश्वर पांडेय और उनके चाहने वालों को यह पक्का यकीन था कि जदयू उन्हें बक्सर सीट से अपना उम्मीदवार बनाएगा लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के कड़े विरोध की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला। हांलांकि बीजेपी को इस जिद का खामियाजा बक्सर सीट गंवा कर चुकानी पड़ी। बक्सर से भाजपा के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी को कांग्रेस के संजय तिवारी उर्फ मुना तिवारी ने हराया। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने यह सीट गुप्तेश्वर पांडेय को टिकट नहीं देने की वजह से गंवाई। गुप्तेश्वर पांडेय के चाहने वालों ने परशुराम चतुर्वेदी की आसान जीत को हार में बदल कर रख दिया। हांलांकि इस दौरान गुप्तेश्वर पांडेय ने ना

■ राजनीति में जनसेवा की नई परिभाषा लिखना चाहते हैं गुप्तेश्वर पांडेय

■ डीजीपी के पद से सेवानिवृति के पाँच महीने पहले ही वीआरएस लेकर जदयू की सदस्यता ली है गुप्तेश्वर पांडेय ने

■ वर्ष 2009 में भी राजनीति में एंट्री की कर चके हैं कोशिश



तो प्रेस में कोई राजनीतिक बयान दिए और ना ही फेसबुक, या किसी अन्य मंच से ही कोई बात कही। अभी भी गुसेश्वर पांडेय की तरफ से राजनीतिक खामोशी और सन्नाटा ही है। अपने डीजीपी के कार्यकाल के दौरान, गुसेश्वर पांडेय ने कई कालजीवी कार्य किये हैं। शराबबंदी के ब्रांड एम्बेसेडर बनकर, इसकी सफलता के लिए इन्होंने जनजगरण के जरिये भरीरथ प्रयास किये। खराब पुलिसिंग के लिए कई पुलिस अधिकारी और जवानों को बर्खास्त तक किये। जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध के लिए उन्होंने कई कड़े कदम उठाए। कई घाती केस का अनुसंधान उन्होंने खुद से कर के एक मिशाल कायम की। यह अलग बात है कि गुसेश्वर पांडेय, अपने डीजीपी के कार्यकाल के दौरान पुलिस की घृस्थोरी और शराबबंदी को रोक पाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। दीगर बात है कि पुलिस के 40 जिलों के पुलिस अधिकारियों का ईमानदारी से उन्हें सहयोग नहीं मिल सका। इनका डीजीपी का पूरा कार्यकाल नोटबन्दी की तरह साबित हुआ। इनके कार्यकाल के दौरान, पुलिस अधिकारी भव्यता हुए बिना काम करते रहे। सबसे अहम बात यह है कि बेहद गरीब परिवार से आने वाले गुसेश्वर पांडेय ने बेदांग पुलिसिंग की है और नौकरी के दौरान जहाँ-जहाँ इन्होंने अपनी सेवा दी, वहाँ एक बड़ी लकीर खींचते चले गए। यह समीक्षा का और बेहद सोचनीय विषय है कि अगर गुसेश्वर पांडेय को धन कमाने का लोभ होता तो, डीजीपी रहते हुए वे धन कुबेर बन जाते। सेवानिवृति से पौंछ महीने पहले वे वीआरएस लेने की जगह सिर्फ रुपये बटोरने का काम करते लेकिन गुसेश्वर पांडेय को राजनीति के जरिये जनसेवा का एक नया इतिहास लिखने का नशा चढ़ा हुआ रहा। एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वे राजनीति में कुछ अलग और खास करने के सपने पाल रखे हैं। वर्तमान राजनीति को लोग बेहद हेय दृष्टि से देखने लगे हैं। वे लोगों की सेवा कर के उनके विचार को बदलने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। उप्र के इस पड़ाव पर धन संचय, उनकी सोच में भी नहीं है। वे मन संचय की एक मजबूत पारी खेलना चाहते हैं। वे जदयू के एक मजबूत सिपाही हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें जो भी जिम्मेवारी सौंपेंगे, उसे वे अपनी क्षमता से ज्यादा करेंगे। बेहद सरल, शौम्य, मृदुल स्वभाव और साधारण तौर-तरीके से रहने वाले गुसेश्वर पांडेय हमेशा मुख्य होकर बोलने के आदी रहे हैं। उन्हें मंत्री बनाने की बात चल रही है को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी उन्हें कौन सी जिम्मेवारी दे रही है। लेकिन यह तय है कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिलेगी, उसे वे स्वीकार और अंगीकार करेंगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक गुसेश्वर पांडेय के मंत्री बनाये जाने पर मुख्यमंत्री की आंतरिक रजामंदी है। बस घोषणा और शपथ ग्रहण बांकिं है। हमारी समझ से राजनीति में ऐसे ज्ञान सिक्का सामर्थ्यवान व्यक्ति को, निसन्देह बड़ी जगह मिलनी चाहिए। गुसेश्वर पांडेय सरीखे आईपीएस की नौकरी में कई जिलों में सेवा देने वाले अधिकारी, विकास के नए आयाम गढ़ने में मिल के पथर साबित होंगे। अभी तो, हम सभी को मन्त्रिमण्डल के विस्तार होने का इनजार है लेकिन हम ताल ठोक कर कहते हैं कि गुसेश्वर पांडेय के मंत्री बनने के आसार प्रबल हैं।

नीतीश कैबिनेट के विस्तार का रास्ता हुआ साफ लव-कुश समीकरण के बीच सवर्णों को भी खुश करने की होगी कोशिश

जेडीयू इन दिनों अपनी पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस संगठनात्मक प्रयोग के दौरान, बिहार मन्त्रिमण्डल विस्तार में अनावश्यक हो रही देरी को अब, पूरी तरह से विराम लग गया है। गैरतलब है कि जदयू अपने लव-कुश समीकरण पर ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यास यह लगाया जा रहा है कि गलोपासा चीफ उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कोटे से मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का या तो जेडीयू में विलय कर लेंगे या फिर जीतन राम माझी और मुकेश सहनी की तरह एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी द्वारा अपने मंत्रियों का नाम तय किये जाने के बाद, अब बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार का कांटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी के भीतरखाने से मिल रही जानकारी के मुताबिक, अगले एक दो दिन में, बीजेपी अपने मंत्री बनाए जानेवाले नेताओं के नाम घोषित कर देगी। जेडीयू पहले ही तय कर चुका है कि मंत्री किस-किस को बनाना है। केवल उपेंद्र कुशवाहा से डील फर्इनल होना शैष है। सूत्रों के अनुसार, संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी गलोपासा का विलय जेडीयू में हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अगर सबकुछ ठीक रहा तो, इसी समाह कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वाले अपने नेताओं के नाम बीजेपी तय कर चुकी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के एनडीए में शामिल होने या फिर फिर जेडीयू में विलय होने का इनतजार भर बाकि है। दीगर बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की नीतीश कुमार के साथ



लगातार बैठकें चल रही हैं। बिहार में मन्त्रिमण्डल के विस्तार को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई हाई लेवल बैठक में नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के नए मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार में शाहनवाज हुसैन को कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया जा सकता है। उम्मीद जारी रही है कि शाहनवाज हुसैन को वित्त या पथ निर्माण विभाग दिया जा सकता है। वैसे शाहनवाज हुसैन यह कहते आ रहे हैं कि वे मंत्री पद की रेस में नहीं हैं। लेकिन ऐसे संवाद, राजनीति में बड़े अस्त्र होते हैं। शाहनवाज के अलावा प्रमोद कुमार, प्रमोद चंद्रबंशी, नितिन नवीन, नीतीश मिश्र, राणा रणधीर सिंह, नीरज कुमार सिंह "बबलू", संजय सिंह, संजय सरावगी, संजीव चौरसिया, भागीरथी देवी, कृष्ण कुमार ऋषि, इंजीनियर शैलेंद्र तथा विधान पार्षद स्प्राइट चौधरी के नाम भी पूरी तरह से चर्चा में हैं। इंजीनियर शैलेंद्र अंग क्षेत्र के बिहूर से विधायक हैं, तो नितिन नवीन युवा चेहरा हैं। पूर्व मंत्री समाप्त चौधरी मुगेर के, तो राणा रणधीर चंपारण के रहने वाले हैं। बीजेपी से सुपौल के छातपुर विधायक नीरज कुमार सिंह "बबलू" का मंत्री बनना पहले से ही लगभग तय है। जेडीयू इन दिनों अपने ह्यूलव-कुशलू समीकरण पर ज्यादा फोकस कर रहा है। जदयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा का नाम एक नम्बर पर है। एनडीए की पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा समाज से हैं। बहुजन समाज पार्टी से जेडीयू में आए जमां खान और निर्दलीय विधायक सुमित्र सिंह को भी जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम माझी एवं विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सह भी मंत्री मुकेश सहनी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। संभव है कि हम और बीआइपी से भी एक-एक और मंत्री बनाए जाएं। जदयू की तरफ से मधुबन से जदयू विधायक राणा रणधीर सिंह, कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र पांडेय, गोपालपुर से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, नालंदा से जदयू विधायक श्रवण कुमार, सरायंजन से जदयू विधायक विजय कुमार चौधरी, धमादाहा से जदयू विधायक लेसी सिंह और रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती, मंत्री पद की ना केवल रेस में हैं बल्कि प्रबल दावेदार भी हैं। अब जिन्हें मंत्री बनना और बनाना है, इस धूंध पर से इसी समाह सारे लिहाफ हट जाएंगे। बिहार में पहली बार, इतने लंबे समय तक मन्त्रिमण्डल का विस्तार रुका रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे विकास और अन्य मुद्दों पर खासा असर पर रहा है। नीतीश कुमार, अपने किश्म के राजनेता हैं। उन्हें हमेशा फ्रॉन्टफुट पर खेलने की आदत रही है। वे दबकर और किसी के प्रभाव में आकर राजनीति करने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार सियासत के महीन और माहिर खिलाड़ी हैं। 43 सीटों पर जदयू के सिमटने के बाद भी, वे अपनी बातें मनवा कर रहते हैं। वैसे भी, बिहार में अगर स्थिर सरकार चलानी है तो, बीजेपी को नीतीश कुमार के हट और जिद के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। बीजेपी किसी तरह का भी गेम खेल सकती है लेकिन बिना नीतीश कुमार के वह मौजू समय में, किसी भी सूरत में अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है।

बिहार के शिक्षा विभाग में नहीं मिल रहा है 700 करोड़ रुपये का कोई लेखा-जोखा



■ सिस्टम में कितने छेद हैं, यह उसी की बानगी है

■ महज एक विभाग की काली करतूत से, अन्य विभागों में हो रही हेराफेरी का है बड़ा अंदेशा

मुकेश कुमार सिंह

बिहार में विगत कई वर्षों से बिचौलिया राज कायम है। अधिकारियों से लेकर अर्दली और स्वीपर तक, अपने पद के प्रतिकूल दल्ले बने हुए दिख रहे हैं। घुसपेहोरी और हर तरह के भ्रष्टाचार में बिहार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ताजा मामला बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का सामने आया है जिसमें बड़ा गड़बड़ज़ाला चल रहा है। बिहार के शिक्षा विभाग में, 700 करोड़ रुपये का कोई लेखा-जोखा नहीं मिल रहा है। विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग में करीब 600 करोड़ रुपये अधिकारियों ने खर्च कर दिए लेकिन उसका हिसाब किताब वो नहीं दे पा रहे हैं। विभाग द्वारा बार-बार उपयोगिता प्रमाण की मांग किये जाने के बाद भी, अब तक डीसी बिल जमा नहीं किया गया है। अब जाकर बिहार शिक्षा विभाग की नींद टूटी है और विभाग ने सभी डीईओ को 20 फरवरी तक का मोहल्लत दिया है। अब अगर जिस जिले के डीईओ उपयोगिता प्रमाण पत्र और डीसी बिल जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी

दी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे गए पत्र में एसी-डीसी कोषाग का गठन कर, इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। गैरतरलब है कि वर्ष 2002-03 से लेकर वर्ष 2019-20 तक, खर्च की गई राशि की एसी-डीसी विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। निसन्देह, यह एक वित्तीय मामला है। उपयोगिता एवं एसी डीसी बिल लंबित रहने के कारण जनहित याचिका भी दायर हो चुका है। जाहिर तौर पर, यह एक गंभीर मामला बना हुआ है। बताना लाजिमी है कि इसकी गंभीरता को देखते हुए, बिहार के सभी जिलों में कोषांग गठन कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन किसी जिले से अभी तक कोषांग गठन की कोई सूचना नहीं मिली है, जो काफी खेद जनक और सद्देहास्पद है। बिहार शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को चेतावनी दी है कि 3 दिनों के भीतर इसकी सूचना उपलब्ध कराएं। विभाग की लंबित सभी एसी-डीसी विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की सूची भेजी जा रही है।

विभागीय निदेशनुसार, एक-एक आवंटन आदेश को देखने और उसकी पहचान करने की हिदायत दी गयी है। पहचान के बाद उपयोगिता विपत्र प्राप्त करने का भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यही नहीं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सासाहिक समीक्षा करने और इसकी कार्यवाही संधारित करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी प्राप्त अनुदान राशि जैसे- पोशाक, छात्रवृत्ति, वेतन, सार्विकल,

प्रोत्साहन राशि, परिश्रमण राशि और भवन निर्माण की एसी-डीसी एवं उपयोगिता 2018-19 तक का शून्य होना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 10 फरवरी 2021 तक सभी लंबित पत्रों की पहचान करने का आदेश दिया है। 15 फरवरी तक सभी एसी-डीसी विपत्र महालेखाकार में जमा करने और 20 फरवरी 2021 तक सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का सख्त निर्देश दिया है। तमाम निर्देशों का क्या और कैसा फलाफल आता है, यह देखना बेहद जरूरी है लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने है, उसके मुताबिक, बड़े घपले की बूँ पहले से आ रही है। यह बेहद खास बात है कि सरकार ने, शिक्षा के नाम पर सरकारी खजाने का मुँह पूरी तरह से खोल रखा है। लेकिन जिस-जिस मद में पैसे दिए जा रहे हैं, वह जमीन पर मूर्त रूप में नजर नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, सरकार के दिये पैसे को जिला और प्रमंडल में अधिकारी, अपनी-अपनी मर्जी से कागजी तौर पर खर्च कर रहे हैं। इस पूरे काम-काज का कोई भी मोनेटरिंग, राज्य मुख्यालय की तरफ से नहीं हो रहा है। शिक्षा माफिया और बिचौलिए, शिक्षा अधिकारी और कर्मी को लूटने का हार रास्ता बता रहे हैं। बिना किसी हिसाब-किताब के लापता हुए 700 करोड़ रुपये में जमकर लूट का खेल हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ज़ूँच और कुछ पड़ताल के बाद, यह मामला सरकारी फाईलों में ढब कर, दीमक का निवाला बनेंगे। अखिर में, हम ताल ठोक कर कहते हैं कि सरकार के सभी विभागों में, कमोबेस यही आलम और मंजर है।

रोहतास के डीएम धर्मेन्द्र के कदम से खुश होगी शेरशाह की आत्मा

■ तीन दशक से जारी समस्या का सासाराम में हुआ समाधान

■ चौक चौराहे पर लोग कर रहे हैं सराहना

अखिलेश कुमार

बात है कीरब 500 वर्ष पुरानी है, विंध्य गिरि पर्वत श्रृंखला की तराई में पला-बढ़ा एक शख्त अपने पराक्रम के बदौलत हिंदुस्तान का बादशाह बना, और उसने दक्षिण एशिया का सबसे लंबा सड़क 2500 किलोमीटर का ट्रैक्ट्रंक यानि जीटी रोड बनवाया था। जो कोलकाता से उसके जन्मभूमि सासाराम को जोड़ते हुए पेशेवर तक बनी। इसी सड़क का नाम अब राष्ट्रीय राजमार्ग-2 है। कीरब तीन दशक से भी अधिक समय से यह शहर जाम की समस्या से जूँझ रहा था। कितने सरकारें बनी और बिगड़ी तथा कई जिलाधिकारी आए और गये, परन्तु जाम की समस्या से निजात दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। वर्ष 2005-6 में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 यानि जीटी रोड का फोर लेन सड़क का बाईपास भाया ताराचौड़ी निर्माण हुआ, लेकिन समस्या ज्यों का त्यों बनी रही। उस बादशाह के अपने कस्बे की हालत यह बन गया था कि लोगों ने रथानीय भाषा में कहावत बना डाली है "जब मिली जाम त समझ जईह कि आ गईल सासाराम" ! जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह सूरी का जिसने मात्र 5 साल के कार्यकाल में



जामीन, सड़क, कर आदि के क्षेत्र में जो व्यवस्था किया वह काबिले तारीफ है, लेकिन इस अत्याधुनिक युग में भी उसी बादशाह के कर्मभूमि सासाराम को सड़क पर जाम की समस्या दर्शकों तक लोगों के परेशानी का सबब बना। प्रतिदिन जाम लोग परेशान होते रहे। कई मरीज लेकर, प्यास से भूखे बच्चे, चिलचिलाती धूप या कड़के की ठंड, इसके बावजूद सभी संसाधन होने के बाद भी प्रशासन जाम की समस्या से शहर को निजात नहीं दिला पा रही थी। लेकिन पछले जनवरी माह में रोहतास के जिलाधिकारी का पदभार संभालने के बाद धर्मेन्द्र कुमार जब खुद इस समस्या का शिकार बने तो इसके समाधान के लिए गंभीर हुए और जिला मुख्यालय के जाम वाले प्रमुख मार्ग का दिन के साथ ही साथ रातों में पैदल निकलकर मुआयना किया तथा इस समस्या का

निदान निकलने की ठान ली। सड़क के किनारे लगने वाले अवैध फुटपाथी दुकान व वाहन के खिलाफ अभियान चलाया तथा शेरशाह मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्थल तक पहुँचाने वाले सड़क सहित अन्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर वन वे परिचालन आरंभ कराया। पटना की बेली रोड के तरह सासाराम में भी कई कट को बंद कराया और देखते ही देखते दशकों से कायम जाम की समस्या से जूँझ रहे रोहतास वासियों को जिला मुख्यालय में निजात मिल गई। फिर अतिक्रमण न हो और सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के लिए तैनात पुलिस कर्मी लापरवाही न करें, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अपने कार्यालय में लगे स्क्रीन पर जिलाधिकारी खुद नजर रख रहे हैं। उनके इस कदम की सराहना नगरवासियों द्वारा खुब की जा रही है।



रोडरेज के कारण हुआ था खपेश की हत्या - पुलिस

रूपेश हत्या कांड जांच का हश भी कहीं
सुशान्त मामले के राह पर तो नहीं!

इंडिगो एयरलाइंस मैनेजर हत्या के खुलासे
पर किसी को भरोसा नहीं।

अखिलेश कुमार

पिछले 12 जनवरी को पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। इसका कारण यह रहा कि एक एयरलाइंस कर्म्पनी के मैनेजर रहते हुए रूपेश सिंह ने अपने कार्यस्थली से बिहार के ब्यूरोक्रेट्स से लेकर राजनीतिक गलियरों में अपनी अच्छी पहचान बना ली थी। बिहार के प्रमुख पत्रकारों से भी उनके मधुर संबंध थे। हत्या को जिस तरिके से अंजाम दिया गया था, उससे यह स्पष्ट ज़ालक रहा था कि इसे किसी पेशेवर व शातिर सूटरों ने अंजाम दिया है और इस हत्या के पिछे कोई बहुत बड़ा साजिश है। रूपेश सिंह शरीर पर आधा दर्जन गोलियां बरसाई गई थीं और हत्या कांड को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से अपने सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए थे।

इस हत्याकांड के प्रमुख कारणों में ठिकेदारी, हथियार का लाइसेंस दिलवाने व राजनीतिक कारणों को केन्द्र में खक्कर बिहार के पत्रकार तथा विपक्ष के राजनेता देख रहे थे। बिहार के कई आईएस से उनके मधुर संबंध और उस सम्बन्ध के माध्यम से लोगों को ठिकेदारी तथा हथियार के लाइसेंस दिलवाने की चर्चा भी रही। साथ ही साथ रूपेश के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी इस मौत के कारणों में गिनाया जाने लगा। इस हत्याकांड के उद्देश्य करने के लिए बिहार के सभी विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता के भागीदार दलों ने भी पुलिस पर दबाव बनाया। एसआईटी गठित की गई और एसआईटी द्वारा हत्याकांड की जांच का जो खुलासा हुआ उस पर आज किसी को भरोसा नहीं हो रहा है।

पटना से एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने इस हत्या का कारण रोडरेज बताया है और इस मामले में रितुराज नामक एक युवक को गिरफ्तार कर उसे हत्या का मुख्य आरोपी बनाया है। एसएससी उपेंद्र कुमार शर्मा ने जो दावा किया है उसके अनुसार पिछले नवंबर महीने में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की गाड़ी रितुराज नामक युवक के बाइक से टकरा गई थी उस दिन दोनों के बीच झड़प हुई थी और उसी के बाद रितुराज ने रूपेश सिंह की हत्या करने को ठान लिया था। पुलिस का यह भी दावा है कि रितुराज ने 12 जनवरी को हत्या से पूर्व भी चार बार रूपेश को गोली मारने का



प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। पुलिसी यह भी कह रही है कि हत्या से पहले रितुराज को यह पता नहीं था कि रूपेश सिंह इतना पहुंच वाला व्यक्ति है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपी रितुराज ने पहले कोई हत्या नहीं की है, वह मायूली एक बाइक चोर है। पुलिस के इस दावे पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है।

भरोसा नहीं होने के कई कारण भी हैं। सबाल यह उठता है कि नंबर महीने में रोडरेज की घटना के बाद जब रितुराज ने रूपेश सिंह की लगातार रेकी करते रहा, पीछा करते रहा तो क्या उसे पता नहीं चल वह आदमी कौन है? दूसरा सबाल कि जब रितुराज ने पहले कभी किसी हत्या जैसी जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दिया था तो हत्याकांड के दौरान उसने आधा दर्जन गोलियां किसी पेशेवर हत्यारे की तरह रूपेश सिंह के शरीर में कैसे दाग दी? साथ रात सबाल यह भी उठ रहा है कि रितुराज के साथ देने वाले अन्य हत्यारे आखिर पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर क्यों हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि रूपेश हत्या कांड को अंजाम देने से पहले एक बड़ी साजिश रची गई हो और बाइक से उसके गाड़ी में टक्कर मारकर हत्या कांड को अंजाम देने के लिए महिनों पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा हो? ऐसे कई बिंदु हैं, जिसपर गहराई से जांच करने की जरूरत है।

इधर आरोपी रितुराज की पती साक्षी मीडिया के

समाने दवा की है कि उसके घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है पुलिस थाने में ले जाकर मेरे पति के साथ साथ मुझे भी प्रताड़ित किया है और बदन से कपड़े उतार कर पिटाई की जिसके चलते रितुराज ने पुलिस की बताई हुई कहानी को स्वीकार कर लिया है उसने अपने शरीर पर गंभीर चोट को दिखाया। हालांकि यदि पुलिस ने पुछताछ के दौरान यदि आरोपी रितुराज के सख्ती बरती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पती के साथ जो सलूक किया गया है वह काफी गंभीर मामला है।

इधर रूपेश सिंह के परिजन भी पुलिस द्वारा हत्या के कारणों की खुलासे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनकी पती नीतू सिंह पिता शिवजी सिंह तथा भाई नंदेश्वर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर पुलिस के खुलासे और दावे पर और अविश्वास करते हुए इसे गहराई से जांच करने की मांग की है। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी रूपेश सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस के खुलासे को दक्षिण भारत के सी ग्रेड फिल्मी कहानियों के तरह बताते हुए रसूखदारों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं।

अब देखना यह है कि आगे पुलिस क्या सफलता हासिल करती है या फिर पिछले 14 जन 2020 को मुंबई में देश के चर्चित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले जैसा ही कहीं रूपेश सिंह हत्याकांड का मामला बनकर तो न रह जाए!

फरमानों से नीतीश की हो रही है फजीहत सरकार को बार-बार अपने आदेश पर देनी पड़ती है सफाई



अखिलेश कुमार

बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा जारी की जा रही फरमानों से नीतीश कुमार को काफी फजीहत झेलनी पड़ रही है। और फरमानों के खिलाफ आम लोगों के साथ विपक्षी दलों के द्वारा की रही हमले के बाद फिर उन्हीं अधिकारियों को सफाई देने को भी मजबूर होना पड़ रहा है। इसी तरह कि दो फरमान पिछले दो सप्ताह के भीतर जारी की गई पहला पत्र 21 जनवरी को आर्थिक अपराध शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान द्वारा बिहार के सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव को जारी की गई जिसमें कहा गया कि सरकार, माननीय मंत्री गण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई भ्रामक टिप्पणी को साइबर अपराध की श्रेणी में मानते हुए उन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के इस आदेश की आलोचना चौतरफा होने

लगी और लोगों ने नितीश कुमार की तूलना मुसोलनी तथा हिटलर से करने लगे। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला व पाबंदी लगाने तथा सरकार द्वारा अपनी आलोचना करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कदम के रूप में देखा गया। चौतरफा आलोचना के बाद सरकार के तरफ से यह बयान देना पड़ा कि इस पत्र में कोई नई बात नहीं कही गई है और पूर्व से साइबर क्राइम के तहत जो करवाई होती थी वही करवाई होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आर्थिक अपराध शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किये गये 21 जनवरी के पत्र को लेकर सरकार की आलोचना हो ही रही थी कि बिहार के पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल ने 1 फरवरी को एक पत्र जारी कर आम लोगों के साथ विपक्ष के आलोचना का पत्र बन गये। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था के स्थिति विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामले में शामिल होता

है और पुलिस द्वारा इस कार्य के लिए आरोप पात्रित जाता है तो उसके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट इस बात को अवश्य प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्ति को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उस से सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकेदारी आदि नहीं मिल पाएगा। डिजीपी ने सभी कनिष्ठ अधिकारियों को इसे सौ फीसद पालन करने की सख्त हिदायत भी दी है। उनके इस आदेश का चौतरफा आलोचना हो रहा है। संवेदन संघ, छात्र संगठन और विपक्षी दलों द्वारा डिजीपी के पत्र को तुगलकी फरमान और हिटलर शाही करार दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव व लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पपू यादव आदि का कहना है कि सरकार ऐसा पत्र जारी कर लोगों को डग रही है, ताकि वे सरकार के गलत नीतियों और गलत कार्य का विरोध न करें। यह लोकतंत्र के लिए घातक है।

जानिए बिहार की राजनीति के अभिमन्यु क्यों है सुमित सिंह

अनूप नारायण सिंह

मंगलवार को बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री परिषद का विस्तार था मंत्रिमंडल में शामिल लोग शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपने समर्थकों के द्वारा पूरी मालाओं से सम्मानित किए जा रहे थे तथा जय जय कार के साथ उनका काफिला आगे बढ़ता जा रहा था पर इन सबसे अलग चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह शपथ ग्रहण करने के बाद जब बाहर निकले तो उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि चकाई से जो लोग सुबह से आए हैं उन्होंने भोजन किया कि नहीं वे कहां ठहरे हैं एक-एक कार्यकर्ता से मिल रहे थे तथा उनसे बधाई लेने की जगह उनके रहने खाने ठहने की सुविधा पूछ रहे थे। मौजूदा बिहार विधानसभा में एकमात्र स्वतंत्र विधायक सुमित कुमार सिंह को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। सुमित कुमार सिंह वर्ष 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पहली बार चकाई से विधायक बने थे तथा नीतीश सरकार को समर्थन किया था। 2015 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया वह निर्दलीय मैदान में उत्तरे और काफी कम अंतर से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने जदयू के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। पूरे 5 साल क्षेत्र में सक्रिय रहे लोगों से मिलते जुलते रहे। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जदयू ने उनका टिकट काट दिया। सुमित सिंह कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे एक तरफ जदयू का संगठन खड़ा करने के लिए जमुई के मौजूदा सांसद लोजपा युवराज चिराग पासवान के साथ उनका और उनके परिवार का छत्तीस का आंकड़ा बना रहा वहीं दूसरी तरफ राजद के निशाने पर भी सुमित सिंह व उनका परिवार रहा। विधानसभा चुनाव के समय अंतिम वक्त में उनकी जगह राजद से पलायन कर जदयू में आए सुनील प्रसाद को जदयू ने सिंबल थमा दिया। फिर भी सुमित सिंह ने जदयू व नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द तक मुंह से नहीं निकाला। उन्होंने पूरी जमुई जिते में जदयू की मजबूत टीम खड़ी की थी। राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी लोगों को घर-घर तक पहुंचाया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके जदयू अपना टिकट देगी पर अंतिम समय में वे राजनीति के शिकार हो गए। उन्होंने निर्दलीय चकाई की जनता से न्याय मांग पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने कभी भी किसी भी दलीय व्यक्ति के लिए किसी भी तरह के कटूता पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जो लोग आज सुमित सिंह की उपलब्धि को विरासत की राजनीति मान रहे हैं। उन्हें जानना जरूरी है कि सुमित सिंह के परिवार में कई पीढ़ियों से राजनीति में लोग आ रहे हैं। उनके पिता नरेंद्र सिंह बिहार के



राजनीति के वटवृक्ष है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री व कृषि मंत्री रह चुके हैं। धारा के विपरीत राजनीति उन्हें पसंद है। सुमित सिंह के बड़े भाई दिवंगत अभ्यं सिंह चकाई से विधायक रह चुके हैं। उनके बड़े भाई अजय प्रताप जमुई

से भाजपा विधायक रह चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद सुमित सिंह को पटा में दिल्ली की आओ हवा नहीं भाति। उन्हें चकाई के ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच रहना लोगों के दुख दर्द में सहभागी रहना ही भाता है। यही कारण है कि तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद बिहार विधानसभा चुनावी महाभारत में अभिमन्यु की तरह उन्होंने चक्रव्यूह भेद कर निर्दलीय चुनाव जीतने में सफलता पाई। विधानसभा चुनाव में सुमित कुमार सिंह को चकाई में वहाँ की राजद विधायक के साथ ही साथ जदयू लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सशक्त उम्मीदवारों से एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। सुमित कुमार सिंह को चकाई के रण में धेरने के लिए सभी विरोधी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। पर सुमित कुमार सिंह को सिर्फ और सिर्फ चकाई के लोगों पर भरोसा था। वे दिन-रात लोगों के बीच रहे। उपलब्धि यह है कि मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव में एकलौते निर्दलीय विधायक हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया है। मंत्री पद का शपथ लेने के बाद सुमित कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि वे जमुई चकाई सोनू के जनता को या मंत्री पद समर्पित करते हैं। वहाँ के लोग उनके मालिक हैं। नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं। जनतंत्र में जनता ही मालिक होती है। और जनता ने उन पर विश्वास जताया है। जब वे इस सरकार का समर्थन करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में चौपाल लगाकर लोगों से राय मांगी। लोगों ने कहा कि आप सदैव नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। इसलिए आपको जदयू का समर्थन करना चाहिए। वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने पद की गरिमा को कायम रखेंगे। उन्हे जो जिम्मेदारी मिली है, उसे वह सेवा करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानते हैं। पिंडा नरेंद्र सिंह जी के आदर्शों को कायम रखने के लिए वे सदैव तत्पर रहेंगे।

उद्योग मंत्रालय सम्बालते ही शाहनवाज की हुंकार बिहार में लगेंगे उद्योग बढ़ेगा रोजगार की रफ्तार

बिहार में रोजगार और उद्योगों की मांग हमेशा से उठती रही है। यहाँ से पलायन करने वाले बेरोजगार युवा तथा मजदूरों का असली तस्वीर कोरोना काल में दुनिया के सामने तब आया, जब घर वापसी के लिए दिल्ली, मुम्बई, गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों से बच्चों महिला व बुद्ध के विलखते लोगों की तस्वीरें सामने आया। इसके बाद बिहार के बेरोजगारी तथा पलायन का मुद्दा जोरों से उठा था। तथा यहाँ उद्योग के अवसर उपलब्ध कराने की मांग तूल पकड़ा। वहीं इस बीच चुनाव हुआ। पिछले नवम्बर महिने में सम्पन्न बिहार विधानसभा चुनाव में राजग गठबंधन की वापसी तो हुआ लेकिन नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ। हालांकि भाजपा द्वारा उनके प्रति दिखाई गई उदारता ने नीतीशकुमार के नेतृत्व में पुः सरकार का गठन हो गया। लेकिं नयी सरकार के समक्ष बिहार में उद्योग धंधे के अवसर मुहैया कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए शायद भाजपा ने केन्द्र सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके शाहनवाज हुसैन को एमएलसी बनाकर उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। उद्योग विहीन बिहार में शाहनवाज हुसैन जैसे अनुभवी तथा बड़े नेता को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी जब सौंपी गई, उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि केन्द्र सरकार राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए जरूर गंभीर होगी। शपथ लेने के बाद शाहनवाज हुसैन ने अपने पहले व्यायाम में यह स्पष्ट भी दिया कि आने वाले दिनों में बिहार में उद्योग धंधे के का बड़ा नेटवर्क बनेगा और आने वाले दिनों में बिहार के बेरोजगार तथा मजदूरों का पलायन थमेगा।

बिहार में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में टेक्सटाइल का भविष्य काफी उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के द्वारा कोरोना काल में कराया गया स्किल मैपिंग इसमें बेहद सहायक होगा। शाहनवाज हुसैन ने उद्योग मंत्रालय की कमान संभालने के बाद कहा की बिहारियों का डंका हर जगह बजा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ही ऐसी क्षमता है जो इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बांग्लादेश को चुनौती दे सके। शाहनवाज ने बताया कि बतौर उद्योग मंत्री टेक्सटाइल सेक्टर उनके लिए खास प्राथमिकता होगी। वे केंद्र सरकार में टेक्सटाइल मंत्री भी रह चुके हैं और इस अनुभव का उन्हें यहाँ खास फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दूरवार्षिता उनके काफी काम आई, जो भी बाहर के राज्यों में काम करने वाले कामगार यहाँ



लॉकडाउन में बिहार लौटे उनका स्किल मैपिंग नीतीश कुमार ने करा लिया। शाहनवाज के मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। सन्तर प्रतिशत तो ऐसे कामगार हैं जो टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्हें हम यहाँ रोजगार दे सकते हैं। बिहारवासी करें निवेश उद्योग मंत्री ने कहा कि जब बिहार में कुशल कामगार, जमीन और सरकार के सहयोग के साथ ही विजली भी उपलब्ध है तो उद्योगों की तरक्की काफी तेजी से की जा सकती है। उन्होंने संपन्न बिहारवासियों से अपने राज्य में वापस आने की अपील की। वहीं निवेशकों को बिहार लाने की बात पर उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जहाँ भी जाना पड़ेगा वो जाएंगे। लोगों

को यह डर है कि बिहार में अपराधिक घटनाएं और कई राज्य से काफी अधिक हैं जबकि नीतीश काल के शासन में यहाँ महाराष्ट्र से भी कम अपराधिक घटनाएं हुई हैं। अब बिहार केवल कंज्यूमर नहीं बनेगा बल्कि उत्पादक राज्य बनेगा। वे डेयरी उत्पदकों से भी अपील करेंगे कि वो बिहार में अपनी उत्पादन इकाई लगाएं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है ऐसे में एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं हैं। गन्ना जो की यहाँ काफी प्रचुर मात्रा में होती है ऐसे में यह पूरे देश को इथेनॉल सप्लाई कर सकता है। वहीं हैंडलूम सेक्टर इंडस्ट्री भी युवाओं के सपने को पंख लगाने का काम करेगा।

पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहारी प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई अपनी पहचान : विजय कुमार सिन्हा



बिहार प्रतिभाओं की खान है पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहारी प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है बदले समय में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिजिटल का प्रभाव पड़ा है ऐसे दौर में बिहार में अत्यधिक सुविधाओं के साथ अरनव मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड न्यूज एंजेंसी का शुभ्रांभ शुभ संकेत है इसके लिए कपनी के प्रबंध निदेशक भूषण कुमार सिंह बबलू व वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह बधाई के पात्र हैं। अरनव मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नवनिर्मित कार्यालय व हाईटेक स्टूडियो का आज पटना के बोरिंग रोड इलाके में शुभ्रांभ हुआ। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने फीता काटकर किया स्टूडियो का

शुभ्रांभ इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी, बिहार सरकार गृह विभाग में विशेष सचिव आईपीएस अधिकारी विकास वैभव, चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह विधायक अरुण कुमार सिंह, पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह अमनौर के विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह तरैया के विधायक जनक सिंह मढ़ौरा के विधायक जितेंद्र कुमार राय बैकुठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव बनियापुर के विधायक केदारनाथ सिंह पटना दीवा से विधायक संजीव चौरसिया बांकीपुर विधायक नितिन नवीन लालगंज से विधायक संजय कुमार सिंह बिस्कोमान चेयरमैन और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह बिहार राज्य महिला आयोग की निवृत्तमान अध्यक्ष दिलमणि

मिश्रा, समाजसेवी विकास चंद्र गुड्डू बाबा गुरु डॉक्टर एम रहमान समेत कई गणमान्य उपस्थित थे आगत अतिथियों का स्वागत अरनव मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अनूप नारायण सिंह ने पुष्पगृच्छ देकर किया इस अवसर पर अरनवनव मीडिया के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता ओम कुमार सिंह प्रबंधक आचार्य रूपेश कुमार पाठक प्रबंधक धीरज कुमार सिंह भी उपस्थित थे। कपनी के प्रबंध निदेशक भूषण कुमार सिंह बबलू ने आगत अतिथियों को कंपनी का स्मृति चिह्न भेंट किया। अरनव मीडिया बिहार की पहली डिजिटल प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एकलौती न्यूज एंजेंसी है जो मीडिया मैनेजमेंट इंवेंट फिल्म निर्माण व आईटी सेक्टर में भी कार्य करेगी।

एलिट संस्थान में छात्रों के लिये छात्रवृति की अनोखी पहल संस्थान के संस्थापक-निदेशक के जन्मदिन पर फीस में विशेष छूट !

इंजीनियरिंग और मेडिकल-प्रवेश परीक्षाओं में अपने उत्कृष्ट रिजल्ट के लिये प्रसिद्ध एलिट इंस्टिच्यूट ने अपने संस्थापक-निदेशक अमरदीप झा गौतम के जन्मदिवस के अवसर पर छात्रों के लिये विशेष-स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। इसके लिये कोई भी छात्र-छात्रा अपने आधार-कार्ड और परीक्षा-रिजल्ट की छायाप्रति (जेरोक्स) के साथ संस्थान के बोरिंग रोड स्थित कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं। ज्ञात हो कि संस्थान के निदेशक अमरदीप झा गौतम का जन्मदिवस 12 फरवरी है और प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर बहुत-सारे छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में एलिट की तरफ से विशेष सहायता मिलती है। संस्थान में आयोजित प्रेस-चार्टर में बताया गया कि 9 फरवरी से 13 फरवरी तक नामांकन करने वाले छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुये संस्थान के निदेशक ने बताया कि 30 छात्र-छात्राओं को इस योजना के आधार पर एलिट में पढ़ाई के लिये सहायता प्रदान किया जायेगा। इस योजना का लाभ ग्यारहवीं और बारहवीं कक्ष के विद्यार्थियों के साथ-साथ जेईई और नीट (मेडिकल) के छात्र भी उठा सकते हैं।



साक्षात्कार : ज्याय के साथ विकास की अवधारणा को घर-घर तक पहुंचाना ही लक्ष्य

बिहार के नवनियुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अनन्व मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के संपादक अनूप नारायण सिंह के साथ एक विशेष बात में बातचीत में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करना न्याय के साथ विकास को घर-घर तक पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। बिहार में विकास की गति को और तीव्रता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है सीमित संसाधनों में बेहतर कार्य कैसे किया जाए इसके लिए पूरी टीम भावना के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की जनता से तीन महीने का समय मांगा तथा कहा कि विभाग को और सुदृढ़ बनाएंगे आम लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की



कोशिश करेंगे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों को संसाधनों से युक्त किया जाएगा राज्य के हुनरमंद युवाओं को दक्षता प्रदान करने की दिशा में भी कारगर कदम उठाए जाएं अपने विधानसभा चकाई को चंडीगढ़ बनाने के अपने बाद को दोहराते हुए उन्होंने कहा चकाई के लोगों ने उन पर विश्वास जाताया है राज्य मंत्रिमंडल में चकाई कि जनता के आशीर्वाद से पहुंचे हैं उन्होंने क्षेत्र की जनता से विकास का जो बाद किया है उसे पूरा करने की दिशा में लगे हुए हैं विकास कार्य द्रुत गति से चल रहा है मंत्री के रूप में भी क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ करना होगा वह उसे पूरा करेंगे उन्होंने कहा कि बिहार का कोई भी व्यक्ति उनके मंत्रालय से संबोधित कार्य के सिलसिले में उनसे विभाग में आकर मिल सकता है जो पटना के विश्वविद्यालय भवन परिसर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भवन में अवस्थित है।

एक दौर था कि बिजली की नाच नहीं तो शादी नहीं

लड़का-लड़की पक्ष के सहुलियत से नहीं, बिजली रानी के अनुसार तय होता था शादी की तिथि

हुस्न ही नहीं, हुनर की भी मलिलका रही है बिजली रानी

अखिलेश कुमार

'बिजुलिया के नाच' जी हां, शाहाबाद हीं नहीं, देश विदेश में बसे भोजपुरी भाषी लोगों के दिलों पर नाच गाने के क्षेत्र में करीब 5 दशक तक एकक्षत्र राज करने वाली नृत्यांगना बिजली रानी किसी नाम की मोहताज नहीं है। एक जमाना रहा है जब 'बिजुलिया के नाच' का नाम आते ही उसे देखने के लिए लोग रात में कई किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। बिहार के रोहतास जिला निवासी इस नृत्यांगना ने अपनी पहचान केवल हुस्न के बदौलत नहीं बनाई, बल्कि हुस्न के साथ हुनर भी बहुत है इसके पास। अपने हुनर और हुस्न के बदौलत इसने जो शोहरत हासिल की है उसे आज तक इस क्षेत्र में कोई चैलेंज नहीं कर सका, और ना ही भोजपुरी भाषी लोगों के दिल में वह जगह बना पाया जो बिजली रानी ने बनाया। बिजली रानी के साथ एक हास्य कलाकार लखी शर्मा हुआ करते थे, और इन दोनों की जोड़ी खूब जमती थी, खासकर बच्चों में काफी लोकप्रिय थे लखी शर्मा। पांच दशक से भी अधिक से बिजुलिया के नाच की अमिट छाप भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में बना हुआ है, और उसके नाम के प्रभाव को आजतक कोई भी महिला कलाकार नाच गाने के क्षेत्र में कम नहीं कर पायी है। जो लोग आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उनके सामने भी जब बिजली रानी का नाम आता है तो वो पुरानी यादों में खोए बिना नहीं रह पाते हैं। एक दौर था जब शादी में बिजली रानी नाच करना लौग गर्व की बात समझते थे, और शादी की तिथि लड़का लड़की पक्ष के सहुलियत से नहीं बल्कि बिजली रानी के नाच की उपलब्धता को देखते हुए तय किया जाता था। बकौल बिजली रानी - 'मेरे टीम के लिए कई शादियां तो इस साल के बदले अगले साल तक के लिए टाल दिया जाता था।' बिजली रानी कहती है कि ऐसा भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ा है कि शादी में नाच का साटा (एग्रीमेंट) कहीं और का होता था और बन्दूक के नोक पर दबंग लोग बीच रास्ते से जबरन कहीं और लेकर चले जाते थे। बिजली रानी बताती है कि एक बार गुलशन कुमार उसे रिकॉर्डिंग के लिए मुम्बई बुलाए थे, हवाई जहाज का पायलट मेरा गया हुआ गाना 'पनिया' के जहाज से पलटनिया बन के अइ' बज रहा था। कैसेट पर फोटो देखकर वह पायलट हमें पहचान गया और साथ में फोटो खिंचवाया। उन्होंने बताया कि पांच वर्ष के उम्र से हीं नाच गाना अरंभ कर दी थी। तब डिजिटल जमाना नहीं था, इसके बावजूद नाच गाने की शोहरत देश की सीमा पार कर दुनिया के कई देशों में पहुंच गया था। आज उम्र के हिसाब से भले हीं वह जवानी से बुढ़ापे के तरफ तेजी से अग्रसर हो रही है, लेकिन जो आवाज और खनक है वह अभी भी कायम है। बिजली रानी बताती है कि वह बचपन से हीं शाकाहारी हैं और कभी शराब की सेवन नहीं की। कला व संगीत एक आराधना, पूजा है, तथा इसमें सफलता हासिल कर उसे कायम रखने के लिए खानपान में संयम रखना जरूरी होता है। भले हीं आज संगीत और नाच-गाने की दुनिया में थोड़ी सी शोहरत मिलते हीं जहाँ लोगों को बॉलीवुड से लेकर राजनीति के क्षेत्र में व्यापक अवसर मिल जा रहे हैं, वैसा सोहरत व अवसर बिजली रानी को नसीब नहीं हुआ। इसके बावजूद नाच गाने के शौकीन लोगों के दिल में बिजली रानी ने जो जगह बना ली है वह शयद ही किसी को मयस्सर हो ! बिजली रानी भोजपुरी गायक के क्षेत्र में अक्षीलाता के बढ़ते प्रभाव से दुखी हैं और भोजपुरी गायकी के के क्षेत्र में कदम रखने वाले नई पीढ़ी के लोगों से अक्षील संगीत से दुरी बनाकर भोजपुरी भाषा के मर्यादा बनाए रखने की अपील भी करती हैं।



एक दौर था जब शादी में बिजली रानी नाच करना लौग गर्व की बात समझते थे, और शादी की तिथि लड़का लड़की पक्ष के सहुलियत से नहीं बल्कि बिजली रानी के नाच की उपलब्धता को देखते हुए तय किया जाता था। बकौल बिजली रानी - 'मेरे टीम के लिए कई शादियां तो इस साल के बदले अगले साल तक के लिए टाल दिया जाता था।' बिजली रानी कहती है कि ऐसा भी परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ा है कि शादी में नाच का साटा (एग्रीमेंट) कहीं और का होता था और बन्दूक के नोक पर दबंग लोग बीच रास्ते से जबरन कहीं और लेकर चले जाते थे। बिजली रानी बताती है कि एक बार गुलशन कुमार उसे रिकॉर्डिंग के लिए मुम्बई बुलाए थे, हवाई जहाज का पायलट मेरा गया हुआ गाना 'पनिया' के जहाज से पलटनिया बन के अइ' बज रहा था। कैसेट पर फोटो देखकर वह पायलट हमें पहचान गया और साथ में फोटो खिंचवाया।

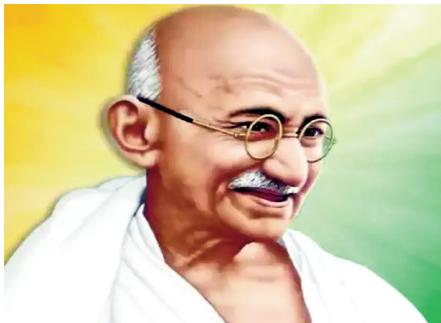
गांधी और नया भारत

सलिल सरोज, नई दिल्ली

न्यू इंडिया को आकार देने में महात्मा गांधी की भूमिका और प्रभाव निर्विवाद है। वह अभी भी इकाईसवीं सदी में एक व्यक्ति और एक दार्शनिक के रूप में प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, इस भूमंडलीकृत, तकनीक-प्रेमी दुनिया में, 'सर्व धर्म सम भाव', या सभी धर्म समान हैं, और 'सर्व धर्म सदा भाव', या सभी धर्मों के प्रति सद्ब्राव, जो गांधी-जी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, सद्ब्राव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और 'वसुधैव कुटुम्बकम' (दुनिया एक परिवार है) के अपने विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है।

स्कॉटिंश इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने उन्नीसवीं शताब्दी में अर्थशास्त्र के लिए एक और शब्द 'निराशाजनक विज्ञान' को गढ़ा था। वह स्पष्ट रूप से अंग्रेजी विद्वान टी आर माल्यस की भविष्यवाणी कि आजादी हमेशा खाद्य उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ेगी, जिससे मानव जाति को गरीबी और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा से प्रभावित माना जाता है। इसे अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या के रूप में भी जाना जाता है: असीमित चाहतों और सीमित संसाधनों के बीच बेमेल। हालाँकि, भारत में, हमने हमेशा असीमित खपत के विपरीत तर्कसंगत खपत में विश्वास किया है, और इसलिए, उपभोक्तावाद हमारे देश में आसानी से जड़े लेने में सक्षम नहीं है। गांधी-जी ने हमारे पारिस्थितिक त्रों को संरक्षित करने, जैविक और पर्यावरण के अनुकूल हर चीज का उपयोग करने और पर्यावरण पर कोई तनाव न पैदा करने के लिए हमारी खपत को कम करने पर बहुत जोर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी खुद की खपत की मांग भी कम कर दी। दुर्भाग्य से, आज, हम एक ऐसे चरण में पहुँच गए हैं जहाँ हम प्रकृति पर बोझ बन गए हैं और वसुधैव कुटुम्बकम का लक्ष्य अप्राप्य है। इसलिए हमें उनके नक्शेकदम पर चलना चाहिए, हमारी नाजुक पारिस्थितिकी के चारों ओर एक वातालाप शुरू करना चाहिए और हम इसे नष्ट करने के लिए कैसे करीब आ रहे हैं, और हमारी मांगों को तर्कसंगत बनाने के तरीकों पर चर्चा करें। भारत में एक दोहरी सामाजिक और आर्थिक संरचना स्थापित की गई है। हमारे 90 प्रतिशत लोग अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। शाही और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, कुलीन और जनता के बीच, पश्चिमी संस्कृति की रक्षा करने वालों के बीच एक विभाजन है। यह द्वंद्व गांधी जी के दर्शन के विपरीत है और हमें इस अंतर को बंद करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए जो पिरामिड के निचले भाग में हैं, कतार के अंत में, सभी पहलुओं में, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य या आर्थिक लाभ।

गांधी जी ने एक बार कहा था, 'स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों का अनुसरण करते हुए, इस राष्ट्र के इतिहास में पहली बार, एक प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रा दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारत को स्वच्छ बनाने के लिए नागरिकों की ओर संकेत



किया। यह कोई रहस्य नहीं है कि भारत में स्वच्छता एक बड़ा मुद्दा है। हममें से जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्वच्छ या स्वच्छ भारत में रहते हैं, उनके लिए स्वच्छता कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है; हालाँकि, यह इस देश में कई लोगों के लिए एक सच्चाई है। और उन्हें साफ करने में मदद करने के लिए, सरकार ने पिछले पांच वर्षों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया है, और 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। तथ्य यह है कि जब कोई एक गांव में जाता है, तो महिलाएं खुद शौच के लिए बाहर जाती हैं जोअपने आप में इस कटु सच की गवाही है। इससे इस देश के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन, वास्तव में, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में दस्त और मलेशिया को कम करने में मदद करता है। दुर्भाग्य से, आज तक भारत में 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जिसका एक बड़ा कारण डायरिया जैसे जलजनित रोग हैं। हालाँकि, ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर घर को पानी मिले, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहल की गई है।

एक स्वच्छ भारत अपने आप हमें एक स्वस्थ भारत की ओर ले जाएगा। गांधी-जी ने कहा था, 'रोकथाम इलाज से बेहतर है।' गांधी-जी अपने जीवन में हर दिन कई किलोमीटर पैदल चलते थे। 1913 से 1948 तक के अपने अधिकारियों के दौरान, उन्होंने लगभग 79,000 किमी की दूरी तय की। वह ढूँढ़ता से स्वस्थ और फिट रहने में विश्वास करते थे, जिसकी गूँज हमें सरकार की आयुष्मान भारत योजना में मिलती है। इस देश के इतिहास में पहली बार, 50 करोड़ लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनके अस्पताल में भर्ती होने का खर्च सरकार द्वारा बहन किया जाएगा। इस योजना का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे टियर- क्रक्क और टियर- क्रक्क शहरों में छोटे निर्माण होम और अस्पतालों के विकास की संभावना बढ़ जाएगी, जो पहले नहीं हुए थे क्योंकि उन क्षेत्रों में लोग ऐसी सेवाओं को बहन नहीं कर सकते थे। यह महान शहरों में अस्पतालों पर बोझ को राहत देने के लिए एक बहुत ही आवश्यक विकास होगा।

गांधी-जी हमेशा से चाहते थे कि भारत एक समृद्ध और सक्षम देश बने। यह अकल्पनीय है कि अब एक दशक पहले तक भारत में 37 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। लेकिन अब बैंक खाते खुलने की मुहीम से इन खातों में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं। अब आसानी से और कितनी जल्दी प्रत्यक्ष

लाभ हस्तांतरण किया जा सकता है। इस योजना का उपयोग करके कुछ 370 योजनाएँ लागू की गई हैं। वे सभी जो पहले औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर थे, अब जन धन के माध्यम से शामिल किए गए हैं। गांधी-जी महिला सशक्तीकरण के सबसे बड़े प्रस्तावक थे। उन्होंने खुले तौर पर वकालत की कि लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए, विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाना चाहिए और परदा व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को उनके घरों से निकालकर मुख्यधारा में शामिल किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जन आंदोलन में समर्थकों की अपनी सेना बनाई। एक पुरानी कहावत है, 'यत्र नार्येण पूज्यते तत्र रमन्ते देवता,' जिसका अर्थ है कि जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। शक्ति के साथ होने तक शिव जड़ है। हमें अपनी आर्थिक नीति और देश को लिंग के संदर्भ में गैर-भेदभावपूर्ण बनाना चाहिए। इस जागरूकता को चलाने के लिए, सरकार ने बेटी बच्चों, बेटी पढ़ाओं योजना शुरू की। तब, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, 8 करोड़ महिलाओं को गैर सेवकशन दिए गए थे। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार निर्भया फंड भी लेकर आई है। लेकिन सबसे बड़ा गैर चंजर, शिक्षा है। हमें अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए; उन्हें बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करना चाहिए। उसके लिए हम उनके माता-पिता को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं ताकि वे काम करने या शादी के लिए स्कूल से बाहर न निकलें। इसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होगी।

गांधी जी ने ग्रामराज्य का सपना देखा था, जहाँ पूर्ण मुशासन और पारदर्शिता होगी। उन्होंने यंग इंडिया (19 सिंबंदर 1929) में लिखा, 'राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज नहीं है। मेरा मतलब है राम राज, भगवान का राज्य। मेरे लिए, राम और रहीम एक ही हैं; मैं सल्त और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और भगवान को स्वीकार नहीं करता।' अगस्त 1934, उन्होंने कहा, 'मेरे सपनों की रामराज्य राजकुमार और कंगाल दोनों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करती है।' फिर 2 जनवरी 1937 के हरिजन में उन्होंने लिखा, 'मैंने रामराज्य का वर्णन किया है, जो नैतिक आधार पर लोगों की संप्रभुता का अधिकार है। भारत की स्वतंत्रता का मतलब पूरे भारत की स्वतंत्रता होना चाहिए। स्वतंत्रता को सबसे नीचे से शुरू करना चाहिए। इस प्रकार, प्रत्येक गांव एक गणतंत्र होगा। यह इस प्रकार है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपने मामलों का प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए। जीवन एक पिरामिड होगा जिसमें नीचे की ओर शीर्ष होगा। ह्लांगांधी-जी के इस सपने को साकार करने के लिए, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को स्थानीय विकास प्रशासन का केंद्र बिंदु बनाया गया है। ग्राम स्वराज को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए, पंचायतों के वित आयोग की धनराशि का 100% ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। गांधी जीविता के प्रतीक हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित विकल्प सार्वभौम और सर्वकालिक हैं।

बिहार का एग्रो टूरिज्म हब बनेगा

बेगूसराय, शुरू हो गई है सेब की भी खेती



नौकरी के लिए नहीं कर बेगूसराय को एग्रो टूरिज्म हब बनाने के लिए लिया है। इसके लिए उसने अपना सब कुछ लाग दिया और पहली कड़ी में सेब की खेती शुरू की है। आमतौर पर सेब हिमाचल प्रदेश में होता है लेकिन उसने कॉन्फ्रैक्ट पर खेत लेकर सेब का पौधा लगाया और जिद पर अड़ा है कि उसके यहां भी सेब फलेगा और वह हिमाचल प्रदेश में उगाए गए किसी भी सेब से गुणवत्ता में कम नहीं होगा। इसके लिए उसे सबसे उन्नत और लेटेस्ट तकनीक का पौधा हिमाचल प्रदेश से मिला है तथा तीन क्वालिटी डोरसेट गोल्ड, अन्ना एवं हरमन-99 की खेती शुरू की है। यह कमाल किया है गंगा के कछार पर बर्से बलहुपुर पंचायत-एक के सिंहपुर निवासी युवक अमित कुमार ने। पंतनगर विश्वविद्यालय से 2006 में कृषि स्नातक की उपाधि लेने के बाद अमित ने बेगूसराय में एग्रो टूरिज्म डेवलप करने के लिए विभिन्न जगहों का दौरा शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश के रहने वाले उद्यान और कृषि विशेषज्ञ हरमन जी से हुई। उनके सानिध्य में उसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। इसके बाद हरमन जी के द्वारा ही गर्म क्षेत्र के लिए डिवेलप किए गए सेब की क्वालिटी हरमन-99 लाकर अपने जिला में उपजाने का निश्चय किया। हरमन-99 को कई क्षेत्रों में उप जाए जाने वाले सेब के बीज को क्रॉस कर तैयार किया गया है। यह गर्म क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है तथा 40 डिग्री के तापमान तक हो सकता है। अमित के पास अच्छे जगहों पर जमीन नहीं थी, दियारा में इसकी खेती हो नहीं सकती है। इसके लिए उसने कॉन्फ्रैक्ट पर एक बीघा खेत लिया है। जिसमें सेब का पौधा लग गया है, अब थाई अमरूद, साउथ का अंगूर तथा अनार लगाने की तैयारी चल रही है। अमित ने बताया कि जब राजस्थान में सेब हो सकता है तो अपने यहां क्यों नहीं हो सकता है। औरंगाबाद में इसकी खेती हो रही है लेकिन उच्च क्वालिटी के सरकी खेती नहीं हो रही है।

सेब को स्वाइल से लेना-देना नहीं है, यह किसी भी मिट्टी में हो सकता है। पथरीली जमीन में भी हो सकता है, सिर्फ क्लाइमेट अनुकूल होना चाहिए। अपने कभी मौसम 40 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होता है। इसलिए यहां भी इसका उत्पादन होगा और हिमाचल प्रदेश से बेहतर होगा। 2022 से बेगूसराय और आसपास के बाजारों में अपने यहां का सेब उपलब्ध होगा। अमित ने बताया कि कृषि स्नातक करने का उद्देश्य नौकरी करना नहीं था। एकमात्र उद्देश्य है बेगूसराय को एग्रो टूरिज्म हब बनाना। इसमें पांच-दस साल या पूरी जिंदगी लगा जाए लेकिन एग्रो टूरिज्म हब को डेवलप करके रहेगा। जिससे दूसरे देश-प्रदेश के लोग बेगूसराय आकर स्थानीय तकनीक को देखें, जानें और किसान समृद्ध हों। हमारे यहां के लोग दूसरे देश-

परदेश में सीखने के लिए जाते हैं, वही चीज जब यहां होगी तो विकास में आपूर्तचूक तेजी आएगी। मेरे यहां भी सब कुछ है, कभी नहीं है, सिर्फ व्यवस्था का अभाव है। सरकार खेती किसानों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है लेकिन, ग्रास रूट पर किसानों को सपोर्ट नहीं मिलता है। व्यवस्था का दोष कुछ ऐसा है कि किसान कार्यालय में दौड़ते-दौड़ते थक कर अपना पैर खींच लेते हैं लेकिन, उसने सरकारी मदद नहीं, खुद के भरोसे एग्रो टूरिज्म डेवलप करने का सपना देखा है। इसकी शुरूआत अंतर्वर्ती खेती, जैविक खेती और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर किया है। विभागीय स्तर पर सहयोग का आश्वासन मिला है, अगर सहयोग नहीं भी मिलता है तो वह अपना सपना हर हाल में पूरा करके रहेगा।



कृषि स्नातक एक युवा ने यह सपना देखकर शुरू की है जिद की खेती उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों का सबसे पहला उद्देश्य रहता है अच्छी नौकरी करना लेकिन बेगूसराय के एक युवक ने उच्च शिक्षा

पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने तारापुर शहीद दिवस का किया जिक्र

सिद्धांत सिंह, मुंगेर

साथियों, इस वर्ष से भारत, अपनी आजादी के, 75 वर्ष का समारोह झंझ अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है, जिनकी बजह से हमें आजादी मिली।

साथियों, हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं, तो, मैं, नमो एप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूँगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी, 1932 को, देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे, एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए, जिस पर उनकी चर्चा नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी।

मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गाँव में आजादी की लड़ाई पूरी तकात



के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूत्रों और चीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने, राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, ऐसे में, यह, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और

इसके लिए उनके बारे में लिख कर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं। मैं, सभी देशवासियों को और खासकर के अपने युवा साथियों को आङ्खान करता हूँ कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें। अब, जबकि, भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनायेगा, तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिसियेटिव शुरू किया जा रहा है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे, जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा। हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले थूलो डरशीप का एक वर्ग भी तैयार होगा। मैं, अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहित्यिक कौशल का अधिक-से-अधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इससे जुड़ी जानकारियाँ शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

जानिए कौन हैं जयराम विप्लव, जिनका पीएम मोदी ने 'मन की बात' में किया जिक्र

सिद्धांत सिंह, मुंगेर

जयराम विप्लव के ट्रिवटर अकाउंट के अनुसार वे भाजपा के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं और विभिन्न चैनलों में डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रिवटर पर फॉलो भी करते हैं साथ ही यह भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेशनल एजिक्यूटिव मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 के पहले "मन की बात" कार्यक्रम में बिहार के बारे में विशेष तौर पर चर्चा की। खास तौर पर उन्होंने नमो एप पर मुंगेर के जयराम विप्लव की एक टिप्पणी का जिक्र किया। पीएम ने कहा- 'विप्लव ने लिखा कि 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने वंदे मातरम हूँ और भारत माँ की जयहूँ के नारे लगाने के कारण निर्ममता से हत्या कर दी।' पीएम मोदी ने विप्लव को धन्यवाद दिया कि वे



ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उनकी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी।

मन की बात में जिक्र आने के बाद जयराम विप्लव फिर से सुखियों में हैं। हालांकि जयराम विप्लव

मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल के धौनी गांव के जयराम विप्लव किसी पहचान के माहताज नहीं हैं। मास मीडिया यानी जनसंचार के छात्र जयराम ने ब्लॉगिंग की दुनिया को 'जनोक्ति' जैसे ब्लॉग के बाद जनोक्ति.कॉम भी बनाया है। उनको पीएम मोदी भी ट्रिवटर पर फॉलो करते हैं। जयराम के ट्रिवटर हैंडल के अनुसार वे भाजपा के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं और विभिन्न चैनलों में डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं। भारतीय युवा मोर्चा के नेशनल एजिक्यूटिव मेंबर हैं, साथ ही भाजपा के स्टडी सर्किल के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर पूर्व दिल्ली में प्रदेश सहमंत्री हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से पूरी करने के बाद अपने दिल्ली का रुख किया। जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में स्नातक का कोर्स किया था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के क्षेत्र काशी और मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर का प्रभार दिया गया था।

इंजीनियर के छात्र जॉब छोड़ कर रहे जैविक खेती



सिद्धांत सिंह, मुंगेर

देश के कई शहरों में चाइनीज वायरस (कोविड-19) की वजह से फिर से लॉकडाउन करना पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की वापसी की समस्या अभी भी बनी हुई है और उद्योगों में सुधार की रफ्तार भी अभी अपेक्षाकृत नहीं है, लेकिन भारत के बड़े क्षेत्र और उस पर निर्भर भारतीयों ने इस वायरस के दौर में भी बेहतरी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है और वह क्षेत्र है कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र। भारत के सन्दर्भ में खेती की बात होते ही हम सबके ध्यान में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वाक्य जरूर आ जाता है और यह सच भी है क्योंकि अभी भी देश की 60 प्रतिशत के आसपास जनसंख्या कृषि और उससे क्षेत्रों पर ही निर्भर है और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस क्षेत्र में किसी दूसरे देश तो छोड़िए ज्यादातर जगह किसी दूसरे क्षेत्र पर बहुत ज्यादा निर्भरता नहीं है। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चाइनीज वायरस के प्रकोप से पीड़ित भारतीयों के लिए करीब 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया तो

उसका नाम आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक पैकेज अभियान दिया। इसके साथ ही लगातार प्रधानमंत्री बोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद भारतीयों के मन में आत्मनिर्भर होने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना अच्छे से स्थापित हो गया है और जब हम आत्मनिर्भर भारत या फिर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान सबसे पहले जाता है। खेती में भी अगर जैविक और हर्बल खेती की तरफ बढ़ते हैं तो बिना किसी विशेष प्रयास के आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादों का महत्व स्पष्टता से समझ आ जाता है।

इसी क्रम तारापुर प्रखण्ड क्षेत्र के धौनी ग्राम के रहने वाले बिनीत चौधरी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर जॉब कर रहे थे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर बिहार की बातों से प्रभावित हुए तो वह अपने जॉब को छोड़कर अपने गांव धौनी आ चुके हैं। और वह जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं साथ ही वह अपने आसपास के कई युवाओं

व वरिष्ठ किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं।

वहाँ इस सम्बंध में ई. बिनीत चौधरी ने बताया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनो की बातों से प्रेरित होकर तहत मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने छोटे से गाँव में आरम्भ किया हूँ और मेरा यह संकल्प है कि पूरे बिहार में पूरे भारत में लोगों में यह संदेश जाए चाहे वह छोटे तबक के किसान हो या बड़े हो प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि आत्मनिर्भर बने अपने मेक इन इंडिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है उसी के तहत मैंने छोटे पैमाने पर जैविक खेती का आरंभ किया है और सबसे अच्छी बात यह निकलकर आती है की जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) में कम लागत में ज्यादा मुनाफा है जो आपको सफल व समृद्ध किसान बनायेगा।

किसान मदन चौधरी ने कहा मैं जैविक खेती अपने 3 एकड़ खेत में कर रहा हूँ, जिसका बहुत फायदा दिखता है। जैविक खेती से उपजाए हुए अनाज कम टूटते हैं। जैविक खेती द्वारा उगाए हुए अनाज स्वास्थ्यवर्धक है और इसमें कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिखता है सभी किसान को यह अपनाना चाहिए।

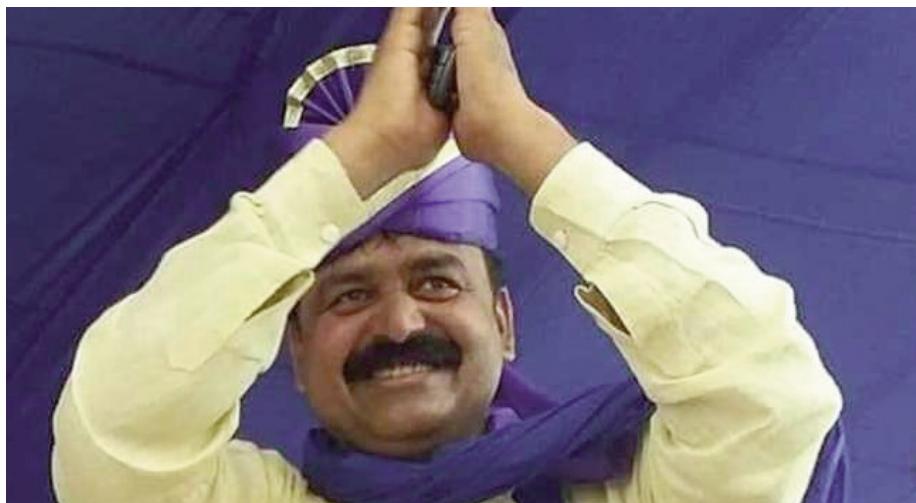
कमल पर नीतीश ने फिर लगाया निशाना !

मंत्रीमंडल विस्तार के बहाने गठबंधन में भविष्य की दण्डनीति की मजबूत

अखिलेश कुमार

पिछले मंगलवार को बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राजग गठबंधन सरकार ने मंत्रीमंडल का विस्तार किया। सरकार बनने के बाद मंत्रीमंडल विस्तार को लेकर राजग के खासकर भाजपा व जदयू के बीच लम्बी माथा पेंची के 84 दिनों बाद विस्तार का संयोग बना और इस विस्तार के माध्यम से नीतीश कुमार ने आपने राजनीतिक सुझावबुझ को एक बार फिर दिखाने में सफल रहे।

दरअसल सम्पन्न बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को काफी सीटें गंवाने पड़े। भाजपा के साथ ही प्रमुख विपक्षी दल राजद से काफी कम सीटें हासिल होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर विरोधी दल लगातार व्यंग्य कर रहे हैं, वहीं दुसरी ओर विधानसभा में सीटें कम हासिल होने के कारण राज्यसभा व विधान परिषद के अगले चुनावों में भी सीटें कम होने की चिंता होना स्वाभाविक है। इसी के तहत नीतीश कुमार ने चैनपुर से बसपा के टिकट पर निर्वाचित विधायक जमा खान और चकाई से निर्वाचित निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को अपने पक्ष में लाकर उन्हें मंत्रीमंडल में शामिल किया। उनके इस कदम से जहाँ सदन में जदयू को दो सदस्य मिल गये। वहीं दुसरी तरफ जहाँ अगले चुनाव के लिए भाजपा के चैनपुर सीट पर जदयू का दावा अभी से हीं मजबूत हो गया वहीं दुसरी तरफ काफी नाराज चल रहे अपने पुराने साथी समाजवादी नेता पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह को मनाने में भी सफल रहे। विश्वास्त सूत्र बताते हैं कि भाजपा ने मंत्रीमंडल विस्तार के लिए जो पहली सूची मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराई थी उसमें जर्मुई से भाजपा के निर्वाचित विधायक व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह का भी नाम था। भाजपा कॉम्मनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता श्रेयसी सिंह को स्टार प्रचारक के रूप में आगे बढ़ाने की मंशा रखती है। लेकिन दिग्विजय सिंह व उनके परिवार से नीतीश कुमार की राजनीतिक मतभेद जग-जाहिर है। इसलिए श्रेयसी सिंह का नाम आते ही जातीय समीकरण का हवाला देते हुए जर्मुई जिले से दो राजपूत को मंत्री बनाने पर उन्होंने आपत्ति जताई और इस सूची में बदलाव की मांग रखी। पुनः भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य बड़े नेता मुख्यमंत्री के आपत्ति को दिल्ली में केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा और अपने एजेंडा पर सफलता हासिल कर ली।



देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च, पराली के धुएं से भी मिलेगी मुक्ति

इस ट्रैक्टर से किसानों को हर साल होगी डेढ़ लाख रुपए तक की

बचत : गडकरी

बायो सीएनजी से चलने वाला देश का पहला ट्रैक्टर लॉन्च हो गया है। लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इससे ना सिर्फ किसानों को हर साल 1.5 लाख तक की बचत होगी बल्कि पराली के प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार खेतों से निकलने वाले बायो कचरे से बायो सीएनजी के निर्माण से किसानों की आमदनी दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी। सीएनजी ट्रैक्टर से होने वाले लाभ गिनाते हुए गडकरी ने कहा कि किसान हर साल लागभग 3.5 टन पराली जलाते हैं। यदि इसका बायो सीएनजी बनाने में इस्तेमाल हो तो किसानों को प्रति टन 2,000 मिलेंगे। जाहिर है इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ पराली के धुएं से भी मुक्ति मिलेगी। यदि पूरी पराली खरीद ली जाए, तो किसानों के खाते में हर साल 1500 करोड़ रुपए जाएंगे। नितिन गडकरी के अनुसार डीजल की तुलना में बायो सीएनजी से ट्रैक्टर चलाने की लागत



आधा रह जाएगी और इससे किसानों को हर साल 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारे पूरे देश में 5,000 बायो सीएनजी तैयार करने वाले प्लांट खड़ा करने की है। हर जिले में बायो सीएनजी प्लांट खुलने से किसानों को अतिरिक्त आमदनी होने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसके बावजूद यहां पर भी ऊर्जा खपत वैश्विक औसत की तिहाई है। इसलिए आने वाले समय में देश में ऊर्जा की खपत में तेजी से बढ़ोतरी होगी और स्थानीय स्तर पर तैयार वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी। नितिन गडकरी ने जिस ट्रैक्टर को लांच किया वह 7 साल पुराना उन्हीं का ट्रैक्टर है। दो स्टार्टअप कंपनियां ने इसे बायो सीएनजी के लिए रिट्रोफिट कर तैयार किया है। गडकरी के अनुसार 6 महीने की ट्रायल के बाद इसे सभी मापदंडों पर खार पाया गया। अभी किसानों के लिए अपने पुराने ट्रैक्टर को बायो सीएनजी में बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। गडकरी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही कई कंपनियां पुराने ट्रैक्टर को बायो सीएनजी में बदलने के काम में आगे आएंगे और किसान आसानी से अपने ट्रैक्टर को बायो सीएनजी में बदलवा सकेंगे।

नए कृषि कानूनों से निवेश आएगा रोजगार के अवसर पैदा होगे : धर्मेंद्र प्रधान

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नहीं कृषि कानूनों से निवेश आएगा, नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय बजट में की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए भाजपा की युवा इकाई द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपए के ग्रामीण आधारभूत विकास को से कृषि क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट बहुत मुश्किल समय में आया है जब अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। मंत्री ने जोर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों और कामगारों को सूरत बनाया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में मंत्री ने टिप्पणी की है। प्रधान ने दिल्ली भाजपा के नेताओं से झुग्गी झोपड़ी वासियों पटरी वालों बड़े बजट के प्रावधानों पर चर्चा आयोजित करने और उनके बारे में जानने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए की गई है उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक



ताकत पर निर्भर करती है और बजट में भी इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वृक्षजनों विधवाओं एवं दिव्यांग जनों के लिए वरदान साबित हो रहा है बुनियाद केंद्र



राजेश पंजिकार(ब्यूरो चीफ)



A portrait of Dr. Binita Chakrabarti, a woman with dark hair, wearing a purple patterned shawl over a white top. She is looking directly at the camera with a neutral expression.

21 फरवरी 1991 को बांका अपने जिला के अस्तित्व में आया था .तब से अब तक बांका जिले में कई अनेक प्रगतिशील योजनाएं कार्यरत होने के साथ-साथ विकसित रूप में नए-एक कार्यालयों एवं सरकारी सेवाओं, सामाजिक देखभाल हेतु कई ऐसे संस्थान बांका जिले में अवस्थित हो चुके हैं। जिससे बांका वासी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं ।इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार एवं विश्व बैंक के संयुक्त प्रयास से बांका जिले में एक बुनियाद केंद्र की स्थापना की गई है इसके तहत वृद्धजनों विधायाओं, एवं दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा सेवाओं एवं सामाजिक देखभाल की जाती है ।इसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ के द्वारा फिजियो थेरेपी की जाती है । विकलांगता और पुनर्वास संबंधी सेवाएं यहां उपलब्ध है । तथा श्रवण संबंधी जांच एवं उसके उचित निदान यहां प्रिया कुमारी द्वारा की जा रही है । आंखों की जांच नेत्र सहायक डॉक्टर गोपाल कुमार के द्वारा की जाती है ।डॉ ध्रुव कुमार गुप्ता नेत्र सहायक भी हैं । रवीश चंद्र और आरती कुमारी ,नितेश कुमार जिला लेखा अधिकारी और कैश मैनेजर के रूप में मृत्युंजय कुमार भगत अपनी सेवा बांका बुनियाद केंद्र में दे रहे ।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी नवल किशोर यादवने चर्चित बिहार को बताया की इस बुनियाद केंद्र में मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक परामर्श की भी व्यवस्था है। सामाजिक

पुनर्वास की भी व्यवस्था है। आवश्यक कानूनी परामर्श भी दी जाती है। साथ ही अस्थाई रात्रि विश्राम की व्यवस्था केवल जिला स्तर के बुनियाद केंद्रों में उपलब्ध है। इस प्रकार बांका जिले के लिए बुनियाद केंद्र वैसे लोगों के लिए जो वृद्धजन हैं दिव्यांगजन हैं एवं विधवाहैं, उसके लिए वरदान साधित हो रहा है। बुनियाद केंद्र के जिला प्रबंधक मुनमुन पाडे ने अपनी सञ्चालन और कार्यकुशलता से बुनियाद केंद्र के द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा सेवाओं वृद्धजनों दिव्यांग जनों विधवाओं के लिए दी जाने वाली सरकारी सुविधा का लाभ लाभान्वितों को स समय मिले, इसके लिए कटिबद्ध है। जिला प्रबंधक मुनमुन पाडे ने चर्चित बिहार को बताया की बुनियाद संजीवनी सेवा मोबाइल थेरेपी बेन के माध्यम से सुरू क्षेत्र, गांव स्तरीय सेवा भी इस बुनियाद केंद्र के द्वारा दी जा रही है। जिससे लाभान्वितों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार एवं विश्व बैंक के संयुक्त प्रयास से बुद्धजनों, दिव्यांग जनों, एवं विधवाओं की सामाजिक सुरक्षा सेवाओं एवं सामाजिक देखभाल का यह केंद्र है। बुनियाद केंद्र जिसमें विभिन्न तरह के सुविधाओं का लाभ लाभान्वित हों को मिलता है। खासकर विकलांगता पुनर्वास संबंधी सेवाएं, फिजियोथेरेपी भाग तथा श्रवण संबंधी जांच का उचित निदान केंद्र है। बुनियाद केंद्र बांकायाहां विकलांग लोगों के लिए टाई साइकिल का भी वितरण किया जाता है।

नवल किशोर यादव



हीरो इलेक्ट्रिक बाइक्स की एजेंसी आन्या इंटरप्राइज का हुआ शुभारंभ

पटना। बढ़ते प्रदूषण के खतरे तथा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच हीरो इलेक्ट्रिक बाइक्स के राजधानी पटना के दीघा आशियाना रोड नियर बधाई मैरिज हॉल राजीव नगर थाना के पास डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आन्या इंटरप्राइज का शुभारंभ हुआ। सरस्वती पूजा के दिन आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दानापुर से राजद विधायक रितलाल यादव शामिल हुए। उन्होंने पहले ग्राहक को स्कूटी की चाबी सौंप कर संस्थान का शुभारंभ किया। आयोजित समारोह में संस्थान के नीरज कुमार सिंह दया मिश्रा कुंदन कुमार सिंह विवेक कुमार मिश्रा एवं वंदना मिश्रा समेत हीरो इलेक्ट्रिक बाइक्स के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे आयोजित उद्घाटन समारोह में संस्थान के नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखकर हीरो ने इलेक्ट्रिक बाइक ई-रिक्षा व स्कूटी को बाजार में उतारा है जो काफी आरामदायक व साथ ही साथ लोगों के बजट के अनुसार है आन्या इंटरप्राइज के दया मिश्रा ने बताया कि प्रदूषण का खतरा भी इलेक्ट्रिक बाइक से नहीं है साथ ही साथ खर्च भी काफी कम है उनके ऐजेंसी में ई-रिक्षा इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी काफी किफायती दामों पर उपलब्ध है। यहां ग्राहकों के लिए फाइंनेंस की भी व्यवस्था है।



बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं डॉ सीपी ठाकुर

पटना। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ सीपी ठाकुर ने आज राजधानी पटना के जगन्पुरा में मिलेनियम ब्लासेज ऑफ फाइन आर्ट्स परी इंटरटेनमेंट एंड इवेंट, परी कंसल्टेंसी एंड मैनपावर सर्विसेज संस्थान का शुभारंभ किया इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख अजीत कुमार भारद्वाज और माही राज उपस्थित थे। बालाजी मल्टीकंपलेक्स न्यू जगन्पुरा बरहमपुर पेट्रोल पंप के पास कोटक महिंद्र बैंक बिल्डिंग तीसरा तला पर इस संस्थान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री डा सीपी ठाकुर ने कहा कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है केंद्र और बिहार में लोकप्रिय एनडीए की सरकार है जो युवाओं के अंदर के हुनर को निखारने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। बिहार के हुनरमंद युवा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं इस संस्थान के माध्यम से बिहार के युवाओं को हुनरमंद किया जाएगा तथा रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए इस संस्थान के निदेशकों का वे आधार व्यक्त करते हैं इससे पहले आगत अतिथि का स्वागत करते हुए संस्थान के निदेशक अजीत भारद्वाज व माही राज ने कहा कि उनके संस्थान में शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत लोकगीत व नृत्य के सभी फॉर्म की शिक्षा दी जाएगी साथ ही साथ इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी उनकी कंपनी काम करेगी। साथ ही साथ उनकी कंपनी कंसल्टेंसी फॉर मैन पावर सप्लाई के क्षेत्र में भी पदार्पण कर रही है जो



बिहार के हुनरमंद युवाओं को उनके हुनर के हिसाब से उचित मानदेव का रोजगार भी उपलब्ध करवाएगी।

समारोह में पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष

आशुतोष शर्मा बिंग गंगा चैनल से जुड़े ग्राकेश तिवारी अरनव मीडिया के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह कुमारसंभव समेत कई गणमान्य जन उपस्थित थे।

शराब माफियाओं पर नकेल कसने हेतु उत्पाद विभाग की कार्यवाही हुई तेज, रंगे हाथ दो तस्कर हुए गिरफ्तार

राजेश पंजिकार (ब्यूरो चीफ)

उत्पाद दल ने एकोरिया हाट से दो शराब तस्कर को 46 बॉटल शराब के साथ गिरफ्तार कर सुपर स्लेन्डर मोटररसाइकिल जब्त किया। गुप्त सूचना मिली थी कि कटाइ लेता (बौन्सी थाना) का मणिकांत कुमार झारखंड से शराब लेकर आ रहा है। इस सूचना पर अवर निरीक्षक मद्य निषेध प्रभात कुमार झा ने बाइक पर सवार दो लोगों को एक भरा हुआ बोरा के साथ आता देत्ह कर जांच के लिये रोकने की कोशिश की तो ये दोनों बोरा पटक कर भागने की कोशिश की पर चौकनी मद्य निषेध सिपाहीयों ने खदें कर पकर लिया। गिरफ्तार का नाम मणिकांत कुमार (कटाइ लेता) और गोपल कुमार (17 वर्ष) कोरोरिया। दोनों शराब लेकर लकरीकोला आ रहे थे। बरामद शराब का ब्रांड इम्पेरियल ब्लू का 375 एम एल का 40 बॉटल और ब्लॉकर्ड प्राइड का 750 एम एल का 6 बॉटल। गोपल कुमार को जुवेनाइल कोर्ट द्वारा बाल सुधार गृह भागलपुर और दूसरे को न्यायिक द्विरासत में भेजा गया। गोपल कुमार 17 से आरम्भ होने वाले मट्रिक का परीक्षार्थी है। रेड का नेतृत्व प्रभात कुमार झा अवर निरीक्षक मद्य निषेध ने किया।



फिल्मों में प्रयोग होती कनपुरिया लफ्फाजी

मशहूर कहावत है हँडाई कोस पास पर पानी बदले और ढाई कोस पर बाणीह यह कहावत बिल्कुल सटीक है- क्योंकि कानपुर से लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है लेकिन भाषा बिल्कुल अलग है। लखनऊ में उर्दू मिक्स अवधी बोली जाती है तो कानपुर में एकदम रौबदार कनपुरिया जो आजकल बॉलीवुड को खूब पसंद आ रही है। बहुत फिल्में बन रही हैं और न जाने कि उनमें फिल्मों की पटकथा लिख चुकी होंगी। कनपुरिया अंदाज के अक्खड़ता की वजह से यह लफ्फाजी, बोली, लोकोक्ति, मुहावरे अपना स्थान बॉलीवुड में बना रहे हैं।

कानपुर शहर दो चीजों के लिए बहुत मशहूर है इन्हें हृषीकेश-मसाला गुटखा दूसरा चमड़ा (लेटर) है आजकल कई भारतीय फिल्मों और टीवी सिरियल में कनपुरिया भाषा का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है क्योंकि इस भाषा में एक रौब और दबगई है जो भारतीय सिनेमा के महारथियों को खूब समझ में आ रही है। वो उस भाषा के साथ न्याय करने की कोशिश भी करते हैं।

शब्दों की अदायगी में एक अनूठापन है जो किसी भी दर्शक के दिल में उतरने की महारत रखती है। उसका सबसे बड़ा कारण है- यह भाषा जिस चरित्र द्वारा



बोली जाती है वो या तो फिल्म का विलेन होता है फिर उसका किरदार रौब वाला होता है।

इस भाषा में आजकल काफी फिल्में, धारावाहिक, वेब सीरीज बन रही हैं जो दर्शकों पर सीधा अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। किसी भी फिल्म की सफलता तभी है जब दर्शक बाहर निकले तो उसके दिमाग में फिल्म की कहानी हो और जुबां पर उस फिल्म के संवाद।

कनपुरिया लफ्फाजी में यह खासियत है कि उसके डायलाग दिल पर उतरते हैं इसलिए ही फिल्म निर्माता खूब कानपुर बेस फिल्मे और वेबसीरीज बना रहे हैं।

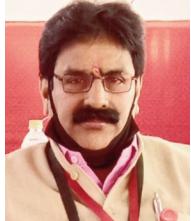
जिसमें कुछ फिल्में सिल्वर स्क्रीन पर आ भी गयी हैं जैसे एलएलबी-2, टशन, तनु वेडेस मनु-1, तनु वेडेस मनु-2, बंटी और बबली, दबंग-2, साई वर्सेज आई, कटियाबाज, देसी कट्टे, बाबर, हंसी तो फंसी, होटल मिलन, मरुधर एक्सप्रेस और भैया जी सुपरहिट उसके अलावा अनेक टीवी धारावाहिक आ गए हैं जो छोटे पर्दे पर धूम मचा रहे हैं।

कृष्णा चलौ लंदन, ह्याशास्त्री सिस्टर्स, भाबी जी घर पर हैं, लापतांज, जीजा जी छत पर हैं, हर शाख पर उल्लू बैठा है, नीली छतरी बाले, ऑफिस-ऑफिस।

ऊपर दिए गए नाम और उनके मतलब से ही आपको इस भाषा (बोली) की दबंगई का पता चल जाएगा कि किस प्रकार यह भाषा फिल्म जगत में अपना स्थान बनाये हुए है। हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा विशेष होती है जिसका इस्तेमाल करने पर पता चल जाता है कि यह किस सीमा तक दर्शक पर अपनी पैठ बना पाएगी इस बोली भाषा की शब्दावली ही निराली है कुछ शब्द और उनके अर्थ जो फिल्मों में इस्तेमाल हुए हैं।

बांका जिला विकास में पीछे नहीं रहेगा जयंत राज ग्रामीण कार्य मंत्री

राजेश पंजिकार (ब्यूरो चीफ)



अमरपुर के नवनिर्वाचित विधायक जयंत राज बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री बनाए गए, मंत्री पद संभालने के उपरांत 13 फरवरी को पहली बार बांका पहुंचे थे। इनके आगमन के निर्धारित स्थल के तहत पहले शंभूगंज पहुंचे जहां जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री महोदय का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात वे अमरपुर के लिए रवाना हुए जहां जदयू कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अमरपुर में 100 करोड़ की लागत से बायपास निर्माण कराने एवं शंभूगंज के गढ़ी मोहनपुर में बड़ुआ नदी पर 15 करोड़ की लागत से पुल पर का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जितने भी सड़क निर्माण कार्य अधूरे रह गए हैं। उसे पूर्ण कराया जाएगा मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले संवेदक बख्तों नहीं जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। इस मौके पर कई जदयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। तत्पश्चात उनके बातों का क्रम का दूसरा पड़ाव अमरपुर में हुआ जहां शहर में भव्य स्वागत किया गया। अमरपुर सीमा में प्रवेश करने पर कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं बुके देकर सम्मानित किया। इसके अलावा भर को, रामपुर अमरपुर बाजार सहित अन्य कई जगह पर लोगों ने घंटों इंजार कर स्वागत किया। मंत्री शहर स्थित कार्यालय पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले। मंत्री प्रखंड मुख्यालय स्थित सप्लाइ अशोक भवन पहुंचे। जहां अमरपुर के लोगों द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। मंत्री जयंत राजने कहा कि बांका जिला विकास में पीछे



नहीं रहेगा। जितने भी ग्रामीण सड़क हैं। उसे जरूरत के हिसाब से चौड़ीकरण के साथ-साथ इसके अंतर्गत आने वाले पुल पुलिया को भी प्राथमिकता देते हुए, निर्माण कार्य कराया जाएगा। शंभूगंज के सौहड़ा पुल सहित अन्य सड़कों का निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। जिसकी निविदा अगले माह निकाली जाएगी। अमरपुर के ग्रामीण सड़कों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और जो भी बाकी बचा है। उसका जल्द निर्माण कराया जाएगा। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र सहित समस्त बांका जिला विकास के मामले में पिछड़ा नहीं रहेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक जनार्दन मांझी द्वारिका प्रसाद मिश्र, नीपुं पांडे, वी डी ओ राकेश कुमार सी ओ स्वाति कृष्णा, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी नीलम श्वेता, मनीष कुमार संतोष करोड़िय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। तत्पश्चात उनका काफिला जिला मुख्यालय के परिसदन की ओर आगे बढ़ा बांका आगमन पर सर्वप्रथम उन्होंने गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर समस्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण किया। तत्पश्चात परिसदन में अपने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत

अभिनंदन स्वीकार करते हुए। एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता करते हुए परिसदन में मंत्री जयंत राज ने बताया कि बांका जिला का लाइफ लाइन कहे जाने वाले चांदन पुल का निर्माण शीघ्र चालू कराया जाएगा। साथ ही साथ पूर्ण बांका जिला को विकसित करने हेतु सुदूर देहात में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण बाकी है, उसे दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही साथ वृक्षरोपण कराया जाएगा। जिससे जहां राह मुसाफिरों को छाया प्राप्त होगा, वहां दूसरी ओर वृक्षरोपण से पर्यावरण भी स्वक्ष होगा। और सड़कों की आयु भी लंबी होगी। ज्ञातव्य हो कि चर्चित बिहार ने प्रेस वार्ता के क्रम में मंत्री जयंत राज को इस बात से अवगत कराया कि सड़क के दोनों ओर वृक्षरोपण कराई जाए। जिससे पर्यावरण स्वक्ष होने के साथ-साथ आवागमन करने वाले लोगों को, वृक्ष की छाया भी प्राप्त होगी। साथ ही साथ सड़क प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होगा।



राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों में तालमेल से तेज होगी विकास की दर



वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए संसद में दिनांक 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किए गए बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति की घोषणा की है। इस वर्ष राजकोषीय नीति को विस्तारवादी बनाया गया है ताकि आर्थिक विकास को गति दी जा सके। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्चों का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूंजीगत खर्चों में 34.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार विभिन्न मदों पर कुल मिलाकर 30.42 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च करने जा रही है और इस खर्चों को करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बाजार से 12 लाख करोड़ रुपए का सकल उधार लिया जाएगा। चूंकि निजी क्षेत्र अभी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने की स्थिति में नहीं है अतः अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलायमान रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अपने पूंजीगत खर्चों में भारी

भरकम वृद्धि करते हुए अपने निवेश को बढ़ा रही है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार निवेश आधारित विकास करना चाह रही है। इस सब के लिए तरलता की स्थिति को मुद्राघर एवं ब्याज की दरों को निचले स्तर पर बनाए रखना बहुत जरूरी है और यह कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से आसानी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 5 फरवरी 2021 को घोषित की गई मौद्रिक नीति के माध्यम से इसका प्रयास भी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 फरवरी 2021 को घोषित की गई मौद्रिक नीति में लगातार चौथी बार नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रुख को नरम रखा है। दिसंबर 2020 में भी आरबीआई ने नीतिगत दरों को यथावत रखा था। मार्च और मई 2020 में रेपो रेट में लगातार दो बार कटौती की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के इस एलान के बाद रेपो रेट 4 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर बनी रहेगी। रेपो रेट वह दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत

दास ने मौद्रिक नीति का एलान करते हुए कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को बरकरार रखने का फैसला किया है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जाताया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने के बाद यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की गई पहली मौद्रिक नीति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हालांकि फरवरी 2020 से अब तक रेपो रेट में 1.15 फीसदी की कटौती की है। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2021 में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संशोधित कर 5.2 प्रतिशत कर दिया है। इस मौद्रिक नीति में यह भी बताया गया है कि महंगाई की दर में कमी आई है और यह अब 6 प्रतिशत के सहित स्तर (टालरेस लेवल) से नीचे आई है। यह भी कहा गया है कि आज समय की मांग है कि अभी विकास दर को प्रोत्साहित किया जाय।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति में नरम रुख रखते हुए यह दर्शाया है कि आगे आने वाले समय में ब्याज दरों में कमी की जा सकती है। दरअसल बजट

में की गई कई घोषणाओं से भारतीय अर्थव्यवस्था में विस्तार देखने को मिलेगा, अतः तरलता को बनाए रखना आवश्यक होगा इसलिए व्याज की दरें भी कम रखनी होंगी। इस प्रकार मौद्रिक नीति अब देश की राजकीय नीति का सहयोग करती दिख रही है। मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाना एक अच्छी नीति है क्योंकि कम व्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होने से बढ़ती दरों की मांग बढ़ती है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के बाद से देश की अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर से गुज़र रही है। केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक तालमल से कार्य कर रहे हैं यह देश के हित में है। सामान्यतः खुदरा महांगाई दर के 6 प्रतिशत (टॉलरन्स रेट) से अधिक होते ही भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में बढ़ाव के बारे में सोचना शुरू कर देता है। परंतु वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए मुद्रा स्फीति के लक्ष्य में नरमी बनाए रखना जरूरी हो गया है क्योंकि देश की विकास दर में तेजी लाना अभी अधिक जरूरी है। मुद्रा स्फीति के लक्ष्य के सम्बन्ध में यह नरमी आगे आने वाले समय में भी बनाए रखी जानी चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों में विकास पर फोकस करना जरूरी है। वैसे भी खुदरा महांगाई दर 5.2 प्रतिशत ही रहने वाली है, जो सहजा स्तर से नीचे है।

दूसरे, केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारी मात्रा में बाजार से कर्ज.लेने की योजना है ताकि बजट में किए गए खर्चों सम्बन्धी वायदों को पूरा किया जा सके। इसलिए भी भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यह आवश्यक है कि मौद्रिक नीति में नरम रुख अपनाए और व्याज दरों को भी कम करने का प्रयास करे। अन्यथा की स्थिति में बजट ही फैल हो सकता है। रेपो रेट को बढ़ाना मतलब केंद्र सरकार द्वारा बाजार से उधार ली जाने वाली राशि पर अधिक व्याज का भुगतान करना। वैसे वर्तमान में तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मात्रा में तरलता उपलब्ध है।

अब तो कोरोना की बुरी आशकाएं भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं अतः व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का विश्वास भी वापिस आ रहा है। सरकार ने बजट में खर्चों को बहुत बढ़ा पुण दिया है और अब सरकार निवेश आधारित विकास करना चाहती है और इस खर्चे एवं निवेश का क्रियान्वयन केंद्र सरकार खुद लीट कर रही है। वित्तीय सिस्टम में न तो पैसे की कमी है और न व्याज की दरें बढ़ी हैं। अतः इन अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास केंद्र सरकार भी कर रही है जिसका पूरा पूरा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होने जा रहा है। सामान्यतः देश में यदि मुद्रा स्फीति सबज़ियों, फलों, आयातित तेल आदि के दामों में बढ़ातरी के कारण बढ़ती है तो रेपो रेट बढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं होता है क्योंकि रेपो रेट बढ़ने का इन कारणों से बढ़ी कीमतों को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यदि देश में मुद्रा स्फीति उक्त कारणों से बढ़ रही है तो रेपो रेट को बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत से कुछ ही अधिक उपयोग हो पा रहा है जब तक यह 75-80 प्रतिशत तक नहीं पहुंचता है तब तक निजी क्षेत्र अपना निवेश नहीं बढ़ाएगा और इस प्रकार मुद्रा स्फीति में बढ़ाव की सम्भावना भी कम ही है। मुद्रा स्फीति पर ज्यादा सख्त होने से देश की विकास दर प्रभावित होगी, जो कि देश में अभी के लिए प्राथमिकता

है। हालांकि अभी हाल ही में विनिर्माण के क्षेत्र में स्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है और यह इस वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2020) में 63.3 प्रतिशत रहा है जो पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2020) में 47.3 प्रतिशत था। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में रिकवरी और तेज हुई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को भी मदद देने की बात की गई है क्योंकि यही क्षेत्र कोरोना महामारी के दैरान सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। इन क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकतम लोग बोरोजगार हो गए थे अतः इस क्षेत्र को शून्य प्रतिशत की व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। साथ ही इस क्षेत्र को तरलता से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या न हो इस बात का ध्यान रखा जाना जरूरी है। यह क्षेत्र ही

देश की अर्थव्यवस्था को बल देगा। इसलिए भी मौद्रिक नीति में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि इस क्षेत्र को ऋण आसानी से उपलब्ध कराया जा सके एवं तरलता बनाए रखी जा सके।

देश की अर्थव्यवस्था में संरचात्मक एवं नीतिगत कई प्रकार के बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर अब भारत में दिखना शुरू हुआ है। अब तो कई अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आदि भी कहने लगे हैं कि आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में केवल भारत ही दर्हाइ के आंकड़े की विकास दर हासिल कर पाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था अब तेजी से उसी ओर बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने और केंद्र सरकार ने बजट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10/10.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेगी।

बिहार में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना गर्व की बात : अजय कुमार



स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के लिए संघर्षरत वरिष्ठ समाजसेवी तथा स्वास्थ्य एवं समग्र मानव विकास फाउंडेशन के चेयरमैन अजय कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बधाई दी है और कहा कि बिहार में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना गर्व की बात है। इसके लिए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है। अजय कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी ने किस तरह से विश्व के अधिकांश देशों में अपना प्रक्रोप सिखाया की तुलना में भारत में इसे प्रभावी ढंग से निपटा गया। इसके लिए केंद्र सरकार एवं आप की अगुवाई वाली राज्य सरकार की भूमिका काबिले तारीफ है। उन्होंने लिखा है कि आपके मार्गदर्शन में ही पूर्ण महामारी से निपटने में बिहार ने अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी प्रभावी कदम उठाए, जिसमें 500 बेड के दो कोरोना हॉस्पिटल का निर्माण भी शामिल रहा है। अजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सस्ते इलाज की व्यवस्था करें। उन्होंने पत्र में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस इटिप्पणी के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना है, जिसने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पुनर्विकास का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो बिहार की जनता के प्रति आपकी सोच को दर्शाता है। अजय कुमार ने कहा है कि यह हर बिहारी के लिए गर्व की बात है कि वह अब पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने का गैरव प्राप्त करने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद बिहार ही नहीं बल्कि देश-दुनिया भर के मरीज को इसका लाभ मिलेगा। बता दे कि समाजक कार्यकर्ता अजय कुमार लगातार डेढ़ दशक से स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने को लेकर प्रयासरत हैं और इसको लेकर लगातार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पत्राचार करते रहते हैं। नीतीश कुमार को लिखे पत्र में इस प्रयास से आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। अजय कुमार ने आगे लिखा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऐसे अस्पतलों के निर्माण के लिए आग्रह करेंगे। ताकि राज्यों के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का बातावरण तैयार हो और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं से विचित्र लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य

किसी ने सच ही कहा है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं। उनके बिना न ही हमारा वर्तमान सुरक्षित है और ना ही भविष्य की नींव रखी जा सकती है। हमारे पूर्वज ही इतिहास से भविष्य के बीच की कड़ी होते हैं। इन सबके बावजूद अफसोस की आज हम अपने पूर्वजों का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं और न ही उनकी दी हुई सीध पर अमल कर पा रहे हैं। मातृ देवों भवः, पितृ देवों भवः से अपने जीवन का आरम्भ करने वाला मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वह अपने पहले गुरु यानी माँ और पिता को ही बृद्धवस्था में दर्किनार कर देगा। इसकी कल्पना तो किसी माँ बाप ने नहीं की होगी।

चलिए अब बीते दिनों मध्यप्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर में घटिट एक घटना का जिक्र करते हैं। जिसने पूरी मानव जाति को शर्मसार कर दिया। इंदौर नगर निगम स्वच्छता में नम्बर वन बने रहने की चाहत में इतना नीचे गिर गया कि वह अपने ही शहर के बुजुर्गों को जानवरों की तरह ट्रक में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया। ऐसे में समझ नहीं आता कि कहां गई वह संस्कृति जिसमें हमें बड़े का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। भारतीय परपरा में तो पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जानवरों यहां तक की पत्थरों की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। फिर आज हमारे समाज ने अपने ही बुजुर्गों को दर दर की ठोकर खाने के लिए कैसे छोड़ दिया है। यहां चंद पक्कियां याद आ रही हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर की कृति हृकुरुक्षेत्र है से ली गई है। जिसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं है। फि र भीष्म पितामह कहते हैं कि हृधर्मराज यह भूमि किसी की, नहीं क्रीत है दासी, हैं जन्मना समान परस्पर, इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधारहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन।

अब ऐसे में अगर इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति के पास समान अधिकार है। फि र कोई सरकार या सरकारी मुलाजिम कैसे किसी को सिर्फ़ इसलिए भगा सकता व्योंकि वह बुजुर्ग और भिखारी है। व्या हम सिर्फ़ बातों में ही संस्कृति के खेवनहार बचें हैं। एक तरफ तो समाज में बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता को दर-दर भटकने के लिए छोड़ देते। ऊपर से अगर शासन-प्रशासन भी निर्लज्जता पर उतारू हो गया। फि र कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग। वैसे हम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखने वाले देश के लोग हैं। फि र आशुनिकता की दौड़ में इतना अंधे कैसे हो रहे हैं कि अपने संस्कारों को ही तिलांजिल देने पर तुले हैं। क्या यही आधुनिकता है, जिसमें अपनों का सम्मान करना ही भूल जाए? हम तो विश्वगुरु बनने की राह में आगे बढ़ रहे हैं फिर कैसे अपने जीवन के प्रथम गुरु के साथ बदसलूकी पर उत्तर आए? ये सच है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर अपनों की जिम्मेदारियों का ख्याल कैसे रखें? लेकिन जिस मां-बाप ने जन्म दिया उसकी जिम्मेदारी से मुंह तो मोड़ नहीं सकते। हम यह क्यों भूल जाते हैं



अब ऐसे में अगर इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति के पास समान अधिकार है। फि र कोई सरकार या सरकारी मुलाजिम कैसे किसी को सिर्फ़ इसलिए भगा सकता व्योंकि वह बुजुर्ग और भिखारी है। व्या हम सिर्फ़ बातों में ही संस्कृति के खेवनहार बचें हैं। एक तरफ तो समाज में बच्चे बड़े होकर अपने माता-पिता को दर-दर भटकने के लिए छोड़ देते। ऊपर से अगर शासन-प्रशासन भी निर्लज्जता पर उतारू हो गया। फि र कहाँ जाएंगे बुजुर्ग लोग।

कि जिस माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहन कर हमें इस दुनिया में जन्म दिया है। जिस पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सीखाया। जिसने हमे इस लायक बनाया की हम सही गलत का फर्क समझ सके। फि र जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की जरूरत फि र हम कैसे मुकर सकते?

एजेंबल नामक एक गैर सरकारी संगठन के सर्वों में यह बात सामने आई है कि देश में हर चौथा बुजुर्ग आदमी अकेले रहने को मजबूर है। 2018 में किए गए सर्वेक्षण की माने तो देश के 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 52 प्रतिशत बुजुर्ग पारिवारिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। 63 फीसदी बुजुर्ग स्वयं इस बात को मानते हैं कि उनका अपना ही परिवार उन्हें

बोझ मानता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद- 21 प्रत्येक मनुष्य को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। जब अपने ही इस अधिकार में बाधा बन जाए तो समाज को यह समझना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमारे समाज की यह बहुत बड़ी बिडम्बना है कि हम बेटों की चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि बेटियों को वह प्यार ही नहीं दे पाते हैं जिसकी वे असल हकदार होती है। आज भी हमारे समाज में पुरुषवादी मानसिकता भरी हुई है। हम आज भी बेटे को कुलदीपक मानते हैं। तो वही बेटियों को पराया धन मानते हैं। यही कुलदीपक अपने ही जन्मदाता को बृद्ध आश्रम छोड़ कर चले जाते हैं। उन्हें जीते जी मार डालते हैं। हमारे समाज में भेदवाव की जड़े भी समाज को खोखला कर रही हैं। जहां बेटियों को तो अपना समझा जाता है लेकिन बहुओं को वह सम्मान नहीं दिया जाता है। लोग तो यह तक भूल जाते हैं कि आज जो हमारी बहु है वह किसी ओर की बेटी भी होगी। लेकिन यही दोहरी मानसिकता समाज में कलह की सबसे प्रमुख वजह बन जाती है।

आज न केवल समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है बल्कि बुजुर्गों पर हो रहे अत्याचार पर सरकार को भी कड़े कानून बनाना चाहिए। जिससे हमारे बुजुर्ग भी सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। हमे समझना होगा कि हमारे बुजुर्ग हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज हमने उन्हें सुनने की बजाए अपनी सुनाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि आज समाज में आपाधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आज हम पुरानी इमारतों को तो सहेजकर रखना चाहते हैं, वही हमारे घर के बुजुर्गों को बेसहारा आंसू बहाने के लिए छोड़ रहे हैं। जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

जीवात्मा स्वरथ एवं बलवान शरीर को ही धारण करती है अन्य नहीं



हम जानते हैं कि सभी मनुष्यों एवं चेतन प्राणियों के शरीरों में एक चेतन आत्मा की सत्ता भी निवास करती है। मनुष्य के जन्म व गर्भकाल में आत्मा निर्माणशील शरीर में प्रविष्ट होती है। मनुष्य शरीर में आत्मा का प्रवेश अनादि, नित्य, अविनाशी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वान्तरामी, सर्वज्ञ, सच्चिदानन्दस्वरूप इश्वर कराते हैं। समस्त संसार, सभी जीवात्मायें एवं प्राणी उनके वश में होते हैं। वह अपनी व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार जीवात्मा के जन्म व उसके जीवन की व्यवस्था करते हैं। जीवात्मा एक सूक्ष्म चेतन अनादि व नित्य सत्ता है। यह अल्पज्ञ, एकदेशी, संसार, जन्म मरण धर्म तथा मनुष्य योनि में कर्म करने में स्वतन्त्र तथा अपने कर्मों का फल भोगने में परतन्त्र होती है। यदि परमात्मा जीवात्मा को उसके पूर्व जन्म के कर्मों वा प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राणी योनि (जाति), आयु और भोग प्रदान न करें तो आत्मा का अस्तित्व अपनी महत्ता को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा का यह अनादि व नित्य विधान है कि वह प्रकृति नामक सूक्ष्म, त्रिगुणों सत्त्व, रज व तम

से युक्त कणों व परमाणुओं की पूर्वावस्था से इनमें विकार उत्पन्न कर महत्त्व, अहंकार, पांच तन्मात्रायें एवं पंचमहाभूत आदि पदार्थों का निर्माण करते हैं और ऐसा करके इस स्थूल सृष्टि व जगत् सहित इसमें विद्यमान सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, नक्षत्र, ग्रह व उपग्रहों को अस्तित्व में लाते हैं। परमात्मा व जीवात्मा की भाँति प्रकृति भी अनादि तथा नित्य सत्ता व पदार्थ है। प्रकृति व आत्मा को परमात्मा बनाते नहीं हैं। परमात्मा को भी कभी किसी ने बनाया नहीं है। इन तीन पदार्थों का अनादि काल से अस्तित्व विद्यमान है और सर्वदा रहेगा। इन तीन पदार्थों में कभी किसी एक भी पदार्थ का भी अभाव नहीं होगा। विचार करने पर विदित होता है कि हमारी सृष्टि जैसी आज वर्तमान है ऐसी ही सृष्टि अनादि काल में भी रही है और भविष्य में अनन्त काल तक रहेगी। इसमें प्रलय व कल्प नाम से रात्रि व दिवस के समान अवस्थायें परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की जाती रहेंगी और हम सब अनन्त जीवात्मायें अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुए सृष्टिकाल में अपने कमार्नुसार

मनुष्य आदि नाना योनियों में जन्म लेते रहेंगे। यह सिद्धान्त व ज्ञान बेदों व वैदिक परमपराओं की समस्त संसार को महान देन है जिससे वैदिक धर्म एवं संस्कृति न केवल सबसे प्राचीन सिद्ध होती है अपितु सब धर्म, मत, पर्थों व संस्कृतियों से महान व श्रेष्ठ भी सिद्ध होती है।

संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य का जन्म माता व पिता से एक शिशु के रूप में होता है। माता के गर्भ काल में जीवात्मा पिता के शरीर से माता के शरीर में प्रविष्ट होती है। इससे पूर्व यह आत्मा संसार व आकाश में रहती है। आकाश में आने से पूर्व यह अपने पूर्वजन्म में किसी प्राणी योनि में रहती है जो मनुष्य व अन्य कोई भी योनि हो सकती है। परमात्मा जीवात्मा को प्रेरणा कर उसे गति प्रदान करते हैं व उसके योग्य पिता के शरीर में प्रविष्ट कराते हैं जहां से वह माता के गर्भ में प्रविष्ट होती है। दस मह तक माता के गर्भ में जीवात्मा का बालक व कन्या का शरीर बनता है और इसके बनने पर जन्म होता है। जन्म होने के बाद माता के दुग्ध व समय समय

पर अन्य पदार्थों के सेवन से शरीर में वृद्धि होती है। समय के साथ शरीर बढ़ता व वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। बालक इस अवधि में माता की भाषा को बोलना सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों को पहचानता है और उन्हें सम्बन्ध सूचक दादा, दादी, पिता, माता, बुआ, चाचा, चाची आदि शब्दों से सम्बोधित भी करने लगता है। हम देखते हैं कि मनुष्य का आत्मा शरीर वृद्धि की अवस्था सहित युवावस्था में तथा बाद में भी जब तक वह स्वस्थ रहता है शरीर में सुख पूर्वक निवास करता है। स्वस्थ, निरोग तथा बलवान शरीर का सुख उत्तम सुख होता है। निरोगी काया को सुखी जीवन का आधार बताया जाता है। युवावस्था व्यतीत हो जाने पर मनुष्य के शरीर में उसके पूर्वकाल के किये भोजन, निद्रा की कमी व अधिकता, व्यायाम व अनियमित जीवन आदि के कारण कुछ विकार होने से रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इन रोगों के कारण शरीर का बल घटता है। अस्वस्थ शरीर में आत्मा को कष्टों का अनुभव होता है। इन्हें दूर करने के लिए चिकित्सा, ओषधियों सहित भोजन छादन, व्यायाम, प्राणायाम, तप, सत्य कार्यों का सेवन, ईश्वरोपासना, अग्निहोत्र यज्ञ, माता-पिता तथा वृद्धों की सेवा, अतिथि सत्कार आदि पर ध्यान देना होता है। ऐसा करके हम अधिक समय व कालावधि तक मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं।

पचास व साठ वर्ष के बाद हम मनुष्य के शरीर में अस्वस्थता व बल की कमी का होना अनुभव करते हैं। ऐसे समय में कुछ रोग भी अधिकांश मनुष्यों में होना आरम्भ हो जाते हैं। आजकल रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा आदि रोग बहुतायत में देखे जाते हैं। इन रोगों से मनुष्य के शरीर में बल की कमी आती है। आयु बढ़ने के साथ शरीर का भार भी कम हो जाता है। चेहरे पर पहले जैसी सुन्दरता व रौनक नहीं रहती। धीरे धीरे शरीर में रोगों की तीव्रता में वृद्धि देखने को मिलती है। सत्तर व उससे अधिक आयु में रोगों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाता है। ऐसे समय व परिस्थिति में मनुष्य को अपने दैनिक कर्तव्य पूरे करने में भी कुछ कुछ बाधायें आना आरम्भ हो जाती है। जो मनुष्य इस आयु में भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं वह भाग्यशाली होते हैं। इसका कारण उनका आरम्भ की अवस्था से संयम तथा नियमित जीवन जीना होता है। ऐसे लोगों ने आरम्भ से ही स्वास्थ्य के नियमों का पालन किया होता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने जीवन के आरम्भकाल में जो संयम, शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, समय पर सोना व जागना, शुद्ध व पवित्र विचार, स्वस्थ चिन्तन व दृष्टिकोण रखना तथा स्वास्थ्य के अन्य नियमों का पालन किया होता है, उनका स्वास्थ्य उन्हीं कार्यों का परिणाम होता है। जो मनुष्य पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं, उन्हें नाना प्रकार के शारीरिक कष्ट सताते हैं। इससे आत्मा में क्लेश होता है। आजकल देश में एलोपैथी, अस्पतालों एवं सभी पद्धति के चिकित्सकों की अधिकता है। लोग उपचार के लिए प्रायः एलोपैथी का चुनाव करते हैं जो अत्यधिक खर्चीली होती है। रक्तचाप, हुद्दा, मधुमेह, मोटापा व अन्य कुछ रोग इन एलोपैथी उपचार पद्धति से पूर्णतया तो किसी के भी ठीक नहीं होते अपितु अत्यधिक दवाओं के सेवन से भी शरीर अधिक दुर्बल होता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि शरीर पर मनुष्य का पूर्ण नियन्त्रण नहीं रहता और नाना प्रकार की कठिनाईयों का अनुभव होता है। ऐसा होते हुए ही मनुष्य



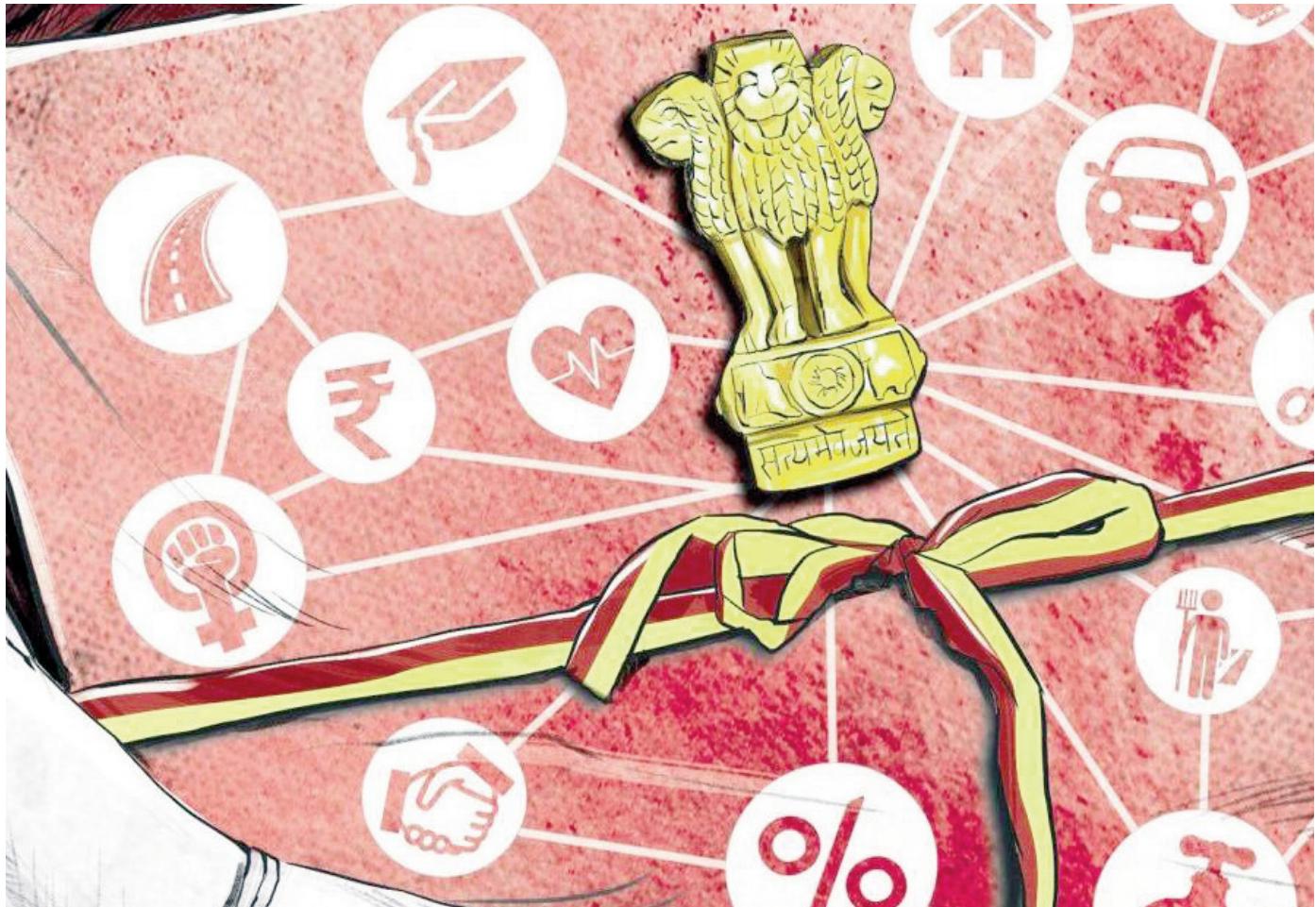
पचास व साठ वर्ष के बाद हम मनुष्य के शरीर में अस्वस्थता व बल की कमी का होना अनुभव करते हैं। ऐसे समय में कुछ रोग भी अधिकांश मनुष्यों में होना आरम्भ हो जाते हैं। आजकल रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा आदि रोग बहुतायत में देखे जाते हैं। इन रोगों से मनुष्य के शरीर में बल की कमी आती है। आयु बढ़ने के साथ शरीर का भार भी कम हो जाता है। चेहरे पर पहले जैसी सुन्दरता व रौनक नहीं रहती। धीरे धीरे शरीर में रोगों की तीव्रता में वृद्धि देखने को मिलती है। सत्तर व उससे अधिक आयु में रोगों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाता है।

का अन्तिम समय आ जाता है और वह अस्पतालों व घरों में मृत्यु का शिकार हो जाता है। किसी मनुष्य की मृत्यु का मूल्यांकन करते हैं तो यही ज्ञात होता है कि रोग, अस्वस्थता व निर्बलता ही मनुष्य की मृत्यु का कारण हुआ करती है। हमें जीवन में निरोग व स्वस्थ रहने के सभी उपायों व साधनों का सेवन करना चाहिये। इसके लिये हमें अपने ऋषियों के ज्ञान आयुर्वेद एवं वैदिक जीवन पद्धति को अपनाना चाहिये। ऐसा करने से हम स्वस्थ जीवन व लम्बी आयु को प्राप्त हो सकते हैं और बलवान होने से हमें कष्ट भी कम होते हैं व उन्हें सहन करने की अधिक शक्ति उपलब्ध होती है।

यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि स्वस्थ एवं बलवान शरीर में ही मनुष्य की आत्मा निवास करती है और जब तक वह स्वस्थ रहता है उसकी मृत्यु उससे दूर रहती

है। इस सिद्धान्त को जानकर हमें अपने जीवन में, हम जीवन की जिस अवस्था में भी हों, वही से स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन करना आरम्भ कर देना चाहिये। रोगों को दूर करने के उपाय करने चाहियें और स्वस्थ कैसे रहें, इस पर चिन्तन करते हुए उसके लिए आवश्यक साधनों को अपनाना चाहिये। भोजन पर हमारा पूरा नियन्त्रण होना चाहिये। हानिकारक पदार्थ फास्ट फूड, तले व बासी पदार्थों का सेवन न करें तो अच्छा है। इनका पूर्णरूप से त्वाय करना ही भविष्य में स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का आधार हो सकता है। हमें वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार प्रातः: 4 से 5 बजे तक जाग जाना चाहिये और नियमित शौच के बाद वायु सेवन व भ्रमण, स्नान, ईश्वरोपासना व अग्निहोत्र, माता-पिता आदि वृद्ध परिवार जनों की सेवा आदि कार्यों को करना चाहिये। स्वास्थ्य में प्रमाद नहीं करना चाहिये। स्वास्थ्य में हम सत्त्वार्थप्रकाश का प्रथम अध्ययन पूरा करें। इससे हमें इसके बाद अन्य किन किन ग्रन्थों का अध्ययन करना है, उसकी प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम उपनिषदों, दर्शनों तथा वेद वा वेदभाष्य का भी अध्ययन कर सकते हैं। उनके मध्य व बाद में हम बाल्मीकि रामायण तथा संक्षिप्त महाभारत का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऋषि दयानन्द तथा अन्य महापुरुषों के जीवन चरित्रों का अध्ययन भी हमें करना चाहिये। हमें अपना ध्यान स्वास्थ्य के नियमों पर केन्द्रित रखना चाहिये और वैदिक जीवन पद्धति को अपनाना चाहिये क्योंकि वैदिक जीवन पद्धति ही संसार में श्रेष्ठ पद्धति है। हमारे आचार, विचार, चिन्तन व हमारा जीवन शुद्ध व पवित्र होना चाहिये। इस जीवन पद्धति को अपनाकर ही हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष प्राप्त होते हैं। हमारा जीवन महर्षि दयानन्द के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर जीने से ही सफल होगा, ऐसा हम अनुभव करते हैं। ओ३३३ शम।

केंद्रीय बजट 2021-22 : चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला बजट



मनोज कुमार सिंह

कोरोना महामारी से संघर्ष के दौर में वर्ष 2021-22 का केन्द्रीय बजट आया है। बजट आने के बाद लाभ-हानि जैसे सवालों पर चर्चा हो रही है। लेकिन, इससे पहले यह विचारना जरूरी है कि जब इस साल का बजट सामने आया है, उस समय देश किस हालात से गुजर रहा है? यदि इस नजरिये के साथ बजट को देखेंगे, तो स्पष्ट होगा कि केन्द्रीय बजट में ह्याजान और जहानाह दोनों की चिंता की गयी है। अर्थव्यवस्था में मंदी, अर्थव्यवस्था पर कोविड के कुप्रभाव और व्यापक आर्थिक संतुलन बनाए रखने सहित कई तरह की चुनौतियों के बीच आप बजट पेश किया गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तमंत्री ने बजट में कई सार्थक प्रस्ताव रखे हैं। सरकार ने लीक से हटकर फैसले लेने का साहस दिखाया है। बजट में कोई नया कर नहीं लगाते हुए ह्यास्वस्थ भारत और मजबूत

बुनियाद के बूते अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला संकल्प परिलक्षित होता है। इसलिए, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ देश को आशा की ओर ले जानेवाला बजट करार दिया जा सकता है। सरकार ने बजट प्रस्तावों के माध्यम से सभी पहलुओं को अपने व्यापक व सर्वसमावेशी दृष्टिकोण में समेटने व उन्हें लाभान्वित करने की सकारात्मक पहल की है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया है। कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के खर्चों का यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया, जब देश की आजादी के बाद भारत पहली बार आधिकारिक तौर पर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बजट में सरकार द्वारा ह्यात्मनिर्भर भारतल पर फोकस करने के अलावा मानव पूंजी नवजीवन, संचार, स्वास्थ्य, कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त वर्ष 2021 में 9.5 फीसदी के राजकोषीय घाटे का आकलन किया गया है, जिसमें बजट सब्सिडी भी शामिल है। पिछले बजट में 2.28 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी की तुलना में इस बार के बजट में सब्सिडी के मोर्चे पर 5.95 लाख करोड़ रुपये हैं। बजट में भारी-भरकम सब्सिडी का प्रावधान रखने से राजकोषीय घाटे का इस सीमा तक पहुंचना स्वाभाविक है। राजकोषीय

का जोखिम नहीं उठाया है, बल्कि हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ साथ कृषि क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। इस बजट में नई योजनाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। बजट में सरकार ने कंजूसी नहीं दिखाई है, बल्कि विकास को तेजी देने के लिए खर्च करने पर जोर दिया है। इसके जरिये सरकार ने उद्योग और अर्थव्यवस्था में तेजी का पश्चात्र होने का संदेश दिया है। अच्छी बात है कि सरकार, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचों पर खर्च करने की एक विस्तारवादी विकास नीति बना रही है। वित्त वर्ष 2021 में 9.5 फीसदी के राजकोषीय घाटे का आकलन किया गया है, जिसमें बजट सब्सिडी भी शामिल है। पिछले बजट में 2.28 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी की तुलना में इस बार के बजट में सब्सिडी के मोर्चे पर 5.95 लाख करोड़ रुपये हैं। बजट में भारी-भरकम सब्सिडी का प्रावधान रखने से राजकोषीय घाटे का इस सीमा तक पहुंचना स्वाभाविक है। राजकोषीय

घाटे को वित्त वर्ष 2022 में कमतर करने का लक्ष्य है। देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत सुधारने और उसे मजबूत बनाने के लिए आम बजट में 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। भारत में बनी न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो अभी सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित है, इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इससे वर्षभर में 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत को रोका जा सकेगा। वहीं, कोविड के लिए पैंतीस हजार करोड़ आवंटन के साथ इस वर्ष स्वास्थ्य पर खर्च में 137 फीसदी की बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि देश के हर नागरिक को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध कराने को जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरूआत होगी, जिसको 2021-26 तक (5 वर्ष की) अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा। इनकास्टकर खर्च को 4.39 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.4 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है।

13 प्रमुख उद्योग क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करना और कई वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क बढ़ाना स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सड़क, परिवहन, रेलवे तथा ऊर्जा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में 37 फीसदी ज्यादा बजट देने की घोषणा की गई है। मेंढ़ी और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की क्षमता में सुधार से विकास में योगदान होगा। रेलवे के लिए

बजट में 1,10,055 करोड़ का प्रावधान है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 14 हजार करोड़ की राशि आवंटित हुई है और नाबार्ड के तहत उपलब्ध राशि को दोगुना करके 5000 करोड़ की वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में कृषि कर्ज का लक्ष्य इस वर्ष 16.5 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। साथ ही सरकार ने हाँऑपरेशन ग्रीन स्कीम मळ की भी घोषणा की है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस क्षेत्र में 15.7 लाख करोड़ रुपये की बड़ी राशि आरक्षित करने की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के तहत देश की जीडीपी की 13 फीसदी राशि ऐसी योजनाओं पर खर्च करने की घोषणा हुई है। पेट्रोल पर 2.50 और डीजल पर 4 रुपये कृषि सेस लगाया गया है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टार्टअप को टैक्स देने में जो शुरूआती छूट दी गई थी, उसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा अन्य त्रैण समर्थन योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 12499.70 करोड़ रुपये किया गया है। चीन सीमा पर गतिरोध के बीच रक्षा बजट में 25 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें 20776 करोड़ आधुनिकीकरण के मद में बढ़ाए गए हैं। नए बजट प्रस्तावों के मुताबिक रिसाईकिलिंग कैपेसिटी को 2024 तक दोगुना करने की घोषणा की गयी है। इससे युवाओं के लिए 1.5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। वहीं, 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का

टैक्स कम किया गया है। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गयी है। वित्तमंत्री के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.8 फीसदी था, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसके घटकर 6.8 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। जबकि, विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना जातीय गयी है। इस बार के बजट में सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए विनिवेश और निजीकरण पर जोर दिया है। इस साल 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का एलान किया गया है। विष्की दल इसे हावेश को बेचनाह कह रहे हैं। लेकिन, वास्तव में वैसे ही संस्थान बेचे जाएंगे, जो निष्क्रिय हैं, नुकसानदेह हैं और जिन्हें चलाने में सरकार असमर्थ है। सरकार यह सब नहीं करती और आम नागरिकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों की बौछार कर देती, तो क्या ठीक होता? कुल मिलाकर देखा जाये तो केन्द्रीय बजट में सरकार का फोकस बुनियादी संरचना पर निवेश बढ़ाने को लेकर रहा है और आर्थिक विकास को गति देने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। देश के स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाते हुए और कोविड-19 के नकारात्मक असर से निकलने के लिए जिस तरह की विकासोन्मुखी बजट की जरूरत थी, यह बजट उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बजट प्रावधानों का स्पष्ट संकेत है कि सबका समग्र विकास करने के मंसूबे के साथ सरकार ने सबका विश्वास हासिल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)



स्वच्छ हवा में सांस लेने का हकदार है बचपन



प्रदूषण एक ऐसी वैश्विक समस्या बन चुका है, जिससे दुनियाभर में अनेक तरह की खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं और लाखों लोग हर साल असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं। भारत में भी वायु प्रदूषण का प्रभाव खतरनाक रूप से पड़ रहा है। देश में और खासकर उत्तर भारत में पराली जलाने तथा कई अन्य इंसानी कारकों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर इन दिनों खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कमोवेश सर्वियों की शुरूआत के समय हर साल वायु प्रदूषण के कारण ऐसे ही चिंताजनक हालात देखने को मिलते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण की ऐसी ही एक भयावह रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण जहां पूरी दुनिया में 4.76 लाख बच्चों की मौत हुई, वहीं अकेले भारत में ही एक महीने से भी कम आयु के 1.16 लाख नवजातों की मौत वायु प्रदूषण की वजह से हो गई। हालांकि नवजात शिशुओं की अधिकांश मौतें जन्म के समय कम बजन और समय से पहले जन्म से संबंधित जटिलताओं के कारण हुई लेकिन वायु प्रदूषण अब नवजातों की मौतों का दूसरा सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, यह स्थिति बहद चिंताजनक है।

अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन ह्यूल्स्ट

इफैक्टस इंस्टीट्यूटल (एचईआई) द्वारा 21 अक्टूबर को वायु प्रदूषण के दुनिया पर असर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि भारत में स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। ह्यास्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 नामक इस वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बाहरी और घेरेलू वायु प्रदूषण के लंबे समय के प्रभाव के कारण 2019 में स्ट्रोक, दिल के दौरे, डायबिटीज, फेफड़े के कैंसर, पुरानी फेफड़ों की बीमारियों और नवजात रोगों के कारण ये मौतें हुईं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें आधी से भी ज्यादा मौतें का संबंध बाहरी पीएम 2.5 प्रदूषक तत्व से है जबकि बाकी मौतें कोयला, लकड़ी और गोबर से बने ठोस ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़ी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण अब मौत के लिए सबसे बड़े खतरे वाला कारक बन गया है और नए विशेषण में अनुमान जताया गया है कि नवजातों में 21 पीसदी मौत का कारण घर और आसपास का वायु प्रदूषण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी वर्ष 2018 में ह्याएयर पोल्यूशन एंड चाइल्ड हैल्थल नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2016 में दुनियाभर में पांच वर्ष से कम आयु के छह

लाख बच्चों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण हुई थी और उनमें से एक लाख से भी अधिक बच्चे भारत के ही थे। वायु प्रदूषण के कारण नवजात शिशुओं की सर्वाधिक मौतें अप्रीका तथा एशिया में होती हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में करीब नब्बे पीसदी बच्चे, जिनकी कुल संख्या लगभग 1.8 अरब है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो स्थिति और भी खराब है, जहां करीब 98 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक प्रदृष्टि माहील में रहते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी विश्वभर में करीब दो अरब बच्चे खतरनाक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें से 6.2 करोड़ दक्षिण एशियाई देशों में हैं। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित मेरी हायप्रूषण मुक्त सांसेंह पुस्तक में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि वायु प्रदूषण से बच्चों के मस्तिष्क और दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जून 2018 में यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि भारत में लगभग सभी स्थानों पर वायु प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक है, जिससे बच्चे सांस, दमा तथा फेफड़ों से संबंधित बीमारियों और अल्प विकसित मस्तिष्क के शिकार हो रहे हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की



मृत्यु में से दस फीसदी से अधिक की मौत वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली सांस संबंधी बीमारियों के कारण होती हैं।

एचईआई (हैल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट) के अध्यक्ष डैन ग्रीनबाम का कहना है कि किसी नवजात का स्वास्थ्य किसी भी समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इन नए साक्षणों से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में नवजातों को होने वाले अधिक खतरे का पता चलता है। ह्यस्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020ल रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी वायु प्रदूषण का घातक असर पड़ता है। इससे समय से पूर्व प्रसव या फिर कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं और ये दोनों ही शिशुओं में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण एवं प्रदूषण पर लिखी पुस्तक ह्याप्रदूषण मुक्त सासेंल के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे अगर बच भी जाते हैं, तब भी उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है। वायु प्रदूषण से नवजातों की मौतों में से दो तिहाई मौतों का कारण घरों के अंदर का प्रदूषण है। विश्व स्तर पर वाहनों से उत्पन्न गैसों और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन पर तो बहुत चर्चा होती है लेकिन घरों के अंदर के प्रदूषण के स्रोतों पर अक्सर कोई चर्चा नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के मुताबिक खाना पकाने, साफ-सफाई तथा घर के अन्य सामान्य कामकाजों के दौरान पार्टिकुलेट मैटर और वोलाटाइल आर्गेनिक कंपाउंड्स (बीओसी) उत्पन्न होते हैं, जो प्रदूषण के कारक बनते हैं। पार्टिकुलेट मैटर खाना पकाने और साफ-सफाई के दौरान उत्पन्न होते हैं।

एचईआई (हैल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट) के अध्यक्ष डैन ग्रीनबाम का कहना है कि किसी नवजात का स्वास्थ्य किसी भी समाज के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और इन नए साक्षणों से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में नवजातों को होने वाले अधिक खतरे का पता चलता है। ह्यस्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020ल रिपोर्ट के मुताबिक गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी वायु प्रदूषण का घातक असर पड़ता है। इससे समय से पूर्व प्रसव या फिर कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं और ये दोनों ही शिशुओं में मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। पर्यावरण एवं प्रदूषण पर लिखी पुस्तक ह्याप्रदूषण मुक्त सासेंल के अनुसार अत्यधिक प्रदूषण में पलने वाले बच्चे अगर बच भी जाते हैं, तब भी उनका बचपन अनेक रोगों से घिरा रहता है। वायु प्रदूषण से नवजातों की मौतों में से दो तिहाई मौतों का कारण घरों के अंदर का प्रदूषण है। विश्व स्तर पर वाहनों से उत्पन्न गैसों और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन पर तो बहुत चर्चा होती है लेकिन घरों के अंदर के प्रदूषण के स्रोतों पर अक्सर कोई चर्चा नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के वैज्ञानिकों के मुताबिक खाना पकाने, साफ-सफाई तथा घर के अन्य सामान्य कामकाजों के दौरान पार्टिकुलेट मैटर और वोलाटाइल आर्गेनिक कंपाउंड्स (बीओसी) उत्पन्न होते हैं, जो प्रदूषण के कारक बनते हैं। पार्टिकुलेट मैटर खाना पकाने और साफ-सफाई के दौरान उत्पन्न होते हैं।

जबकि शैम्पू, परफ्यूम, रसोई और सफाई वाले घोल बीओसी के प्रमुख स्रोत हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस प्रकार के तत्व विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अलावा कैंसरकारक भी होते हैं।

घरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते दुष्प्रभावों का सबसे बड़ा कारण आजकल अधिकांश घरों में विभिन्न घरेलू कार्यों में तरह-तरह के रसायनों का बढ़ता उपयोग माना जा रहा है। ऐसे ही रसायनयुक्त पदार्थों के बढ़ते चलन के ही कारण घरों के अंदर फॉर्मेल्डाइइड, बेंजीन, एल्कोहल, कीटोन जैसे कैंसरजनक हानिकारक रसायनों की सांदर्भ बढ़ जा रही है, जिनका बच्चों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों में ये तथ्य सामने आ चुके हैं कि घरों के भीतर का प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण बच्चे मंदबुद्धि हो रहे हैं, जन्म के समय कम वजन के बच्चे पैदा हो रहे हैं। गर्भ में भी बच्चे वायु प्रदूषण के प्रभाव से अछूते नहीं हैं, उनका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, उनमें दमा और हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं और वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों बच्चों की मौत वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के कारण हो रही हैं। बहरहाल, वायु प्रदूषण के बच्चों पर पड़ते दुष्प्रभावों और हर साल वायु प्रदूषण के कारण हो रही लाखों बच्चों की मौतों को लेकर पूरी दुनिया को अब संजीदगी से इस पर विचार मंथन करने और ऐसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है, जिससे मासूम बचपन प्रदूषण का इस कदर शिकार न बने।

पॉक्सो की त्याख्या बनाम न्याय-प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न



बाँधे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा पिछले दिनों 2016 में दर्ज एक मामले में दिए गए निर्णय ने न सिर्फ संबंधित न्यायाधीश की न्यायिक समझ; बल्कि पूरी की पूरी न्याय-प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपने इस अत्यंत विवादस्पद और असंवेदनशील निर्णय में नागपुर एकल पीठ की न्यायमूर्ति पुष्ण गणेशीवाला ने पॉक्सो एकट को पुनर्परिभाषित करते हुए उसकी बहुत सीमित और प्रतिगामी व्याख्या की है। उन्होंने 12 वर्षीय एक बच्ची पर हुए यौन हमले के लिए नागपुर सत्र न्यायालय द्वारा पॉक्सो एकट के तहत दोषी ठहराए गए 39 वर्षीय व्यक्ति सतीश बंधु रागड़े को इस अपराध-मुक्त करते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला के जबरन शीलभंग) के अंतर्गत दोषी ठहराया हैक उन्होंने पॉक्सो एकट लागू करने के लिए यौन मंशा के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क की अनिवार्यता को अपने इस निर्णय का आधार बनाया हैक उनके अनुसार चूँकि घटना के समय बच्ची ने टॉप पहना हुआ था, इसलिए आरोपित द्वारा उसके वक्षस्थल को ढाबाने के बावजूद पॉक्सो एकट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आरोपित ने बच्ची का शारीरिक स्पर्श नहीं किया था। यह निर्णय पॉक्सो एकट की सीमित समझ और इस कानून में अन्तर्निहित भावना

की ओर उपेक्षा का परिणाम है। पॉक्सो एकट की यह परिभाषा इस अर्थ में विशेष रूप से खतरनाक और परेशान करने वाली है कि बच्चों पर हाने वाले यौन हमलों से सम्बंधित मामलों में निचली अदालतों के लिए भविष्य में एक उदाहरण बन सकती हैक यह परिभाषा इसलिए भी बेचैन करती है क्योंकि यह उत्पीड़ित के संरक्षण की जगह उत्पीड़क को संरक्षण प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अपराध के लिए पॉक्सो एकट के अनुभाग 8 के तहत 3 साल कारावास की सजा दी गयी थी, जबकि भा द सं की धारा 354 के अंतर्गत मात्र एक वर्ष के कारावास की ही सजा दी गयी हैक गैरतलब यह भी है की नागपुर सत्र न्यायालय द्वारा भी जाने-अनजाने एक महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी की गयीकृघटना के समय पीड़िता बच्ची की आयु 12 वर्ष से कम थी, इसलिए आरोपित को पॉक्सो एकट के अनुभाग 9 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाना चाहिए था। अनुभाग 9 के अंतर्गत दोषसिद्ध होने पर न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान हैक ये निर्णय न्याय-व्यवस्था और न्यायिक-प्रक्रिया की सीमाओं को भी उजागर करते हैं। इसलिए बार-बार न्याय-व्यवस्था के सुधार और न्यायिक-प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील, समयबद्ध और जवाबदेह बनाये जाने की माँग उठती रहती है।

इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के माध्यम से तुरंत हस्तक्षेप किया और उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करते हुए इस प्रतिगामी निर्णय पर रोक लगाकर इसकी समीक्षा की माँग कीक भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने इस निर्णय पर रोक लगा दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ इस निर्णय के खिलाफ याचिका दायर करने की अनुमति दी है बल्कि महाराष्ट्र सरकार और आरोपित को दो सप्ताह बाद होने वाली अगली सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया जाना स्वागत योग्य हैक इस असावधानीपूर्वक दिए गए अपरिपक्व निर्णय से गलत नजीर कायम होने की आशंका पैदा हो गयी थी। इसलिए इस गलती को ठीक किया जाना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बाल विरोधी इस निर्णय के खिलाफ उच्चतर पीठ में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस निर्णय के खिलाफ मुखर है।

तमाम बाल अधिकार संरक्षण और महिला

POCSO ACT



अधिकार संगठनों के लम्बे संघर्ष और प्रयासों के परिणामस्वरूप सन 2012 में प्रोटोकशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स (पॉक्सो) एक्ट लागू किया गया था। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के मासूमों को यौन उत्पीड़न से बचाने हेतु बनाया गया था। इस कानून में बालक-बालिका दोनों को ही संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, बच्चों की मासूमियत और असुरक्षा के महेनजर उनके यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों के लिए सामान्य से अधिक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। पॉक्सो एक्ट के अनुभाग 7 के तहत जब कोई व्यक्ति यौन मंशा के साथ बच्ची/बच्चे के गुसांगों या वक्ष को छूता है या बच्ची/बच्चे से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के गुसांगों को स्पर्श करता है या यौन मंशा के साथ कोई अन्य कृत्य करता/करता है, जिसमें सम्भोग किये बगैर यौन मंशा से शारीरिक संपर्क शामिल हो, उसे यौन हमला/उत्पीड़न कहा जाता है। न्यायाधीश महोदया ने इसी अनुभाग की व्याख्या करते हुए शारीरिक संपर्क के लिए त्वचा से त्वचा के संपर्क की अनिवार्यता पर बल दिया हैक इस समस्यापूर्ण व्याख्या के अनुसार तो दस्ताने, अंडरवीयर या कंडोम पहनकर किये जाने वाला यौन उत्पीड़न भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। सन 2018 में संशोधित इस कानून में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ दुष्कर्म/बलात्कार के दोषी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान जोड़ा गया है। हालाँकि, मृत्युदंड के इस प्रावधान के बारे में बाल संरक्षण और महिला अधिकारों के लिए कार्यरत विभिन्न सामाजिक कार्यकार्ताओं और संगठनों में सहमति नहीं है। इससे असहमत लोगों का मत यह है कि इस प्रावधान से यौन अपराधियों द्वारा बच्चों की हत्या की सम्भावना बढ़ जाएगी क्योंकि सजा को बहुत अधिक सख्त करने की जगह जाँच प्रक्रिया और न्याय-व्यवस्था को दुरुस्त करने की कहीं अधिक

आवश्यकता है। इन दोनों की खामी की वजह से ही न सिर्फ न्याय मिलने में देरी होती है, बल्कि दोषिसंदिक की दर भी निराशाजनक रूप से अत्यंत कम है।

यह कानून नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न/हमले, पोर्नोग्राफी आदि से संरक्षण प्रदान करने के लिए अस्तित्व में आया थाक निश्चय ही, कोई भी कानून अपराधों की रोकथाम और समस्या के समाधान का एकमात्र तरीका नहीं है, बल्कि एक तरीका मात्र हैक अपराध के लिए समूचित और समयबद्ध दंड का प्रावधान न्यायप्रिय और लोकतान्त्रिक समाजों का आधारभूत लक्षण है। जब अपराधी को दंड नहीं मिलता और उत्पीड़ित को समूचित और समयबद्ध न्याय नहीं मिलता तो सामाजिक ढांचा जर्जर होने लगता है। समाज में जंगलराज कायम हो जाता है और अराजकता और अंधेरादी बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि न्याय मिलने में देरी न्याय न मिलने के समान हैक इसमें यह जोड़ने की भी आवश्यकता है कि अपराध के अनुपात में दंड न मिलना भी न्याय न मिलने जैसा ही है। कानून बनाना मात्र समस्या का समाधान नहीं है, कानून का उसकी भावना के अनुरूप समयबद्ध क्रियान्वयन भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे न होने से न्याय-व्यवस्था जैसी संस्थाओं के प्रति सामाजिक विश्वास की नींव हिलने लगती है।

भारत में न्याय की प्रतीक्षा कभी न खत्म होने वाली प्रतीक्षा हैक अपराधी से ज्यादा शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण उत्पीड़ित का होता हैक दोवानी मामलों को तो छोड़ ही दीजिये, अब तो फौजदारी मामलों के निपटारे में भी पीटियां गुजर जाती हैक भारत की विलंबित न्यायिक-प्रक्रिया वैटिंग फॉर गोदा जैसी हो गयी है। जिला एवं सत्र न्यायालयों से लेकर उच्च और उच्चतम न्यायालयों तक लंबित मामलों की संख्या लाखों में है, पर लंबित मामलों के

समयबद्ध निपटारे के लिए कहीं कोई गंभीर पहल या हलचल नहीं दिखाई देती है। बदलाव या सुधार के लिए कहीं कोई आत्म-मंथन नहीं करता दिखता। खादी और खाकीपोश अपराधियों की बढ़ती संख्या के अनुपात में ही भारतीय न्याय-व्यवस्था से आम भारतीय का भरोसा घटता जा रहा है। अब न्यायालय से न्याय प्राप्त करना उसकी पहली प्राथमिकता न होकर निरुपाय का अंतिम शरण्य है। न्यायालयों को लेकर आम भारतीय की मन-स्थिति हारे को हरिनाम जैसी है। भारत के अधिकांश उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जिस अंग्रेजी भाषा में फैसले सुनाये जाते हैं, वह देश की 95 फीसद जनता के लिए अबूझ पहली है। भारत की न्याय-व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुयी है। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में न्यायमूर्तियों की चयन-प्रक्रिया को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैक इन न्यायालयों में न्यायाधीशों का चयन उच्चतम न्यायालय के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम करता है। यह व्यवस्था अत्यंत आंतरिक, अपवर्जी, असमावेशी और गोपन हैक इसपर पारदर्शिता और जवाबदही के अभाव और पेशेवर योग्यता की उपेक्षा के आरोप गाहे-बगाहे लगते रहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने न्याय-व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदही सुनिश्चित करने के लिए और न्यायिक-प्रक्रिया को गतिशील, त्वरित, समयबद्ध और वहनीय बनाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने की पहल की थीक सरकार की यह कोशिश कॉलेजियम व्यवस्था के लाभार्थियों और हिमायतियों को सख्त नागवार लगी और अपनी सुप्रीम शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह देखना सचमुच दिलचस्प होगा कि उच्चतम न्यायालय न सिर्फ उपरोक्त मामले में बल्कि सेल्फ करेक्षण की दिशा में कितनी न्यायिक सक्रियता दिखाता है।

एयरो इंडिया-2021: पूरी दुनिया ने देखा भारत का दमखम

कर्नाटक की राजधानी बैंगलुरू में 3 से 5 फरवरी तक चली एशिया की सबसे बड़ी एयरो-स्पेस और डिफेंस प्रदर्शनी ह्याएयरो इंडिया-2021ल के 13वें संस्करण में भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया को अपना दमखम दिखाया। इसे एशिया की सबसे बड़ी सैन्य विमानन प्रदर्शनी कहा जाता है और इस शो के आयोजन का उद्देश्य लड़ाकू विमानों की क्षमता देखकर सौदा करना है। एयरो-स्पेस में दुनियाभर की कई बड़ी एयरो-स्पेस कम्पनियां भी भारत के साथ मिलकर भारत में ही अपने हथियारों का उत्पादन करने के लिए पहुंची। बैंगलुरू में तीन दिन तक चली सैन्य साजो-सामान और लड़ाकू विमानों की प्रदर्शनी में एयरो-स्पेस क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और देश की लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वह दिन अब दूर नहीं, जब इस क्षेत्र में भारत दुनिया का पहले नंबर का शक्तिशाली देश होगा। मौजूदा समय में अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस के बाद भारतीय सैन्य शक्ति दुनिया में चौथे नंबर पर है। प्रदर्शनी में कुछ साजो-सामान असली रखे गए थे जबकि कुछ के हूबहू मॉडल और इस प्रदर्शनी में 14 देश शामिल हुए थे, जिनमें 338 वर्चुअल एग्जिबिट्स थे। इसमें कुल 603 प्रदर्शक (525 भारत के तथा 78 अन्य देशों के) रखे गए थे। सैकड़ों कम्पनियों ने वर्चुअली अपने हथियारों और दूसरे सैन्य-साजो सामान को प्रदर्शित किया, इसीलिए इसे ह्यार्डब्रीड-मोडल प्रदर्शनी नाम दिया गया था।

तीन दिन तक चले एयरो शो में लाखों लोग हुए शामिल हुए, जिनमें 16 हजार से अधिक व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर जबकि साढ़े चार लाख से ज्यादा वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कोविड-प्रोटोकॉल के कारण इस बार एयरो-शो में आम लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लोगों को प्रदर्शनी वर्चुअल देखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। एयरो इंडियो शो के उद्घाटन के तुरंत बाद रक्षामंत्री और वायुसेना प्रमुख की मौजूदी में वायुसेना और हिन्दुस्तान एयरनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच 83 अतिरिक्त एलसीए तेजस मार्क-1 एयरक्राफ्ट्स का अनुबंध हुआ। एयर शो की शुरूआत में हुए फ्लाइंग-डिस्प्ले में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टरों ने दुनिया को आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का स्पष्ट परिचय दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक एयरो इंडिया शो के जरिये भारत अपने मित्र देशों को हथियारों के लिए नेट-एक्सपोर्टर बनाना चाहता है। एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत के बढ़ते दबदबे का ही असर है कि अब ह्यामेक इन इंडियाल के तहत दुनिया की हर बड़ी कम्पनी भारत में ही हथियारों का निर्माण करना चाहती है।



हर दो साल में एक बार होने वाले एशिया के सबसे बड़े एयरो शो में भारतीय वायुसेना की एयरोबैटिक टीम सूर्योकरण ने उद्घाटन समारोह के अवसर पर प्रदर्शन करने के अलावा अगले दिन भी प्रदर्शन किया और वायुसेना के लड़ाकू विमान रफेल तथा सुखोई ने भी बैंगलुरू के बेलहका एयरबेस पर उद्घाटन समारोह में गरजते हुए उड़ान भरी। एयरो शो के दौरान वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के अलावा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने भी अपना दमखम दिखाया। वायुसेना के सुखोई-30 एयरक्राफ्ट ने दो जागुआर और दो हॉक एयरक्राफ्ट्स के साथ एक फॉर्मेशन में एयरबेस के ऊपर आसमान में प्रदर्शन किया। इसके अलावा वायुसेना के सांग हेलीकॉप्टर तथा एक सूर्योकरण एयरोबैटिक टीम एयरक्राफ्ट ने भी एयर शो के दौरान प्रदर्शन दिखाया। ह्यानेत्रल के आकार में उड़ान भरने वाले विमानों ने डीआरडीओ की पूर्व चेतावनी एवं निगरानी प्रणली की क्षमता दिखाई।

एयरो शो के दौरान आसमान में स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स छाए रहे। एचएएल की ओर से कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टरों ने आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत का दुनिया को अहसास कराया। एयरो शो में जहां रूस की सहायता से भारत में ही तैयार किए जा रहे सुखोई लड़ाकू विमान आसमान में गरजते दिखाई दिए, वहीं ह्यात्मनिर्भर फ्लाइट फॉर्मेशनहूँ के तहत एलसीए-ट्रेनर (लिफ्ट-ट्रेनर), एचटीटी-40, आईजेटी, एडवांस हॉक एमके-132 तथा सिविल डेरनियर (डो-228) के ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स एक विशेष फॉर्मेशन में उड़ान भरते दिखाई दिए। एयरो इंडिया शो में एचएएल के ह्यात्मनिर्भरहूँ विमान दस्ते को पेश करने का उद्देश्य प्रशिक्षण क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना था। डीआरडीओ ने भी अपने 300 से ज्यादा उत्पाद और तकनीकें दुनिया के सामने पेश की। एयरो शो में स्वदेशी लाइट कॉम्पेट एयरक्राफ्ट एलसीए-तेजस, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ह्याथ्वल्ह, लाइट कॉम्पेट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एचटीटी-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट ने भी अपनी जांबाजी के



जौहर दिखाए। अमेरिका के लंबी दूरी के लड़ाकू विमान दस्ते की रीढ़ माने जाने वाले ह्याबी-1बी लांसर एयरक्राफ्ट्स ने भी एस्ट्रोबैटिक टीम में हिस्सा लिया, जिसे अमेरिका के दक्षिण डकोटा के एयरबेस से उड़ान भरकर बैंगलुरू तक आने में 26 घंटे का समय लगा। भारतीय सरजर्मी को छूने वाला यह पहला अमेरिकी लड़ाकू विमान बना।

इस शो के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भारत ह्यात्मनिर्भर भारतहूँ अभियान के तहत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तत्पर है और अपनी रक्षा के लिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। उनके मुताबिक भारत की सापायिक स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना जरूरी है और विश्व ने भारत को अब एक भरोसेमंद रक्षा निवेश गंतव्य के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों हिंद महासागरीय क्षेत्र (आईओआर) के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए भी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का कहना था कि भारत आईओआर के देशों को मिसाइल तथा इलैक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली सहित विभिन्न हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।

देश के आकाश को सुरक्षित रखने और सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए वायुसेना के पायलटों के योगदान और बहादुरी की सराहना करते हुए एयरो इंडिया शो के समापन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शो को अभूतपूर्व सफल करार देते हुए कहा था कि बैंगलुरू में द्विवार्षिक एयर शो वैश्वक स्तर पर रक्षा एवं एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ ही देश को विश्व के लिए विनिर्माण देश के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

आधुनिक खेती ने खाद्य उत्पादन को ही बना दिया जलवायु के लिए खतरा

नेचर में आज प्रकाशित शोध के अनुसार नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जलवायु के लिए इस कदर खतरा बन गए हैं कि इनके चलते पेरिस समझौते के तहत जलवायु से जुड़े लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखते। आज से 111 साल पहले 1909 में जब जर्मन वैज्ञानिक फ्रिट्ज हेबर ने दुनिया को बताया कि नाइट्रोजन और हायड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया बनती है, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने वाले और बेहतर करने वाले नाइट्रोजन उर्वरकों का आधार बनने वाली यह खोज आगे चल के पूरी मानवजाति के लिए एक भारी खतरा बनेगी।

आज, 2020 में विज्ञान हमें बता रहा है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जलवायु के लिए इस कदर खतरा बन गए हैं कि इनके चलते न सिर्फ पेरिस समझौते के तहत जलवायु से जुड़े लक्ष्य पूरे होते नहीं दिखते, बल्कि इन उर्वरकों ने खाद्य उत्पादन तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खाद्य उत्पादन पर जलवायु को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगे तो यह बड़ी विकट परिस्थिति की ओर इशारा करती है। भारत तो बो देश है जो हमेशा से देसी कृषि तकनीकों का समर्थक रहा है लेकिन बाजारवाद के दबाव में आधुनिक कृषि तकनीक और उर्वरक हमें ही खाने को तैयार बैठे दिखते हैं।

दरअसल, नेचर मैगजीन में छ्ये ऑर्बर्न विश्वविद्यालय के ताजा शोध से पता चलता है कि नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन कि वजह से पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को पूरा न होने का खतरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर में भोजन के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता या कंसन्ट्रेशन्स बढ़ रहा है। यह एक ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक प्रभावी है और मानव जीवन की तुलना में वायुमंडल में लंबे समय तक रहती है। यह खोज ऑर्बर्न यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ साइंसेज में एनड्रू कॉनर्जी फेलो और इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड ग्लोबल चेंज रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर हैंकिन टीयान के नेतृत्व में हुए एक अध्ययन का हिस्सा है। ये अध्ययन आज दुनिया की सबसे प्रचलित विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर हैंकिन टीयान ने 14 देशों के 48 अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ को साथ लेकर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव की छत्राध्याय में इसका सह-नेतृत्व किया। अध्ययन का उद्देश्य और शीर्षक था, हैविश्वक नाइट्रस ऑक्साइड स्रोतों का एक व्यापक मात्राकरण और हानिहृ, इस प्रभावकारी ग्रीनहाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड का अभी



तक का सबसे व्यापक मूल्यांकन जो इसके उत्पादन के भी स्रोतों और उससे होने वाले नुकसानों की पूरी जानकारी देता है। टीयान के ऑर्बर्न सहयोगी जिसमें प्रोफेसर शुफेन पान, पोस्टडॉक्टरेल फेलो रोंगिंग जू, हाओ शि, युआनजी याओ और स्नातक छात्र नाइकिंग पैन भी शामिल हैं, ने और 57 वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम ने सह-लेखक के रूप में काम किया। ये अध्ययन, जलवायु परिवर्तन को तेजी से प्रभावित करने वाली एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है: नाइट्रस ऑक्साइड पूर्व-औद्योगिक स्तरों के मुकाबले 20 प्रतिशत तक बढ़ा है इसके अलावा विभिन्न मानव गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन के कारण हाल के दशकों में इसकी वृद्धि में और तेजी आई है। प्रोफेसर हैंकिन टीयान ने कहा, हूँडसकी वृद्धि का सबसे प्रमुख कारक है कृषि। इसके अलावा जानवरों के लिए भोजन और फीड की बढ़ती मांग भी वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को और बढ़ाएगी।

अध्ययन से यह भी जानकारी मिलती है कि वैश्विक नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का है। अध्ययन में पाया गया कि चीन, भारत और अमेरिका में सिंथेटिक उर्वरकों के इस्तेमाल से यहाँ उत्सर्जन सबसे अधिक है, जबकि पशुधन से बनने वाली खाद से होने वाले उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का है। उत्सर्जन की सबसे अधिक विकास दर उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से ब्राजील, चीन और भारत में पाइ गई, जहां फसल उत्पादन और पशुधन की संख्या में वृद्धि हो रही है। अध्ययन का सबसे आश्वर्यजनक परिणाम जिसमें सभी सह-लेखक सहमत थे कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन की वजह से वर्तमान पेरिस जलवायु समझौता या पेरिस अकॉर्ड में निर्धारित किये लक्ष्यों को प्राप्त करना

संभव नहीं है, क्योंकि इसका उत्सर्जन नियमों के अनुरूप नहीं है।

195 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित, इस समझौते का उद्देश्य है कि इक्कीसवीं सदी में वैश्विक तापमान में वृद्धि से होने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना और तापमान को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है।

हालांकि, ऑस्ट्रिया में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस में एक सीनियर रिसर्च स्कॉलर और अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन इनिशिएटिव की पूर्व निदेशक विलफिएद विनीवार्टर कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के अवसर अब भी मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा, यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछले दो दशकों में नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन को सफलतापूर्वक कम किया है।

ग्रीनहाउस गैसों और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और उर्वरक उपयोग को सुधारने के लिए बनाई गई औद्योगिक और कृषि नीतियां प्रभावी साक्षित हुई हैं। फिर भी यूरोप में और साथ ही विश्व स्तर पर और भी प्रयासों की आवश्यकता होगी। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साईटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट साइंस सेंटर के मुख्य वैज्ञानिक और ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के कार्यकारी निदेशक के रूप में अध्ययन के सह-नेता जोसेप कानडेल्ल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि यह शोध महत्वपूर्ण और जरूरी है। वो कहते हैं, यह नया तुलनात्मक विश्वेषण वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग और दुरुपयोग के तरीकों पर पूरी तरह से पुनर्विचार करने कि ओर इशारा करता है और हमें आग्रह करता है कि हम खाने को व्यर्थ न करें और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में और अधिक प्राकृतिक तकनीकों को अपनाएं।

वेलेंटाइन डे, बेगानी शादी में अद्भुतला दीवाना



भारत ने संसार को प्रेम और भ्रातृत्व का सन्देश दिया हमारे यहाँ प्रेम, की वैसी परिभाषा नहीं है जैसी कि पश्चिमी देशों में है। किन्तु आज का तथाकथित एलीट वर्ग पश्चिम से आयी प्रत्येक परंपरा को प्रतिष्ठा की बस्तु (स्टेटस सिम्बल) मानकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं योरप में प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला वेलेंटाइन डे अब वेलेंटाइन वीक बनगया है। किंवदंति है कि रोम का राजा कल्पा डियप विवाह करने की प्रथा के विरुद्ध था यह भी कहा जाता है कि योरप में कुछ सदी पूर्व तक विवाह की परंपरा सामान्य प्रचलन में न थी। वेलेंटाइन चाहते थे कि वासना की स्वेच्छाचरिता को समाप्त कर लोग विवाह करें किन्तु उनके इस अधियान को वहाँ दण्डनीय माना गया परिमाण यह हुआ कि उन्हें मृत्यु दण्ड मिला। जिन युगलों के उन्होंने विवाह कराए वे प्रतिवर्ष उनकी मृत्यु के दिन श्रद्धाजल देने लगे और इस प्रकार वेलेंटाइन डे की परंपरा आरंभ हुई, किन्तु भारत में इसका क्या औचित्य है? यह चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गृहस्थ आश्रम ही समाज की रीढ़ है। भारत में कोई पुत्री अपने पिता या माँ से कहे, पापा यू आर माई वेलेंटाइन तो इसका अर्थ होगा कि पिता जी आप मेरा विवाह करने वाले व्यक्ति हैं, आपका आभार। भारत में तो माता-पिता की इच्छा से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ विवाह मत करो ऐसा कहने वाले लोग भी नहीं हैं फिर इसमें वेलेंटाइन के नाम पर क्या जोड़-घटाएँ यह समझ से परे है। यदि दूसरे मिथक को मान लें जिसके अनुसार वेलेंटाइन किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे उसे लिखे प्रेमपत्र के अंत में तुम्हारा दीवाना था।

यह चिंतन का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गृहस्थ आश्रम ही समाज की रीढ़ है। भारत में कोई पुत्री अपने पिता या माँ से कहे, पापा यू आर माई वेलेंटाइन तो इसका अर्थ होगा कि पिता जी आप मेरा विवाह करने वाले व्यक्ति हैं, आपका आभार। भारत में तो माता-पिता की इच्छा से विवाह करना श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ विवाह मत करो ऐसा कहने वाले लोग भी नहीं हैं फिर इसमें वेलेंटाइन के नाम पर क्या जोड़-घटाएँ यह समझ से परे है। यदि दूसरे मिथक को मान लें जिसके अनुसार वेलेंटाइन किसी राजकुमारी से प्रेम करते थे उसे लिखे प्रेमपत्र के अंत में तुम्हारा दीवाना था।

कि उनकी याद में प्रेम दिवस या प्रेम या सप्ताह नहीं मनाए जाते? हमारे यहाँ प्रेम दिवानी मीरा को पूजा जाता है किन्तु ध्यान रहे भारतीय समाज प्रेम के वासना रहित स्वरूप या कहें सात्त्विक प्रेम का ही अभिनन्दन करता है। वासना जनित प्रेम या प्रेम के नाम पर होने वाली कथित काम-क्रीडाओं को यहाँ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता।

आधुनिक वेलेंटाइन वीक के जनक हैं यूरोपीय बाजार उपहार बनाने-बेचने वाली कंपनियों ने जब यह देखा कि क्रिसमस के बाद वेलेंटाइन डे के आस-पास भी ग्रीटिंग कार्डों की डिमांड बढ़ जाती है, तो उन्होंने इसे प्रमोट करना आरंभ किया, वेलेंटाइन को दी जाने

वाली श्रद्धांजलियाँ धोर-धोरे उल्लास और प्रेम के उत्सव में बदल दी गई। प्रार्थनाएँ प्रपोज डे में रूपांतरित हो गई और देखते-ही-देखते यह उत्सव वेलेंटाइन वीक बना गया। अब पूरे सप्ताह बाजार में रैनकर रहे, बिक्री बढ़े इसके लिए एक दिन रोज डे मनाकर गुलाब बेचे गए और करोड़ों अरबों का व्यापार खड़ा कर लिया गया फिर चॉकलेट वाले इसमें कूद पड़े, एक दिन में कई महीने के बावरा चॉकलेट की बिक्री होने लगी। बड़े-बड़े आकर्षक विज्ञापन गढ़े गए विवाहित लोगों के घरों में प्रेमिका की भाँति पत्नी को चॉकलेट खिलाई जाने लगीं। अब फेसबुक आदि सोशल मीडिया ने इसे घर-घर में पहुंचा दिया एक दिन टैडी डे बना दिया, इतने सब के बाद चौदह फरबारी को क्या करें यह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यह दिन तो शोक का दिन है तो इस दिन या तो वेलेंटाइन को श्रद्धाजल अर्पित करो या एक सप्ताह से चले आ रहे प्रेम प्रसंग को विवाह में परिणत करो किन्तु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो होता है वह बहुत ही निंदनीय है, युवक-युवतियाँ और अधिकांश नाबालिंग बच्चे दिन भर पार्क, पर्यटन स्थलों पर भाँड़ी हरकते या कहें कि अश्लील व अमर्यादित आचरण करते दीखते हैं। सज्जन लोग आज के दिन सार्वजनिक स्थानों पर सपरिवार जाने से भी बचते हैं क्योंकि ऐसे अशोभनीय दृश्य कोई भी भला आदमी अपने बच्चों के साथ देखना पसंद नहीं करता। कई स्थानों पर पुलिस दिन भर इन युगलों को भगाती दीखती है तो कई स्थानों पर सामाजिक कार्यक्राताओं को इन्हें खदेड़ना पड़ता है। बाजारबाद ने प्रेम के नाम पर जो वितंडा खड़ा किया है वह बहुत ही भयानक है। आज नई पीढ़ी के समक्ष प्रबोधन की आवश्यकता है कि प्रेम का वेलेंटाइन रूप हमारे सामाजिक ढाँचे के अनुरूप नहीं है।

माता पिता की सेवा से आशीर्वाद एवं जीवन में सुख मिलता है

मनुष्य एक मननशील प्राणी है। इसका आत्मा ज्ञान व कर्म करने की शक्ति से युक्त होता है। मनुष्य को ज्ञान अपने माता, पिता व आचार्यों से मिलता है। माता-पिता सन्तानों को श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा देते हैं। आचार्य भी वेद व ऋषियों के ग्रन्थों सहित आधुनिक विषयों का ज्ञान अपने अपने शिष्य व विद्यार्थियों को करते हैं। ऐसा करके ही मनुष्य ज्ञानवान होता है। जिस मनुष्य के माता पिता धार्मिक विद्वान होते हैं उतना ही अधिक उन सन्तानों का उपकार होता है। धर्म का अर्थ मनुष्य जीवन में धारण करने योग्य श्रेष्ठ गुणों व कर्तव्यों का धारण व आचरण करना होता है। धार्मिक माता पिता का अर्थ भी सत्य ज्ञान से युक्त तथा श्रेष्ठ आचार करने वाले माता पिता होते हैं। ऐसे माता पिता की सन्तानें उत्तम होती हैं। सन्तानों को माता पिता से सत्याचरण सहित श्रेष्ठ आचरण की शिक्षा मिलती है। यदि मनुष्य को श्रेष्ठ व उत्तम आचरण वाले वेदों के ज्ञानी आचार्य मिल जाते हैं तो मनुष्य का सर्वविध कल्याण होता है। धार्मिक माता पिता तथा आचार्यों से पालन पोषण व विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। वह अपने कर्तव्यों को भली भांति जानता व समझता है तथा उनके पालन में वह तत्पर रहता है। अपने सभी कर्तव्य का पालन करना सभी मनुष्यों का धर्म होता है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते वह देश व समाज में निन्दित होते हैं। सत्य के विरुद्ध व्यवहार करना सभी के लिए अनुचित होता है। मनुष्य को लोभ में फँस कर कभी भी कोई अकर्तव्य व अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये। मनुष्य को अपने किए हुए प्रत्येक कर्म का फल ईश्वर द्वारा सम्यान्तर पर मिलता है। मनुष्य जीवन में ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता जिसे मनुष्य करे और उसे उसका फल न मिले। कर्म फल सिद्धान्त का आवश्यक मन्त्र है हाव्यवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं अर्थात् मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म का फल सुख व दुःख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में हमें जो सुख व दुःख मिलते हैं, जिसका कारण हमें समझ में नहीं आता, वह हमारे अतीत व पूर्वजन्म में किये कर्म ही हुआ करते हैं। अतः मनुष्य को अशुभ कर्मों का त्याग तथा अपने कर्तव्य कर्मों का आत्मस्व व प्रमाद से रहित होकर सेवन व पालन करना चाहिये। ऐसा आचरण ही हम विद्वानों व महापुरुषों के जीवन में देखते हैं।

सभी सन्तानों को अपने माता व पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिये। माता पिता की सेवा व पूजा करना वैदिक धर्म एवं संस्कृति का मुख्य सिद्धान्त है। वैदिक परम्परा में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मनुष्य के लिए संसार में सबसे अधिक सत्कार करने योग्य अपनी माता ही होती है। माता को देवी कहा जाता है। देवी या देवता



दिव्य गुणों से युक्त तथा दूसरों पर उपकार करने वाले स्त्री व पुरुषों को कहते हैं। माता, पिता व आचार्य चेतन देव होते हैं। पृथिवी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश आदि जड़ देवता होते हैं। इन जड़ पदार्थों में भी अनेक दिव्य गुण हैं जिनका लाभ व उपकार हम अपने जीवन में इनसे लेते हैं। इसलिये इन पदार्थों के प्रति भी हमारा कृतज्ञता व श्रद्धा का भाव होना चाहिये। माता व पिता संसार के वह दो महान व्यक्तित्व होते हैं जिनसे सन्तान का जन्म होता है। माता पिता को गर्भ धारण व प्रसव में अनेक कष्ट व दुःख होते हैं। दस महीने तक निरन्तर सन्तान को गर्भ में धारण करना होता है। इससे माता को अकथ कष्ट होता है। यह कष्ट सहन करना कोई आसान काम नहीं होता। प्रसव में भी तीव्र पीड़ा होती है। पुराने समय में तो कई माताओं की प्रसव पीड़ा से मृत्यु तक हो जाती थी। सन्तान के जन्म के बाद सन्तान की रक्षा व उसके पालन में भी माता व पिता दोनों को ही अनेक कष्ट व दुःख उठाने पड़ते हैं।

सभी माता-पिता अपनी सन्तान को शिक्षित करते हैं। उसे स्वयं पढ़ाते व विद्यालय में भेजकर भारी व्यय उठाते हैं। उसके सुखों व भविष्य के लिये चिन्तित रहते हैं। अपने बच्चों को आश्रय व अच्छा निवास देते हैं और अपने से भी अधिक अपनी सन्तान का ध्यान रखते हैं। बड़ा होने पर सन्तान का विवाह आदि कर अपने कर्तव्य से निवृत होते हैं। सन्तान बड़ी होती है तो माता-पिता भी बृद्धावस्था के द्वारा परहुंच जाते हैं। इस अवस्था में उनको अपनी सन्तानों से अच्छे मधुर व्यवहार सहित सेवा व पोषण की आवश्यकता होती है। बृद्धावस्था में वह कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें कुछ रोग भी आ घेरते हैं। ऐसे समय में माता पिता को आश्रय सहित उनको भोजन, सत्र, आषाढ़ि, चिकित्सा, सेवा व सन्तानों के मधुर व्यवहार की आवश्यकता होती है। अतः सन्तान को अपने इन सभी कर्तव्यों की पूर्ति श्रद्धा एवं निष्ठा से अवश्य ही करनी चाहिये। जो सन्तान ऐसा करते हैं वह यशस्वी एवं प्रशंसित होते हैं। न केवल माता-पिता का अपितु ईश्वर का आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होता है। माता-पिता की सेवा सत्कर्त्व होने से सन्तानों को इसका ताल्कालिक एवं प्रारब्ध कर्मों के रूप

में परजन्म में भी लाभ प्राप्त होता है। वह जन्म जन्मान्तरों में माता पिता की आत्माओं से निकले आशीर्वादात्मक वचनों से उन्नति करते हुए सुखों को प्राप्त होते हैं। अतः सभी सन्तानों को अपने माता-पिताओं के प्रति कर्तव्य पालन पर ध्यान देना चाहिये और प्रतिदिन उनकी सेवा करते हुए उन्हें किसी प्रकार का किंचित भी कष्ट नहीं होने देना चाहिये। यही हमारे वेद आदि शास्त्रों का उपदेश है।

अनादि, नित्य तथा सनातन वैदिक धर्म में सभी मनुष्यों के पांच कर्तव्य होते हैं जिनमें तीसरा कर्तव्य व धर्म पितृयज्ञ करना होता है। यह पितृयज्ञ माता, पिता को सत्कर्णीय चेतन देव मानकर उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा से उनको सन्तुष्ट करना होता है। इतिहास में भी माता पिता की सेवा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माता-पिता के प्रति आदर बुद्धि रखते थे। राज्य के अधिकारी होने पर भी वह अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए बिना पिता द्वारा आज्ञा दिए ही 14 वर्ष के लिए वन में चल गये थे। उन्होंने अपनी सभी माताओं एवं पिता का आदर्श मनुष्य के रूप में पालन किया था। आज अनेक युग व्यतीत हो जाने पर भी उनका यश पूरे विश्व में व्याप्त है। श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की आदर्श सेवा की। आज भी हम समाज में माता पिता की श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक सेवा करने वाले तथा न करने वाले दोनों प्रकार की सन्तानों को देखते हैं। हमें वैदिक परम्पराओं का पालन करते हुए नित्य प्रति अपने माता पिता की व्रतपूर्वक श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिये। ऐसा करके ही हमारा पितृयज्ञ करना सफल होगा। जो सन्तानें अपने माता-पिता की सेवा नहीं करती वरन् उनको अपने व्यवहार व आचरणों से अनुचित कष्ट पहुंचाती हैं वह निन्दनीय होती है। वह सामाजिक नियमों से तो बच सकती हैं परन्तु परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था से बच नहीं सकती। उनको भी भविष्य में बृद्ध होना है। उनको भी अपनी सन्तानों के प्रेम, सहयोग एवं सेवा की आवश्यकता होगी। यदि उन्होंने अपने माता-पिता की सेवा नहीं की होगी तो उनको शिकायत करने का अवसर नहीं मिलेगा।

जो मनुष्य किसी से कुछ भी उपकार लेता है और उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होता वह कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्न सबसे बड़ा पाप होता है। हमें अपने जीवन व कर्मों पर ध्यान देना चाहिये और कृतघ्न कदापि नहीं होना चाहिये। हमें परमात्मा द्वारा प्रवृत्त वैदिक धर्म मर्यादा के अनुसार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना उपासना करने से सहित अपने माता, पिता, वृद्ध परिपालिक जनों तथा आचार्यों की सेवा करनी चाहिये और जीवन में यथाशक्ति परोपकार व दान आदि के कार्य करने से चाहिये। ऐसा करके ही हमारा वर्तमान व भविष्य का जीवन तथा परजन्म उन्नत व सुखदायक होगे।

ओटीटी प्लेटफार्म के द्वारा फैलती अश्लीलता पर सरकार लगाए जल्द अंकुश!

लॉकडाउन के दौरान जब देश में सभी लोग अपने घरों में एक तरह से कैद थे, तो उस समय सबसे सुलभता से उपलब्ध मनोरंजन के सशक्त प्लेटफार्म के तौर पर ओटीटी प्लेटफार्म देश में उभरा था, देश में इस प्लेटफार्म का चलन बहुत तेजी से बढ़ा था, सिनेमा हाल बंद होने की वजह से अचानक बड़े-बड़े धुरंधर ओटीटी प्लेटफार्म पर आ गये थे, आज बहुत बड़ी संख्या में हर उम्र के दर्शक किसी ना किसी देशी या विदेशी ओटीटी प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार के मदेनजर आयेदिन भारतीय दर्शकों के लिए नयी फिल्म या वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती है। उसी कड़ी में देश में ओटीटी प्लेटफार्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 15 जनवरी शुक्रवार को सैफ अली खान व डिंपल कपड़िया की वेब सीरीज ह्यतांडवल्ह रिलीज हुई है, जिसके बाद से ही यह सीरीज जबरदस्त विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस वेब सीरीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों की बड़ी मुहिम चल रही है, देश में बहुत सारी जगह तो इस सीरीज से जुड़े हुए कछ लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, कुछ आम दर्शक तो वेब सीरीज के निर्माताओं पर सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और भगवान राम का अपमान करने का दुस्साहस किया है, लोगों का कहना है कि जानबूझकर सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था से खेलने का कार्य किया गया है, दर्शकों का आरोप है कि इस सीरीज में प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धूमिल करने का दुस्साहस किया गया है, साथ-साथ जातिगत व धार्मिक विवादित टिप्पणी करके देश के आम लोगों



की आस्था व भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली तांडव वेब सीरीज पर तकाल प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिसको लेकर के देश में जगह-जगह से लोगों की मांग कर रहे हैं। हालांकि ओटीटी प्लेटफार्म पर यह कोई पहली विवादित वेब सीरीज या फिल्म नहीं है इसके पहले भी कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज विभिन्न कम्पनियों के ओटीटी प्लेटफार्म पर आ चुकी हैं, पूर्व में भी इस तरह से ही मंदिर में राम धुन पर किसिंग सीन फिल्मा कर सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं से खेलने का कार्य एक ओटीटी प्लेटफार्म के द्वारा किया गया था, उस समय भी खूब विवाद हुआ था।

आवश्यकता

चर्चित बिहार मासिक हिन्दी पत्रिका का



भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, सासाराम, बेगूसराय, जमुई रोहतास, जहानाबाद, समस्तीपुर, रोसड़ा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार किशनगंज, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, छपरा, सिवान में जिला संवाददाता एवं विज्ञापन प्रतिनिधि की आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति अविलंब संपर्क करें।

संपादक, अभिजीत कुमार

गिरिराज सदन, काली मंदिर रोड संजय गांधी नगर हनुमान नगर कंकड़बाग पटना, 20

सम्पर्क : 9431006107, 9999357107

Coming Soon

आवश्यकता है पूरे देश में व्यूरो प्रमुख, विज्ञापन प्रतिनिधि की, इच्छुक व्यक्ति अविलंब संपर्क करें।

CB News

24x7

खबर हमारी, फैसला आपका

www.cbnews24x7.com

9431006107, 9999357107, 8287266244

